● वर्ष-3
● अंक-96
रायपुर, गुरुवार
30 नवंबर 2023
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› इन आसान तरीकों से आप भी....

छत्तीसगढ़ में परिणाम देख चौक जाएंगे पंडित, ओममाथुर का बड़ा बयान

शपथ ग्रहण की तैयारी में जुटी भाजपा

रायपुर। छत्तीसगढ़ भाजपा के चुनाव प्रभारी ओम माथुर ने ट्वीट किया कि छत्तीसगढ़ में भी हम राजनीतिक पंडितों को चौंकाने वाले हैं। ओम माथुर ने ट्वीट किया कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी शानदार बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, छत्तीसगढ़ में भी हम राजनीतिक पंडितों को चौंकाने वाले हैं। वहीं भाजपा को लेकर सुशील आनंद द्वारा दिए गए बयान और बीजेपी के बड़े नेताओ के दौरे पर बीजेपी प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी ने कहा कि काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती, इस बार जनता उनके भुलावे में नहीं आएगी। 3 दिसम्बर को नतीजे आने के बाद शपथ ग्रहण की तैयारी के लिए मनसुख मांडविया और ओम माथुर आ रहे है, वो विधायकों से चर्चा करेंगे। कांग्रेस जीत के मुगालते में है। मतगणना और स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर हुई शिकायत पर श्रीचंद सुंदरानी ने कहा- भाजपा कभी भी मतगणना में गड़बड़ी नहीं करती। भाजपा ने चुनाव अधिकारियों से कई शिकायतें की लेकिन वे भूपेश बघेल सरकार के पिट्ठू बनकर काम कर रहें, इसलिए कार्रवाई नहीं की। धान और समर्थन मूल्य को लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनाने के कांग्रेस के बयान पर सुंदरानी ने कहा- कांग्रेस मुद्दा ही बस बनाती है। कांग्रेस उनके हाथ में कुछ नहीं आएगा, वो मुद्दा बनाने वाली पार्टी ही बनकर रह जाएगी।

कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला के बयान पर भाजपा प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी ने कहा कि नियमितीकरण का वादा कांग्रेस सरकार ने किया था, 5 साल तक कर्मचारियों के साथ धोखा हुआ, अब भाजपा की सरकार आ रही है, कर्मचारियों को घबराने की जरूरत नहीं है, नियमितीकरण किया जाएगा।

2018 में फेल हुआ था एग्जिट पोल

नई दिल्ली । 7 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए। वहीं, तेलंगाना में मतदाता गुरुवार (30 नवंबर) को वोटिंग करेंगे। सभी राज्यों के नतीजे तो 3 दिसंबर को पता चलेंगे, लेकिन 30 नवंबर की शाम को अलग-अलग मीडिया चैनलों और सर्वे एजेंसियों की तरफ से एग्जिट पोल जारी किए जाएंगे। दरअसल एग्जिट पोल एक तरह का चुनावी सर्वे होता है। मतदान वाले दिन जब मतदाता वोट देकर पोलिंग बूथ से बाहर निकलता है तो वहां अलग-अलग सर्वे एजेंसी और न्यूज चैनल के लोग मौजूद होते हैं। इन आंकड़ों को जुटाकर और उनके उत्तर के हिसाब से अंदाजा लगाया जाता है कि पब्लिक का मूड किस ओर है?

छत्तीसगढ़ में अधिकतर एग्जिट पोल सर्वे ने रमन सिंह की अगुवाई में फिर से भाजपा सरकार बनने का अनुमान जताया था। टाइम्स नाउ-सीएनएक्स ने भाजपा को 46 सीटें, कांग्रेस को 35 सीटें, बसपा को 7 सीटें और अन्य को 2 सीटें दी थीं।

न्यूज 24- पेस मीडिया के अनुमान में भाजपा के खाते में 38 सीटें, कांग्रेस को 48 सीटें, बसपा और जनता कांग्रेस को 4 सीटें और अन्य को 2 सीटें मिलनी थीं। एबीपी- सीएसडीएस ने अपने एग्जिट पोल में भाजपा को 39 सीटें, कांग्रेस को 46 सीटें और अन्य को 05 सीटें दी थीं।

आजतक- एक्सिस माय इंडिया के मुताबिक, नतीजों में कांग्रेस को 55-65 सीटें, भाजपा को 21-31 सीटें और अन्य को 4-8 सीटें मिलनी थीं। जन की बात एजेंसी ने अपने एग्जिट पोल में भाजपा को 44 सीटें, कांग्रेस को 40 सीटें और अन्य को 6 सीटें दी थीं।

न्यूज नेशन के अनुसार भाजपा को राज्य में 38-42 सीटें, कांग्रेस को 40-44 सीटें, जेसीसी को +4-8 सीटें और अन्य को 0-4 मिलनी थीं।

टाइम्स नाउ- सीएनएक्स

भाजपा	6 सीटें
कांग्रेस	35 सीटें
बसपा	7 सीटें
अन्य	2 सीटें

न्यूज 24- पेस मीडिया

भाजपा	38 सीटें
कांग्रेस	48 सीटें
बसपा-जनता कांग्रेस	4सीटें
अन्य	2 सीटें

एबीपी- सीएसडीएस

भाजपा	39 सीटें
कांग्रेस	46 सीटें
अन्य	5 सीटें

आजतक- एक्सिस माय इंडिया

कांग्रेस	55-65 सीटें
भाजपा	21-31 सीटें
अन्य	4-8 सीटें

जन की बात एजेंसी

भाजपा	44 सीटें
कांग्रेस	40 सीटें
अन्य	सीटें

न्यूज नेशन

भाजपा	38-42 सीटें
कांग्रेस	40-44 सीटें
जेसीसी	+4-8 सीटें
अन्य	0-4 सीटें

जब चुनाव नतीजे आए तो 90 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस को 68 और भाजपा को 15 सीटें मिलीं। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) ने पांच सीटें जीते थीं और दो सीटें बसपा के खाते में गई थीं।

सुरंग से रेस्क्यू किए गए मजदूरों को पीएम मोदी ने किया फोन, जाना हालचाल

उत्तरकाशी की सिल्कयारा सुरंग में फंसे सभी 41 मजदूरों को 17 दिन की मशक्कत के बाद मंगलवार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. इन मजदूरों को सुरंग से बाहर निकालने के बाद एंबुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका हेल्थ चेकअप किया गया. इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन मजदूरों से फोन पर बात कर उनका हालचाल जाना.

2024 की तैयारी में जुटी भाजपा, मोदी ने मंत्रियों को दिए खास निर्देश

नई दिल्ली। 2024 के चुनाव नजदीक आ रहे है। सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारी में लगे हुए है। इसी कड़ी में सत्तारूढ़ भाजपा भी 2024 की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की। इस दौरान मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों से केंद्रीय योजनाओं को उजागर करने के उद्देश्य से एक मेगा आउटरीच अभियान, विकसित भारत संकल्प यात्रा में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए कहा है। सूत्रों के मुताबिक, मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आउटरीच कार्यक्रम विकसित भारत (विकसित भारत) बनाने का हिस्सा है। उन्होंने मंत्रियों से इस बात का प्रचार-प्रसार करने पर ध्यान केंद्रित करने को कहा कि कैसे समाज के विभिन्न वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए कई योजनाएं तैयार की गई हैं। जानकारी के मुताबिक 2.55 लाख ग्राम पंचायतों और शहरी क्षेत्रों में लगभग 18,000 स्थानों पर सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए वाहनों का उपयोग किया जा रहा है। आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) वैन को विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, ग्रामीण आवास योजना, उज्ज्वला योजना और पीएम स्वनिधि योजना के साथ ब्रांड किया जा रहा है। यात्रा के हिस्से के रूप में, देश के सभी शहरों और कस्बों में 2.55 लाख ग्राम पंचायतों और समूहों को कवर करने के लिए 2,500 से अधिक मोबाइल प्रदर्शन वैन और 200 से अधिक मोबाइल थिएटर वैन को सेवा में लगाया जाएगा।

आउटरीच कार्यक्रम की संकल्पना संपूर्ण-सरकारी दृष्टिकोण पर की गई है, जिसमें कृषि मंत्रालय ग्रामीण अभियान के लिए नोडल मंत्रालय है और सूचना और प्रसारण मंत्रालय शहरी अभियान का नेतृत्व कर रहा है। प्रधानमंत्री ने 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से यात्रा की शुरुआत की थी। उन्होंने यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर विशेष रूप से डिजाइन की गई पांच आईईसी वैन को हरी झंडी दिखाई थी। इसी तरह की वैन को देश भर के अन्य जिलों से भी रवाना किया गया, जहां बड़ी संख्या में आदिवासी आबादी है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में केंद्र के प्रमुख कार्यक्रमों के लाभार्थियों तक पहुंचने का अभियान 25 जनवरी, 2024 को समाप्त होगा।

प्रमुख समाचार

तेलंगाना में चुनाव की तैयारियां पूरी, आज मतदान

हैदराबाद। युवा राज्य तेलंगाना में गुरुवार को मतदान होगा। मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव कांग्रेस से कड़ी टक्कर के बीच तीसरे कार्यकाल की उम्मीद कर रहे हैं। भारत संघ का सबसे युवा राज्य उत्तर पश्चिम आंध्र प्रदेश से अलग होकर देश का 29वां राज्य बना और तब से इस पर बीआरएस का शासन है। भारत राष्ट्र समिति का मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा से है। दोनों दल राज्य में अपनी पूरी ताकत लगा रही हैं। 119 सदस्यीय राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राज्य भर में 35,655 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां कुल पंजीकृत 3.26 करोड़ मतदाता हैं।

सुचारू और व्यवस्थित मतदान सुनिश्चित करने के लिए अर्धसैनिक बलों और 35,500 होम गार्ड सहित 45,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को तैनात करके कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चुनाव के दौरान अनियमितताओं की जांच के लिए करीब 1800 दस्ते भी तैनात किये गये हैं. मतदान समाप्ति तक शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गयी है।

प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने पहुंचे मोहन भागवत

नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख डॉ. मोहन भागवत वृंदावन गए और यहां उन्होंने प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन किए है। प्रेमानंदजी महाराज और मोहन भागवत के बीच मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। प्रेमानंदजी महाराज राधारानी की भक्ति को लेकर सोशल मीडिया पर काफी फेमस है। इसी बीच मोहन भागवत से भेंट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इसमें दिख रहा है कि प्रेमानंदजी महाराज के आश्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे है। मोहन भागवत के आश्रम में पहुंचने के बाद आचार्य मोहन भागवत का प्रेमानंदजी महाराज से भेंट करवाते है। इसके बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत सम्मान करने के लिए महाराज जी को पीला दुपट्टा उढ़ाते है। दोनों के बीच ये भेंट पूर्ण रूप से आध्यात्मिक थी। इस भेंट के दौरान मोहन भागवत ने कहा कि मैंने वीडियो में आपकी बातें सुनी है। मुझे लगा दर्शन कर लेना चाहिए। चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, ऐसे लोग कम ही दिखते है। इसके बाद प्रेमानंद जी महाराज भी मोहन भागवत से बात करते हुए दिखते है।

क्रिमिनल लॉ को बदलने की जल्दबाजी न करें-ममता

कोलकाता. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नए आपराधिक-दंड कानूनों पर जल्दबाजी नहीं करने की अपील की. उन्होंने हितधारकों के बीच आम सहमति बनाने का आग्रह किया. अमित शाह को लिखी चिट्ठी में ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया कि इसमें आमूल-चूल परिवर्तन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि मौजूदा आपराधिक-दंड कानूनों का राजनीति पर प्रभाव पड़ेगा. अमित शाह बुधवार को बंगाल दौरे पर थे. केंद्र सरकार औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को रिप्लेस करने के लिए तीन विधेयक लेकर आई है. नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम हैं. इनके संसद के शीतकालीन सत्र में पारित होने की उम्मीद है. ममता बनर्जी ने कहा, मेरा दृढ़ विश्वास है कि ये बहुत महत्वपूर्ण कानून है, जो हमारे दंड-आपराधिक न्यायशास्त्र का आधार बनते हैं.

सीएए: इसे कोई नहीं रोक सकता, हम लागू करेंगे: शाह

कोलकाता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को घोषणा की कि नरेंद्र मोदी सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) लागू करेगी और इसे कोई नहीं रोक सकता। पार्टी के लोकसभा अभियान की शुरुआत करने के लिए कोलकाता में एक रैली को संबोधित करते हुए शाह ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य में घुसपैठ रोकने में असमर्थ हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में घुसपैठियों को वोटर और आधार कार्ड खुलेआम और अवैध तरीके से बांटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस राज्य में इतनी घुसपैठ होती है, क्या वहां विकास होगा?.. इसलिए ममता बनर्जी सीएए का विरोध कर रही हैं... लेकिन मैं कहूंगा कि सीएए देश का कानून है, और इसे कोई नहीं रोक सकता... हम इसे लागू करेंगे। 2020 में संसद द्वारा पारित, सीएए 2015 से पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत में प्रवेश करने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करता है। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) जोर देकर कहती है कि सीएए असंवैधानिक है.

क्रिटिकल मिनरल्स की पहली बार नीलामी कर रही सरकार

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने लिथियम, कोबाल्ट और टाइटेनियम जैसे खनिजों के संभावित सप्लाई चेन की कमजोरियों को दूर करने के लिए क्रिटिकल मिनरल्स की नीलामी का पहला दौर बुधवार (29 नवंबर) से शुरू किया है. सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बताया कि कुल 20 ब्लॉक नीलामी के लिए रखे गए हैं. उनकी कंबाइंड वैल्यू 45000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है. इस नीलामी में लिथियम और ग्रेफाइट जैसे मिनरल्स के लिए बोली मंगाई गई है.

महत्वपूर्ण और रणनीतिक लिहाज से खास खनिजों के ये 20 ब्लॉक उत्तर प्रदेश, गुजरात, झारखंड, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और जम्मू-कश्मीर में स्थित हैं. उनमें से 16 के लिए के लिए कंपोजिट लाइसेंस (समग्र लाइसेंस) जारी किए जाएंगे. बाकी 4 ब्लॉक के लिए माइनिंग लाइसेंस दिए जाएंगे. कंपोजिट लाइसेंस के तहत एक्सप्लोरेशन यानी अन्वेषण की परमिशन है.

ब्लॉक की नीलामी में बोली लगाने वाले लोगों का सिलेक्शन उनके गिए गए रॉयल्टी रेट उच्चतम

बदलाव के वक्त यह व्यापक सोच जरूरी

नए कानून में कुछ 'नया' नहीं : मौजूदा समय, हालात में आपराधिक कानून कैसे हों?

पी. चिदंबरम

भारतीय दंड संहिता, 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 हमारे यहां आपराधिक न्याय प्रणाली के तीन स्तंभ हैं। भारतीय दंड संहिता के प्रणेता थॉमस बैबिंग्टन मैकाले थे, जिन्होंने प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता की थी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लेखक सर जेम्स फिट्जेम्स स्टीफन थे। ऐसे ही वर्ष 1973 में नया कानून पारित कर 1898 की दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) को निरस्त कर दिया गया था।

देश भर की सैकड़ों अदालतों में रोज इन तीनों कानूनों का इस्तेमाल होता है। हजारों जज और 1,50,000 से अधिक वकील (जिनमें से ज्यादातर फौजदारी मामलों से जुड़े होते हैं) लगभग रोज ही इन तीन कानूनों से गुजरते हैं। हर जज या वकील यह जानता है कि आईपीसी की धारा 302 हत्या के मामले में लगती है। वे जानते हैं कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के तहत किसी पुलिस अधिकारी के सामने दिए गए बयान से अदालत में आरोपी के खिलाफ अपराध तय नहीं होते। वे यह भी जानते हैं कि सीआरपीसी की धारा 437, 438 और 439 में अग्रिम जमानत और जमानत देने के प्रावधान हैं। इन तीनों कानूनों में ऐसे अनेक प्रावधान हैं, जिनके बारे में जजों और वकीलों को गहराई से जानकारी है।

कानूनों में सुधार करना अच्छा विचार है, लेकिन सुधार का मतलब यह नहीं है कि मौजूदा प्रावधानों को ही दोबारा व्यवस्थित कर दिया जाए या उनकी फिर से क्रम दिया जाए। बदलाव करते हुए यह व्यापक सोच हमारे सामने होनी चाहिए कि मौजूदा समय और परिस्थिति में आपराधिक कानून कैसा होना चाहिए। निश्चित रूप से कानून को बदले हुए जीवन मूल्यों, आदर्शों, आचार-विचार और आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। आधुनिक अपराध विज्ञान, आपराधिक न्याय शास्त्र तथा सजा व जेलों से जुड़े आधुनिक अध्ययनों के जरूरी हिस्से नए कानून में दिखने ही चाहिए। लेकिन इन तीन विधेयकों में हम क्या पाते हैं? कानून के क्षेत्र के अनेक विद्वानों ने इन तीन विधेयकों की गंभीरता से जांच की है। हम यह पाते हैं कि भारतीय दंड संहिता के 90-95 फीसदी प्रावधान उठाकर नए मसौदे में जोड़ दिए हैं। आईपीसी के 26 में से 18 अध्याय (तीन अध्यायों में सिर्फ एक-एक धाराएं ही थीं) नए विधेयक में ज्यों के त्यों रख दिए गए हैं। स्थायी समिति की रिपोर्ट में भी यह स्वीकारा गया है कि विधेयक में आईपीसी की 511 धाराओं में से 24 को हटा दिया गया है और 22 धाराएं जोड़ी गई हैं-बाकी को जस का तस रखा गया है, हालांकि उन्हें दोबारा व्यवस्थित किया गया है और उनके क्रम बदले गए हैं। जबकि इन बदलावों को आईपीसी में संशोधन करके बहुत आसानी से लागू किया जा सकता था। साक्ष्य अधिनियम और सीआरपीसी में भी यही कहानी दोहराई गई। साक्ष्य अधिनियम की सभी 170 धाराओं को नए विधेयक में जोड़ा गया है। ऐसे ही, सीआरपीसी का 95 फीसदी हिस्सा कट-पेस्ट है। जाहिर है, यह पूरी कवायद श्रम, समय और संसाधन की बर्बादी थी। यही नहीं, विधेयक के पारित होने पर कई अनपेक्षित परिणाम होंगे। यह कोई छोटी परेशानी नहीं है कि हजारों जजों, वकीलों, पुलिस अधिकारियों, कानून के छात्रों-यहां तक कि आम नागरिकों को भी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उन्हें कानूनों की फिर से जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। जहां तक विधेयकों की विषय-वस्तुओं का सवाल है, तो इनमें कुछ अच्छी चीजें हैं, जिनके बारे में सरकार संसद में बताएगी, लेकिन मैं इन विधेयकों के उन बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिनसे सवाल उठते हैं। उनमें से महत्वपूर्ण ये हैं-

प्रतिगामी प्रावधान- मृत्युदंड की सजा को खत्म किए जाने की सार्वभौमिक मांग के बावजूद इसे बनाए रखा गया है। बीते छह वर्षों में शीर्ष अदालत ने सिर्फ सात मामलों में मौत की सजा सुनाई है। किसी भी व्यक्ति को सुधार का मौका दिए जाने के नाम पर बगैर जमानत आजीवन कारावास में रखना कहीं ज्यादा सख्त दंड है।

व्यभिचार को, जो पति और पत्नी के बीच का मामला माना जाता है, फिर से अपराध की श्रेणी में लाया गया है। इसके आधार पर, पीड़ित पति या पत्नी तलाक के लिए मुकदमा कर सकते हैं। सरकार को उनकी जिंदगी में हस्तक्षेप करने का कोई हक नहीं है। इससे भी बुरा यह है कि आईपीसी की धारा 497, जिसे शीर्ष अदालत ने रद्द कर दिया था, उसे लिंग के प्रति तटस्थता रखते हुए वापस लाया गया है। बगैर कारण बताए, मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजाओं को कम करने या बदलने की कार्यपालिका की शक्ति संविधान के अनुच्छेद-14 का उल्लंघन है। एकांत कारावास एक क्रूर और असामान्य सजा है।

कुछ मामलों में अदालत की कार्यवाहियों की मीडिया द्वारा होने वाली रिपोर्टिंग को विधायिका द्वारा रोका जाना असंवैधानिक है। आतंकवाद से जुड़े मामलों को गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत अच्छी तरह से देखा जाता है। इन्हें नई दंड संहिता के तहत लाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा, सहायक सत्र न्यायाधीश के पद को खत्म करना भी सही नहीं है, क्योंकि, इससे सत्र न्यायाधीश पर बोझ बढ़ जाए। इस व्यवस्था में पहली अपील उच्च न्यायालय में होगी, जिससे उच्च न्यायालयों पर भी बोझ बढ़ेगा।

हथकड़ी लगाने की अनुमति केवल तभी देनी चाहिए, जब हिरासत में रखा गया व्यक्ति हिंसक हो या उसके भागने की आशंका हो। जिस मजिस्ट्रेट के सामने हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिमांड के लिए लाया जाता है, उसे व्यक्ति की गिरफ्तारी की जरूरत और वैधता को लेकर संतुष्ट होना आवश्यक है। नई अपराध संहिता का खंड 187 (2) पुलिस अधिकारियों और न्यायाधीशों के बीच गलत धारणा पैदा करता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पुलिस या न्यायिक हिरासत में भेजा जाना चाहिए। मुझे न्यायमूर्ति कुष्णा अय्यर की वह चेतावनी याद आती है कि मजिस्ट्रेट किसी हिरासत की जरूरत नहीं के तीसरे विकल्प की अनदेखी करते हैं। खंड 254 जांच अधिकारी को श्रव्य-दृश्य माध्यमों से गवाही देने की अनुमति देता है, खुले सार्वजनिक न्यायालय में निष्पक्ष कार्यवाही के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। नया विधेयक यह स्पष्ट करने में विफल है कि जमानत नियम है, जबकि कारागार अपवाद है। नतीजतन, खंड 482 प्रतिगामी है।

सरकार की मंशा तो मैकाले और जेम्स स्टीफन की तरह कुछ ऐतिहासिक बदलाव लाने की थी, लेकिन ज्यादातर मौजूदा कानूनों को कॉपी, कट और पेस्ट करने से कथित बदलाव महज दो औपनिवेशिक हस्तियों को श्रद्धांजलि बन कर रह गए हैं।

पीएलजीए सप्ताह मनाने नक्सलियों ने फेंके पर्चे

कवर्धा। कबीरधाम जिले में एक बार फिर नक्सलियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। नक्सलियों ने जिले के वनांचल ग्राम समनापुर के एक दुकान के पास एमएमसी जोनल कमेटी के नाम से पम्पलेट लगाया है। जिसमें नक्सलियों ने ग्रामीणों से पीएलजीए सप्ताह मनाने अपील की है। ग्रामीणों की सूचना के बाद पुलिस सक्रिय हो गई है। पुलिस ने मामले की जांच के साथ इलाके में सर्चिंग भी तेज कर दी है।

कवर्धा के एएसपी हरीश राठौर ने बताया, 27 नवंबर की देर शाम झलमला थाना क्षेत्र के ग्राम समनापुर के एक दुकान के पास नक्सली पम्पलेट चस्पा होने की सूचना मिली थी। जिस पर पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और पम्पलेट जब्त कर मामले की छानबीन कर रही है। पूछताछ में ग्रामीणों ने बताया कि पम्पलेट लगाते किसी को नहीं देखा गया है। ग्रामीणों ने किसी बाहरी व्यक्ति के भी गांव में नहीं आने की बात कही है। जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही।

पीएजीए का मतलब पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी है। इस संगठन में शामिल नक्सली लड़ाई में माहिर और अत्याधुनिक हथियारों से लैस रहते हैं। इस नक्सली संगठन के सदस्यों के पास बड़ी घटनाओं की जानकारी होती है। ये बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। मुठभेड़ में मारे गए साथियों की याद में नक्सली हर साल 02 से 08 दिसंबर तक एक सप्ताह शहीद दिवस के रुप में मनाते हैं। साथ ही पूरे साल का नया लेखा-जोखा शुरु करते हैं। नक्सली पीएलजीए सप्ताह के दौरान साल भर की पूरी प्लानिंग भी करते हैं।

दरअसल कबीरधाम जिले में नक्सली 2015 से सक्रिय हैं। बोड़ला भोरमदेव एरिया कमेटी के सदस्यों की लगातार पुलिस एनकाउंटर में मौत हो रही थी। इसके बाद 06 माह पहले बस्तर से 25 सदस्यों को और बुलाया गया है। लेकिन नया इलाका और

अलग भाषा के चलते उन्हें सहयोग नहीं मिल पा रहा है। नक्सलियों की बोली-भाषा अलग होने के चलते ग्रामीण समझ नहीं पाते। यही वजह है कि इतने लंबे समय बाद भी नक्सली जिले में अपनी पैठ बनाने में नाकाम रहे हैं। बावजूद इसके नक्सली जिले में एरिया कमेटी का भी गठन कर चुके हैं। जिसके कई सदस्य पुलिस एनकाउंटर में मारे गए तो कुछ आत्मसमर्पण कर चुके हैं। ऐसे में नक्सली कबीरधाम जिले से लगे मध्यप्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क को अपना ठिकाना बनाए हुए हैं। कबीरधाम जिले में सामान लेने आना-जाना करते हैं। ऐसी सूचना समय समय पर मिलती रहती है।

दरअसल, कबीरधाम और राजनांदगांव जिले से लगे जंगल में महाराष्ट्र-मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को एक साथ जोड़ती है। यह नक्सलियों के लिए एक सुरक्षित स्थान माना जाता है। नक्सली घटना को अंजाम देने के बाद दूसरे राज्य में दाखिल हो जाते हैं। लेकिन पुलिस को दूसरे राज्यों में दाखिल होकर सर्चिंग करने लिए उच्च अधिकारियों की परमिशन लेनी पड़ती है। ऐसे में तब तक नक्सलियों को भागने का समय मिल जाता है। हालांकि इन तीनों राज्यों की पुलिस भी समय समय पर ज्वाइंट ऑपरेशन चलाती है। इससे तरह के ऑपरेशन से कई बार पुलिस को कामयाबी भी मिली है। बावजूद इसके नक्सली इसे सेफ जोन मानते हैं। इसलिए इस क्षेत्र का नाम एमएमसी जोनल कमेटी रखा गया है।

दंतेवाड़ा में पीएलजीए सप्ताह से पहले नक्सलियों ने मचाया उत्पात

दंतेवाड़ा। बस्तर में नक्सली लगातार अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए उत्पात मचा रहे हैं। नक्सलियों ने नारायणपुर और बारसुर के बीच हर्राकोडर गांव में लगे जियो टॉवर को आग के हवाले कर दिया है। इसी जगह पर नक्सलियों ने पीएलजीए सप्ताह मनाने के लिए पोस्टर भी फेंके हैं। नक्सलियों की पूर्व बस्तर डिवीजन कमेटी ने टॉवर में आग लगाई है और पोस्टर फेंके हैं। इस घटना की जानकारी मिलते ही एसपी गौरव राय ने पुलिस टीम को रवाना किया। पुलिस ने नक्सिलयों के फेंके बैनर पोस्टर उठा लिए हैं। इस घटना की जांच की जा रही है। दंतेवाड़ा एसपी, गौरव राय ने कहा जियो टावर में आगजनी के बाद नक्सलियों ने बैनर पोस्टर भी फेंके हैं। जिसमें नक्सलियों ने पीएलजीए सप्ताह मनाने का जिक्र किया है। जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट है और जिले के अंदरूनी क्षेत्रों में सर्चिंग तेज कर दी गई है। नक्सलियों ने न सिर्फ बस्तर बल्कि कबीरधाम में भी पीएलजीए सप्ताह मनाने के लिए पर्चे फेंके हैं। दरअसल नक्सली हर साल 2 दिसंबर से 8 दिसंबर तक पीएलजीए सप्ताह मनाते हैं। पीएलजीए यानी पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की इस बार 23वीं वर्षगांठ है। नक्सलियों ने गुरिल्ला युद्ध के लिए साल 2000 में पीएलजीए की स्थापना की थी।

हाथियों के झुंड ने रात भर गांव में मचाया आतंक, मकान को गिराया

कोरबा। कोरबा के कटघोरा वन मंडल में लगभग 60 हाथियों के झुंड में से 12 हाथियों ने झिनपुरी भदरापारा में बीती रात ग्रामीणों का घर घेर लिया। एक मिट्टी के मकान को जगह-जगह से छेद कर अंदर रखे धान और चावल को खा गए। घर पर रखे सामान को बिखेर दिया। ग्रामीण परिवार सहित भाग कर किसी तरह जान बचाई। इस घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया। पूरा गांव रतजगा करने को मजबूर हो गया।

वन परिक्षेत्र केंदई के ग्राम झिनपुरी निवासी राम सिंह मरकाम अपने घर में पांच सदस्यों के साथ सो रहा था, रात तीन बजे अचानक हाथियों की आहट सुनाई दी उसने परिवार के सभी सदस्यों को लेकर सुरक्षित स्थान पर जाना ही उचित समझा। चुपचाप कमरे से निकल कर गांव के ही पास दूसरे रिश्तेदार के घर जाकर सबने पनाह ली।

हाथियों ने घर के अंदर रखे धान और चावल को खा लिया यहीं नहीं बाकी सामान भी तहस नहस कर दिया। सुबह जब राम सिंह घर पहुंचा तो मकान को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त पाया। घटना की सूचना पर वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे और घटनाक्रम की जानकारी लेते हुए किसानों का क्षतिपूर्ति हेतु बयान दर्ज किया गया।

वन विभाग की माने तो लगभग 60 हाथियों का दल इस इलाके में विचरण कर रहा है जो रात को भोजन की तलाश में आसपास गांव में प्रवेश कर जाते हैं। गांव वालों से सावधान रहने की अपील की गई है और शाम होते ही घर से निकलने के लिए मना किया गया है। वहीं रेंजर अभिषेक दुबे ने बताया कि रामसिंह का मकान गांव के बाहर अकेले में है ऐसे स्थान पर हाथी जल्दी पहुंच जाते हैं इसलिए ग्रामीणों को सतर्क रहने की जरूरत है।

भाजपा को है बैलेट पेपर से छेड़छाड़ का डर, स्ट्रांग रूम में शिफ्ट करने की मांग!

भाजपा ने बैलेट पेपर की सुरक्षा पर उठाए सवाल

कोरबा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के तहत वोटों की गिनती 03 दिसंबर को होने हैं। इसे लेकर सभी जिलों में प्रशासन ने तैयारी पूरी कर रखी है। इस बीच कोरबा में बीजेपी के संगठन को डर है कि बैलेट पेपर के माध्यम से हुए मतदान से छेड़छाड़ हो सकती है। यह सभी बैलेट पेपर फिलहाल जिला कलेक्ट्रेट स्थित कोषालय में रखे हुए हैं। जिनकी सुरक्षा बढ़ाने के साथ इन्हें स्ट्रांग में शिफ्ट करने की मांग बीजेपी कर रही है। इस दौरान कोरबा जिले के चारों विधानसभा के भाजपा प्रत्याशियों की मौजूदगी में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है।

बीजेपी ने बैलेट पेपर की सुरक्षा पर सवाल उठाया है। भाजपा संगठन ने आशंका जताई है कि बैलेट पेपर से छेड़छाड़ की जा सकती है। जिले के चारों विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशियों ननकीराम कंवर, लखनलाल देवांगन, प्रेमचंद पटेल और रामदयाल उइके के साथ जिलाध्यक्ष राजीव सिंह ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने मांग रखी है कि बैलेट पेपर मतपत्र को ट्रेजरी से स्ट्रांग रूम में शिफ्ट किया जाए और उसकी सुरक्षा को चाक-चौबंद किया जाएं।

भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव सिंह का कहना है, अन्य जिलों में ऐसा देखने को मिला है कि बैलेट पेपर के आसपास अनाधिकृत और संदिग्ध लोगों का आवागमन हो रहा है। जिनमें से कई कांग्रेसी विचारधारा के हैं। इसलिए बैलेट पेपर से छेड़छाड़ की संभावना है। जिसे देखते हुए हमने बैलेट पेपर की सुरक्षा बढ़ाते हुए, इसे स्ट्रांग रूम में शिफ्ट करने की मांग कलेक्टर से की है।

बैलेट पेपर से मतदान करने वालों में सरकारी विभागों के अधिकारी-कर्मचारी के अलावा 80 के उपर आयु वाले मतदाता और दिव्यांगजन शामिल हैं। ऐसे सभी लोगों के वोट चुनाव के कुछ दिन पहले ही दर्ज कर लिए गए थे। सभी ने बैलेट पेपर के माध्यम से ही मतदान किया था।

अपनी मांगों को लेकर 11 महीनों से धरने पर बैठे आदिवासी ग्रामीण

■ आंदोलनकारियों ने पुलिस पर मारपीट करने का लगाया आरोप

नारायणपुर। जिले के अबूझमाड़ मुख्यालय ओरछा के नदी पारा में बीते 11 महीनों से धरने पर बैठे आदिवासी ग्रामीणों ने पुलिस के जवानों पर उनसे मारपीट करने का आरोप लगाया है। बता दें की नारायणपुर जिले के 5 अलग-अलग जगहों पर अबूझमाड़ के ग्रामीणों अपनी तीन सूत्रीय मांगो को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। जिसमें नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ के अंदरूनी इलाके सोनपुर, कच्चापाल, तोयामेटा, मड़ोनार और ओरछा शामिल है। वहीं ओरछा में बैठे ग्रामीणों का आरोप है की वहां बीते 11 महीनों से 104 गांव के लोग सरकार के खिलाफ 3 सूत्रीय मांगों को लेकरशांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठे हुए हैं। इसी दौरान शुक्रवार की सुबह ओरछा थाने से डीआरजी के जवान लगभग 150 की संख्या में उनके पास पहुंचे और ग्रामीणों से मारपीट की। ग्रामीणों का आरोप है की उनके कुछ साथियों को पुलिस थाने में ले जाकर मारपीट की है।

मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार ने कहा जिले में आचार संहिता और धारा 144 लगा हुआ। जिसके चलते ग्रमीणों को धारा 144 का उल्लंघन न करने की समझाइश देने जवान गए हुए थे। उसी दौरान ग्रामीण जवानों पर हावी होने लगे, जिसके बाद जवानों के साथ हलकी झुमाझटकी हो गई। जिससे कुछ जवानों को मामूली चोट आई और पुलिस ने पूरे मामले पर ग्रामीण के खिलाफ ओरछा थाने में प्राथमिक रिपोर्ट भी दर्ज किया है।

ग्रामीणों ने जवानों पर तोड़फोड़ का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने मीडिया को जवानों के द्वारा किये गए तोड़फोड़ किये गए सामानों के साक्ष भी दिखाए। वहीं ग्रामीणों ने कहा की टंगिया, फर्सा, लाठी और तीर धनुष हमारे पारंपरिक हथियार और परंपरागत तरीके से हम हथियारों को अपने साथ रखते हैं। वही पुलिस के जवानों द्वारा हम पर कितना भी अत्याचार किया जाए हम अपने मांगों को लेकर अडिग है और इसी तरह हम डटे रहेंगे।

बस्तर का ग्रामीण इसी तरह सिक्को की दो पहलुओं पर पिस रहा है। बस्तर का ग्रामीण कभी नक्सलियों तो कभी पुलिस के दबाव में जीवन यापन करने मजबूर है। वहीं ग्रामीणों का बस्तर के अंदरूनी इलाकों में लम्बे समय से धरने पर बैठना और सरकार के द्वारा उनकी मांगों पर अनदेखी करना। यह दर्शाता है बीते चार दशकों से बस्तर में चल रही नक्सलवाद की जंग ने एक नया मोड़ ले लिया हो।

पुल और नाली निर्माण करवाने गड्ढा खोदकर भूल गया नगर पालिका

नारायणपुर। पूरे भारत में स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है तो वहीं छत्तीसगढ़ के नगर पालिका परिषद नारायणपुर के निष्क्रियता के चलते दीनदयाल कॉलोनी के वार्डवासी अधूरे निर्माण और गंदगी जैसी अनेकों समस्याओं से जूझ रहे हैं।

दरअसल, मामल अटल आवास-दीनदयाल कालोनी नारायणपुर का है। जहां वार्डवासियों का आरोप है कि लगभग पिछले डेढ़ माह से नगर पालिका परिषद द्वारा कॉलोनी में नाली और पुल का जीर्णोद्धार करने के नाम पर गड्डा खोदकर छोड़ दिया गया है। जिसके कारण मार्ग अवरुद्ध है और लोगों को घूमकर आना-जाना पड़ता है। साथ ही अपूर्ण नाली में गंदा पानी भरा हुआ है। जिससे आस पास दुर्गंध फैला रहता है। गंदगी के कारण कीड़े- मकोड़े और मच्छर से वार्डवासी जूझ रहे हैं।

वार्डवासियों ने कहा कई दफा बच्चे खेलते खलते गड्ढे में गिर जाते हैं। परन्तु पालिका बड़ा हादसा होने का इंतजार कर रहा है। वार्डवासियों ने लिखित और मौखिक रूप से सीएमओ को समस्याओं से अवगत कराया है। लेकिन अधुरे कार्य को पूर्ण करने के बजाय उल्टा उन्हें नोटिस थमा दिया गया है।

इस पूरे मामले पर सीएमओ नारायणपुर, आशीष कोर्राम ने कहा कि अटल आवास और दीनदयाल कॉलोनी बीते कुछ माह पहले ही हाउसिंग बोर्ड के द्वारा नगर पालिका परिषद को हैंडओवर किया गया है और हम धीरे-धीरे वार्ड वार्डवासियों के नाली और सड़क के समस्यओं का समाधान कर रहें। नाली निर्माण कार्य पारम्भ किया गया था परन्तु कुछ जगह वार्डवासियों द्वारा अतिक्रमण किया गया। जिसके कारण कार्य बंद हैं।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

कोयलीबेड़ा क्षेत्र से आईईडी बरामद, डिफ्यूज करने के दौरान एक जवान घायल

कांकेर। सर्चिंग पर निकली छ्त्रन्न व क्स्स्न की संयुक्त टीम ने कोयलीबेड़ा क्षेत्र के पानीदोबीर जंगल क्षेत्र से पाइप आईईडी बम बरामद किया। बीडीएस टीम की सहायता से आईईडी को जंगल में ही नष्ट किया गया। इस दौरान एक जवान घायल हो गया। आईईडी बम को डिफ्यूज करते वक्त आईईडी में लगा स्प्रिंटल जवान के कान के पास लगा। इससे जवान जानकीराम दुग्गा घायल हो गया। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने बताया कि जवान को मामूली चोट आई है। जवान पूरी तरह सुरक्षित है।

स्कूल जा रही छात्रा के अपहरण से मचा हड़कंप

जशपुर। जशपुर सिटी कोतवाली क्षेत्र के लोखंडी गांव में एक स्कूली छात्रा के अपहरण की खबर से सनसनी फैल गई। कुछ कार सवार युवकों ने इस घटना को अंजाम दिया है। छात्रा के अपहरण की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने पूरे जिले में कड़ी नाकाबंदी कर सघन जांच शुरू कर दी है लेकिन अभी तक बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। स्कूली छात्रा के दिन दहाड़े अपहरण के बाद जशपुर में बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। छात्रा के अपहरण की यह घटना आज दोपहर 11 बजे की बताई जा रही है। स्कूली छात्रा अपनी एक सहेली साथ स्कूल जा रही थी तभी बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में इस वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने पहले युवती को फिल्मी स्टाईल में जबरन गाड़ी में बैठा लिया और मौके से भाग निकले। इस बीच अपहृत युवती की सहेली किसी तरह बच निकली और शोर मचाने लगी लेकिन तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुके है। जिला एसपी डी रविशंकर ने बताया कि अपहृत युवती की सहेली से घटना के संबंध में पुलिस पूछताछ कर रही है।

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र से निकला बल्लेबाज

नारायणपुर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया द्वारा आयोजित भारतीय क्रिकेट की मजबूत जड़ मानी जाने वाली अंडर 16 की विजय मर्चेंट ट्रॉफी का आयोजन 1 दिसंबर से होने जा रहा है। जिसमें छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ की अंडर 16 टीम में नक्सल प्रभावित जिले नारायणपुर का एक होनहार क्रिकेट खिलाड़ी रिजूल देवांगन का चयन हुआ है। रिजूल टीम में मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज और एक राइट आर्म लेग स्पिनर गेंदबाज की भूमिका निभायेंगे रिजूल का सफर नारायणपुर की डिस्ट्रिक टीम से शुरू हुआ था। प्लेट ग्रुप इंटर डिस्ट्रिक टूर्नामेट में रिजूल ने अपने खेल से चयनकर्ताओं को काफी प्रभावित किया, कुछ अच्छी पारी खेलने के बाद रिजूल का चयन रेस्ट ऑफ सीएससीएस के प्लेट कंबाइंड टीम में हुआ। जहां पर एलिट ग्रुप की टीमों के खिलाफ मुश्किल परिस्थिति में एक मैच विनिंग शतकीय पारी खेलने के बाद सीएससीएस टीम के चयनकर्ताओं का ध्यान अपने तरफ खींचा और रिजूल का सिलेक्शन 30 सदस्यीय बोर्ड कैम्प में हुआ।

बीएसपी का चोरी हुआ 32 लाख का मैग्नेटिक क्वाइल बरामद

दुर्ग/भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र से चोरी किये गए मैगेनेटिक क्वाइल का पता पुलिस ने लगाया है। दुर्ग पुलिस ने चोरी हुए मैगेनेटिक क्वाइल को बीएसपी के जोरातराई गेट के पास से बरामद करने में सफलता हासिल की है। लेकिन पुलिस को भिलाई स्टील प्लांट से चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले चोरों का सुराग नहीं मिला है। दुर्ग पुलिस पूरे मामले को लेकर बड़े स्तर पर जांच पड़ताल कर रही है। भट्ठी थाना भिलाई टीआई विपिन रंगारी ने बताया कि सुबीद कुमार डे भिलाई इस्पात संयंत्र में महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराया कि 30 अक्टूबर से 3 नवंबर के अज्ञात व्यक्ति ने बोरिया गेट स्टोर नंबर 7 से 16 नग मैगेनेटिक क्वाइल गायब कर दिया है। जिसकी कीमत करीब 32 लाख के आसपास है। बाहर से 23 अक्टूबर को मैगेनेटिक क्वाइल को मंगाया गया था। इसे भंडार गृह नंबर 8 में रखना था, लेकिन भारी होने के वजह से उसे उतारते नहीं बना, तो क्रेन की मदद से उठाकर स्टोर नंबर 7 में रखवाया गया था।

हाईवा और कार में हुई आमने-सामने की टक्कर

भिलाई। भिलाई के जामुल थाना क्षेत्र के दुर्ग धमधा मार्ग पर भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौके पर मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक, हाईवा और स्विफ्ट कार की आमने-सामने टक्कर हो गई, जिसमें कार सवार एक पुरुष और दो महिलाओ की मौत हो गई। घटना की सूचना पर जामुल पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सभी मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुट गई है। पुलिस ने बताया कि स्मृति नगर भिलाई निवासी 67 वर्षीय पी वेंकट रत्नम, 60 वर्षीय पत्नी श्यान्ति और श्यान्ति की बुजुर्ग माता की मौत हुई है। तीनों के शव को भिलाई के सुपेला अस्पताल के मर्च्युरी में रखा गया। वहीं, हाईवा टिप्पर को जामुल पुलिस ने जब्त कर लिया है। घटना के बाद से हाईवा का चालक फरार बताया जा रहा है। तीनों मृतक अपनी कार से बेरला से भिलाई लौट रहे थे।

बालोद में मतगणना को लेकर प्रशासन की तैयारी पूरी

■ कलेक्टर के नेतृत्व में हुई ऑफिसर्स की ट्रेनिंग

बालोद। छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत बालोद में मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है। काउंटिंग का काम पूरी तरह से त्रुटिरहित और पारदर्शी तरीके से हो, इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है। ईव्हीएम, वीवीपैट से मतगणना हेतु गणना सुपरवाईजर एवं गणना सहायकों को प्रशिक्षण भी दिया गया है। जिसका नेतृत्व जिला निर्वाचन अधिकारी कुलदीप शर्मा ने किया। इस दौरान कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने गणना सुपरवाईजर एवं गणना सहायकों को उनके कार्यों एवं दायित्वों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी।

मतगणना में त्रुटि की कोई गुजांईश नहीं

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं बालोद कलेक्टर कुलदीप शर्मा आज जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित प्रशिक्षण के दौरान मौजूद रहे। इस दौरान कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने कहा, निर्वाचन से जुड़े सभी काम विशेष प्राथमिकता का कार्य होता है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि की कोई गुजांईश नहीं होती। उन्होंने मतगणना कार्य में लगे सभी अधिकारी-कर्मचारियों को पूरी तरह से त्रुटिरहित एवं पारदर्शी तरीके से काउंटिंग संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। यहां ईव्हीएम एवं वीवीपैट से मतगणना हेतु गणना सुपरवाईजरों एवं गणना सहायकों के रूप में अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सभी अधिकारी-कर्मचारियों को पूरी गंभीरता के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करने कहा है। उन्होंने अधिकारियों को मतगणना के दिन समय-सीमा का ध्यान रखते हुए गंभीरता एवं विशेष सावधानी के साथ अपने दायित्वों को निभाने को कहा है। इस प्रशिक्षण में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ रेणुका श्रीवास्तव, डिप्टी कलेक्टर प्राची ठाकुर भी मौजूद रहीं।

प्रत्येक राउंड के बाद होगी रेंडम जांच

कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने अधिकारियों से मतगणना स्थल के व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को मतगणना कार्य में लगे अधिकारी-कर्मचारियों एवं अभिकर्ताओं के लिए समुचित पेयजल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षकों ने गणना सुपरवाईजरों एवं गणना सहायकों, उनके कार्यों एवं दायित्वों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। 3 दिसम्बर को मतगणना स्थल में सर्वप्रथम डाक मत पत्रों की गणना की जाएगी। इसके बाद कंट्रोल यूनिट के माध्यम से गणना प्रारंभ किया जाएगा। इन सभी प्रक्रियाओं की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। हर एक राउंड की गणना खत्म होने के बाद सामान्य प्रेक्षक के द्वारा दो मतदान केंद्रों के मशीनों की रेण्डम जांच कर अतिरिक्त गणना अधिकारियों के माध्यम से सत्यापन कराया जाएगा।

कोरबा में झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही ने ले ली एक मरीज की जान

कोरबा। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग के लाख प्रयासों के बाद भी अंदरूनी क्षेत्रों में झोलाछाप डॉक्टर सक्रिय हैं। ग्रामीण बीमार पड़ने पर इनसे इलाज भी करा लेते हैं। लेकिन सस्ता इलाज एक मरीज को महंगा पड़ गया। एक व्यक्ति को पेट में तेज दर्द हुआ, तो झोलाछाप डॉक्टर ने पेट में इंजेक्शन लगा दिया। इसके कुछ दिनों बाद मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। यह पूरा मामला कोरबा के पसान थाना क्षेत्र के ग्राम गुरुद्वारी का है। जहां भानूप्रताप ओट्टी नाम के व्यक्ति को पेट में तेज दर्द हुआ। भानुप्रताप की पत्नी सुकुल बाई और बेटा शिवगोपाल मनरेगा के कार्य में व्यस्त थे। वह रोजी मजदूरी कर रहे थे। इसलिए भानुप्रताप ने खुद ही झोलाछाप डॉक्टर करण कुमार को बुलाया और इलाज करने को कहा। डॉक्टर ने उसे चार इंजेक्शन लगा दिया, जिसमे से एक इंजेक्शन पेट में भी लगाया। इसके कुछ दिनों बाद मरीज ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। जिसके बाद परिवार ने इसकी शिकायत पुलिस में की। पुलिस ने झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। झोलाछाप डॉक्टर करण कुमार ने 3 नवम्बर को भानुप्रताप को 4 इंजेक्शन लगाया था। एक बांह में, 2 कमर और 1 इंजेक्शन पेट में लगाया था। पेट में इंजेक्शन लगाने के बाद भानुप्रताप का पेट दर्द और बढ़ गया। ग्रामीण की पत्नी सुकुल बाई ने झोलाछाप डॉक्टर करण को फोन लगाकर तबीयत और बिगड़ जाने की जानकारी दी। तब करण ने समय नहीं होने की बात कहकर फोन रख दिया। भानुप्रताप का पेट दर्द और बढ़ता देख परिजनों ने उन्हें पेंड्रा के अस्पताल में भर्ती कराया। जहां 2 दिन तक उनका इलाज चलता रहा, लेकिन भानुप्रताप की तबीयत ठीक नहीं हुई। इसके बाद मरीज को बिलासपुर ले जाने की सलाह दी गयी। इसी बीच 20 नवंबर की सुबह भानुप्रताप की मौत हो गई।

संक्षिप्त समाचार

कांग्रेस अध्यक्ष से मिले सीएम बघेल छत्तीसगढ़ में जीत के लिए किया आश्वस्त

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से दिल्ली में मुलाकात की। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री बघेल ने ङ्क पर लिखा, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से आज उनके निवास पर सौजन्य मुलाकात हुई। उन्होंने पांच राज्यों के चुनाव में अथक परिश्रम किया है। उनकी ऊर्जा हमारे लिए प्रेरणादायक है। सीएम बघेल ने कहा, मैंने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत के प्रति उन्हें एक बार और आश्वस्त किया।

तीन दिवसीय संत बाबा गेलाराम साहेब का 15वां बरसी महोत्सव 8 दिसंबर से

रायपुर। देवपुरी स्थित गोदड़ीवाला धाम में संत बाबा गेलाराम साहेब का 15वां बरसी महोत्सव 8, 9 व 10 दिसंबर को मनाया जाएगा। दरबार के सेवादारी अमर गिदवानी, हरि ईसरानी, पवन प्रीतवानी, सतीष थौरानी ने बताया कि बरसी महोत्सव की तैयारियों पर जोर दिया। गोदड़ीवाला प्राथमिक पाठशाला देवपुरी के द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। विशाल निःशुल्क नेत्र शिविर, ब्लड डोनेशन कैम्प भी लगाया जाएगा। तीनों दिन अनेक कार्यक्रम होंगे। राजेश कुमार अमरावती, युधिष्ठिर लाल शदाणी दरबार, चाण्डूराम साहेब शिवशांति आश्रम लखनऊ आदि विशेष रूप से शामिल होंगे। भजन मंडलियों में कथावाचक डॉ. मनमोहन कृष्ण बृजधाम मथुरा वृंदावन, त्रिलोक एण्ड पार्टी इटारसी, बाबा बालक मंडल जलगांव साहेब रायगढ़ एवं भाटापारा, कृष्णधाम आश्रम चकरभाटा व अन्य कई भजन मंडलियां भी शामिल होगी।

100 बिस्तर अस्पताल के लिए 94 पद मंजूर

रायपुर। चिरमिरी सीएचसी को अपग्रेड कर 100 बेड का बनाया जाएगा इसके लिए 94 पदों को मंजूरी दी गई है। वर्तमान में सीएचसी में 50 बेड हैं। शासन ने आचार संहिता के पहले अस्पताल में अधीक्षक, मेडिकल, सर्जिकल और निश्चेतना विशेषज्ञ के पदों को मंजूरी दी थी। साथ ही विभिन्न विभागों में पीजी मेडिकल ऑफिसर के 7, चिकित्सा अधिकारी के 8 और स्टॉफ नर्स के 30 पदों की स्वीकृति दी गई है। अस्पताल अधीक्षक के एक पद, मेडिकल विशेषज्ञ, सर्जिकल विशेषज्ञ और निश्चेतना विशेषज्ञ के एक-एक पद, शिशु रोग, रेडियोलॉजी, ईएनटी, नेत्र रोग, अस्थि रोग, मेडिसिन और स्त्री रोग विभाग में पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल ऑफिसर के एक-एक पद होंगे। चिकित्सा अधिकारी के आठ पद, दंत चिकित्सक के एक पद, मेडिकल रिकॉर्ड अधिकारी के एक पद, स्टॉफ नर्स के 30 पद, नर्सिंग सिस्टर, ऑडियोमेट्रिशियन, रेडियोग्राफर, स्टोर कीपर, फॉर्मासिस्ट ग्रेड-2, कोल्ड चैन-कम-वैक्सीन लॉजिस्टिक असिस्टेंट, सहायक ग्रेड-3 और ड्रेसर ग्रेड-2 के दो-दो पद हैं। इसी तरह लैब टेक्नीशियन के चार पद, लैब अटेंडेंट के तीन पद, लेखापाल, ऑप्थेलमिक असिस्टेंट, डेंटल असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन, वाहन चालक, ड्रेसर ग्रेड-1, भृत्य, धोबी, चौकीदार और स्वीपर के एक-एक पद तथा वार्ड ब्वाय और आया के पांच-पांच पद के सृजन की मंजूरी दी गई है। अधिकारियों के अनुसार आचार संहिता खत्म होते ही स्वीकृत पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। जरूरी योग्यता भर्ती नियमों के अनुसार होगा। ताकि इस पर कोई विवाद न हो।

दो डाक अफसर हुए पदोन्नत, सरगुजा व बिलासपुर के बदले अधीक्षक

रायपुर। सहायक निदेशक एके. सिंह के स्थान पर सौरभ कुमार असाटी को एडी-स्टाफ के पद पर सीपीएमजी छत्तीसगढ़ वीणा श्रीनिवासन ने पदोन्नत करते हुए तबादला किया है। सिंह दीपावली से पहले पदोन्नत होकर मप्र के शहडोल एसपी के रुप में पदस्थ किए गए है लेकिन उनकी रिलीविंग अब तक नहीं हो पाई है। स्थानांतरण के बाद आवश्यक विजिलेंस क्लीयरेंस नहीं मिल पाया है। सौरभ कुमार तभी ज्वाइन करेंगे जब सिंह रिलीव होंगे। विनय कुमार प्रसाद एएसपी बिलासपुर को वहीं पदोन्नत कर एसपी पदस्थ किया गया है। एएसपी रवि लाल कचेर, एडी-3 यानी बिजनेस डेवलपमेंट और फिलैटेली पदोन्नत किए गए हैं। इसी तरह से एसपी सरगुजा आलोक कुमार को एडी-2, इंक्वायरी, मेल के पद पर सर्किल आफिस लाया गया है। उनकी जगह बिलासपुर एसपी एच आर साहू को सरगुजा पदस्थ किया गया है।वहीं एडी श्री पारधी को कोई आंच नहीं आई है। वे पी एल आई, टेक्नोलॉजी का काम देखते रहेंगे।

पुलिस की वर्दी में रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया इस महिला को

रायपुर। रायपुर पुलिस ने पुलिस की वर्दी में एक महिला को गिरफ्तार किया है। ये महिला अपने आप को टिकरापारा थानाक्षेत्र की हेड कांस्टेबल बताती थी। हालांकि इस महिला का वर्दी पहनने का उद्देश्य क्या था और इस वर्दी के एवज में उसने क्या-क्या खेल किए इसकी पूछताछ अभी पुलिस कर रही है। जिसके बाद उम्मीद है कि कई चौंकाने वाले खुलासा हो सकते है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी महिला को कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनने तथा टोकन धारण किए हालत में पाए जाने धारा 171 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला का नाम मल्लिका गिरी है। ये आरोपिया मठपुरैना में ही रहती है।

प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 14 टेबलों पर एक साथ होगी मतगणना

■ **प्रदेश के 90 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना के लिए तैयारियाँ पूरी**

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन-2023 अंतर्गत 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए दो चरणों में हुए मतदान के बाद आगामी 3 दिसम्बर को मतगणना होगी। इसके लिए सभी 33 जिला मुख्यालयों में तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि सभी मतगणना केंद्रों में प्रेक्षकों की निगरानी में होने वाली मतगणना के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 14 टेबल लगाए गए हैं। मतों की गिनती सुबह आठ बजे से शुरू होगी जिसमें सबसे पहले सेवा मतदाताओं के मतों की गणना होगी। सबसे पहले ईटीपीबीएस (इलेक्ट्रानिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलैट सिस्टम) से प्राप्त मतों के क्यूआर कोड की स्कैनिंग की जाएगी। उसके बाद डाक मतपत्रों की गिनती शुरू होगी। साढ़े आठ बजे के बाद सभी टेबलों पर एक साथ मतगणना शुरू होगी। प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों में से कवर्धा में सबसे अधिक 30 चक्रों में मतगणना होगी। इसके बाद कसडोल में 29 चक्र होंगे। वहीं सबसे कम मनेन्द्रगढ़ एवं भिलाई नगर में 12 चक्रों में मतगणना होगी।

श्रीमती कंगाले ने बताया कि कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना केन्द्रों में होने वाली मतों की गिनती के दौरान बिना प्राधिकार पत्र के किसी भी व्यक्ति को मतगणना कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। उल्लेखनीय है कि 1181 अभ्यर्थियों के राजनीतिक भाग्य का फैसला 7 नवम्बर और 17 नवम्बर को ईव्हीएम में बंद हुआ था। आगामी 3 दिसम्बर को मतों की गिनती के साथ ही इनके परिणाम आएंगे। मतगणना के दौरान अभ्यर्थी किसी भी टेबल पर जाकर मतगणना को देख सकेंगे जबकि अभ्यर्थी के अभिकर्ता सिर्फ निर्धारित टेबल पर ही मतगणना का निरीक्षण करेंगे। मतगणना की पूरी कार्यवाही मतगणना प्रेक्षक तथा सामान्य प्रेक्षक की उपस्थिति तथा निगरानी में होगी। इस दौरान प्रत्येक राउंड की समाप्ति पर अभ्यर्थी या उनके अभिकर्ता की उपस्थिति एवं प्रेक्षक की निगरानी में रैंडम आधार पर किसी दो कंट्रोल यूनिट की जाँच की जाएगी। इसके अलावा सभी चक्रों की गणना पूर्ण होने पर पाँच वोटर वेरिफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (व्हीव्हीपेट) का ड्रा के माध्यम से चयन कर मतों का सत्यापन किया जाएगा।

मतदान के बाद ईवीएम को सभी जिला मुख्यालयों में स्ट्रांग रूम में त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में रखा गया है। पूरी मतगणना प्रक्रिया की रिकार्डिंग भी रखी जाएगी। इस दौरान प्रेक्षक तथा रिटर्निंग ऑफिसर को छोड़कर मतगणना कक्ष में किसी को भी मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण यथा आईपेड, रिकार्डर, वीडियो कैमरा जैसे अन्य उपकरण नहीं ले जा सकेंगे।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बीजापुर में ईवीएम से जुड़ी शिकायत को बताया निराधार

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने कहा है कि निर्वाचन आयोग निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतगणना के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य किया जा रहा है। ईवीएम और डाकमतपत्रों की सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। ईवीएम के लिए स्ट्रांगरूम में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

बीजापुर जिले में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन स्ट्रांग-रूम में संधारित न होकर खुले में रखे पाए जाने की शिकायत निराधार है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने इस संबंध में स्पष्ट करते हुए कहा है कि प्रशिक्षण के लिए निर्धारित इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन जिनके सीरियल क्रमांक की जानकारी उम्मीदवारों को पूर्व से ही दी गई है, उन्हें प्रशिक्षण के लिए निर्धारित प्रशिक्षण स्थल कलेक्टरेट सभाकक्ष बीजापुर में लाया गया था तभी दूर से फोटो लिया गया है।

साथ ही मौके पर मतपेटियों के खुली पाए जाने तथा फटे मतपत्र चारों ओर बिखरे पड़े होने और मत-पेटियों तथा मतपत्रों से छेड़-छाड़ के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि विधानसभा निर्वाचन में डाक मतपत्र के लिफाफे गुलाबी रंग के हैं। जबकि प्रचारित फोटो और विडियो में भूरे रंग के लिफाफों को दर्शाया गया है। जिस से स्पष्ट है कि यह डाक मतपत्र या उनके लिफाफे नहीं हैं।

वास्तव में ये जिला निर्वाचन अधिकारी बीजापुर के कार्यालय में वीवीपेट के पर्चियों की गणना के लिए आवश्यक तैयार किए जा रहे पिजन होल में लगाए जा रहे प्रतीक चिन्ह के फोटो है। जो स्टील पेटियां फोटो मे दिखाई गई हैं वो जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय की स्टील पेटियां हैं। जिसमें विविध निर्वाचन सामग्री रखी जाती हैं। अतः यह फोटो और विडियो जिसके आधार पर शिकायत की गई है भ्रामक और निराधार है।

सर्व समाज के 76% आरक्षण विधेयक को रोककर आखिर किस बात का बदला ले रहे हैं भाजपाई?

रायपुर। विगत 2 दिसंबर 2022 से राजभवन में लंबित आरक्षण विधेयक को लेकर भारतीय जनता पार्टी के रवैया पर सवाल उठाते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ के बहुसंख्यक आबादी अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति सहित सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनता से भारतीय जनता पार्टी को आखिर इतनी नफरत क्यों है? भारतीय जनता पार्टी के नेता आखिर क्यों नहीं चाहते कि छत्तीसगढ़ के निवासियों को उनकी संख्या के अनुसार उनका हक मिले। स्थानीय जनता के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तरक्की से भाजपाइयों को इतनी हिकारत क्यों है? भाजपा के नेता और केंद्र की मोदी सरकार क्यों नहीं चाहती की स्थानीय जनता को शिक्षा और रोजगार में प्राथमिकता मिले?

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि जहां-जहां भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है वहां पर राज्य सरकारों के द्वारा विधानसभा में पारित विधेयकों को राजभवन की आड़ में लटकाने का षड्यंत्र रचने का काम लगातार कर रही है। छत्तीसगढ़ में एक तरफ जहां आरक्षण विधेयक के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने सहमति जताते हुए सर्वसम्मति से पारित करवाया लेकिन तत्काल बाद से राजभवन के आड़ में रोकने का षड्यंत्र रचे। विगत लगभग 1 साल से राज भवन में इतना महत्वपूर्ण विधेयक लंबित है, लेकिन भाजपा का कोई भी नेता राजभवन से उक्त विधेयक पर अनुमोदन के लिए तत्परता बरतने की अपील करता हुआ नहीं दिखा, उल्टे समय समय पर छत्तीसगढ़ के भाजपाई लंबित आरक्षण विधेयक को लटकाए जाने की वकालत करते रहे है।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि 15 साल भाजपा को अवसर मिला था कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति, समृद्धि और स्थानीय बहुसंख्यक आबादी के हितों का संरक्षण और संवर्धन करते, लेकिन भाजपाइयों ने स्थानीय छत्तीसगढिया जनता के हितों की सदैव उपेक्षा ही किया है। भूपेश बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ में सर्व समाज को आरक्षण देने का काम पूरी ईमानदारी से किया है। 15 साल रमन राज में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की दिशा में कोई प्रयास नहीं हुआ। भूपेश सरकार ने न केवल कमेटी गठित की बल्कि मोबाइल एप और वेबसाइट के माध्यम से आंकड़े जुटाकर स्थानीय निकाय के सामान्य सभा में अनुमोदित भी कराया, आधार से वेरिफिकेशन करके डेटाबेस तैयार किया। विधि विभाग से परीक्षण के उपरांत 76 प्रतिशत नवीन आरक्षण विधेयक पारित किया गया। विधेयक में अनुसूचित जनजाति के लिए 32 प्रतिशत, ओबीसी के लिए 27, अनुसूचित जाति के लिए 13 प्रतिशत और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। उक्त विधेयक का समर्थन विधानसभा के भीतर भाजपा की विधायकों ने भी किया। यह भाजपा के राजनीतिक पाखंड का ही नमूना है कि एक तरफ समर्थन का ढोंग करते हैं, दूसरी तरफ राजभवन में षड्यंत्र करके विधेयक को लटकाए रखने की साजिश रचते हैं। छत्तीसगढ़ की स्थानीय आबादी से आखिर किस बात का बदला लेना चाहते हैं भाजपाई?

मतगणना से पहले जीत का दावा कांग्रेस-भाजपा में छिड़ी जंग

गौरीशंकर ने लगाया दांव- कांग्रेस जीती तो दूंगा दो लाख

रायपुर। छत्तीसगढ़ में तीन दिसंबर को मतगणना होना है। सभी राजनीतिक पार्टी के नेता अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं प्रदेश की जनता भी अबकी बार छत्तीसगढ़ में किसकी सरकारी बनेगी? पर चर्चा कर रहे हैं। वहीं भाजपा और कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने मतगणना से पहले ही रिजल्ट पर दांव लगा बैठे हैं। भाजपा ने दो लाख रुपये का दांव लगाया तो कांग्रेस बढ़कर ढाई लाख रुपये का दांव लगाया है। फिलहाल, यह तीन दिसंबर को ही तय होगा कि छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी।

भाजपा प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने जीत का दावा करते हुए दो लाख रुपये का दांव लगाया है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुबोध हरितवाल ने भी जीत का दावा करते हुए ढाई लाख रूपये का दांव लगा दिया है। दोनों ने ही सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया है। इस दौरान दोनों ही पार्टी के प्रवक्ता ने एक दूसरे पर निशाना भी साधा है। वहीं दोनों अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि बस कुछ ही दिन फिर छत्तीसगढ़ कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है। भय, भूख, भ्रष्टाचार समाप्त ,पुरखों का छत्तीसगढ़ बनाएंगे सुशासन लाएंगे। उन्होंने ने इस पर सुबोध हरितवाल टैग कर लिखा कि @subodhharitwal कोई संदेह हो तो दो लाख रूपये की शर्त लगा लीजिए सुबोध जी विदाई का समय आ गया है-@INCChhattisgarh

दूसरी ओर इस ट्वीट का जवाब देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सुबोध हरितवाल ने भी सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि आपकी चुनौती स्वीकार है, कमीशनबाज भाजपा को छत्तीसगढ़ की जनता कभी मौका नहीं देगी। उन्होंने बढ़कर दांव भी लगाया है। सुबोध हरितवाल ने लिखा कि शर्त की एक और शर्त है, मैं जीता तो 2 लाख रुपये लूंगा, पर यदि आप जीते तो ढाई लाख रूपये दूंगा वादा रहा। उन्होंने कहा की भरोसा बरकरार फिर से कांग्रेस सरकार।

कांग्रेस नेताओं को पार्टी से सस्पेंड करने का मामला जिला अध्यक्ष को पीसीसी ने थमाया स्पष्टीकरण

कबीरधाम। कबीरधाम जिले में बीते दो दिनों से कांग्रेस पार्टी का हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है। दरअसल, कांग्रेस जिला अध्यक्ष होरीराम साहू ने मंगलवार व बुधवार को एआईसीसी व पीसीसी के पंडरिया विधानसभा के चुनाव प्रभारी की रिपोर्ट पर पूर्व जिला अध्यक्ष महेश चन्द्रवंशी, प्रदेश युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष तुकाराम चन्द्रवंशी समेत 10 बड़े नेताओं को पार्टी से छह साल के लिए सस्पेंड कर दिया था। रिपोर्ट में बताया गया था कि ये सभी कांग्रेस नेता पंडरिया विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी के

खिलाफ काम किया है। इससे पार्टी की छवि धूमिल हुई है।

अब इस पूरे मामले को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बुधवार को संज्ञान में लिया। पीसीसी के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू के हस्ताक्षर से जारी आदेश अनुसार कबीरधाम जिला कांग्रेस अध्यक्ष होरीराम साहू को स्पष्टीकरण थमाया है। जारी आदेश में बताया गया है कि पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के पार्टी अधिकृत प्रत्याशी के शिकायत पर स्थानीय कार्यकर्ताओं को सस्पेंड किए जाने का मामला प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संज्ञान में आया है, जो पार्टी संगठन के संविधान विरुद्ध कार्रवाई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए आपके द्वारा बिना संज्ञान में लिया गया, उक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई को तत्काल निरस्त करते हुए बहाल किए जाने संबंधी आदेश जारी करें। आपके द्वारा उक्त कार्रवाई के संबंध में अपना लिखित स्पष्टीकरण पत्र 24 घंटे के भीतर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजें। बहाली आदेश जारी नहीं किए जाने की स्थिति में उक्त सस्पेंड आदेश निरस्त माना जाएगा।

इधर, कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने कार्यकर्ताओं व बड़े नेताओं को सस्पेंड किए जाने के बाद काफी किरकिरी हो रहीं है। क्योंकि, ये कंट्रोवर्सी बीते दो दिनों से चल रहीं है। जिन नेताओं को सस्पेंड किया गया था, वे स्पष्ट तौर पर कह चुके है, उन्हें किसी भी प्रकार से नोटिस नहीं दिया गया और न ही उनसे कार्रवाई के संबंध में जानकारी दी गई थी।

जनता ने भाजपा को मुख्यमंत्री का चेहरा ढूंढने का अवसर नहीं दिया : ठाकुर

रायपुर। प्रदेश में फिर कांग्रेस की सरकार बन रही है।जनता ने भाजपा को मुख्यमंत्री का चेहरा ढूंढने का अवसर नहीं दिया है। भाजपा को नेता प्रतिपक्ष कौन होगा? इस दिशा में मजबूती से प्रयास करना चाहिए।भाजपा को यह बताना चाहिए क्या मोदी की गारंटी पर चुनाव लडने वाली भाजपा का अगला नेता प्रतिपक्ष गारंटी देने वाला होगा? या फिर राज्य निर्माण के वक्त नेता प्रतिपक्ष चुनने आए प्रभारी के साथ एकात्म परिसर में हुई घटना की फिर पुनर्विवृत्ति होने वाली है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि जनता ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का चेहरा सरकार के काम और कांग्रेस की घोषणा पत्र पर भरोसा किया है। भाजपा जिस प्रकार से नकारात्मकता ,अफवाह फैलाकर चुनाव लड़ी है। जनता ने उसे खारिज कर दिया है।दूसरे राज्यों से भाजपा के कई दिग्गज नेता आकर छत्तीसगढ़ में चुनाव की कमान संभाले थे।सभी को मुंह की खानी पड़ी है। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेताओं को चुनाव प्रचार के दौरान धूल चटा दिया है। भाजपा के घोषणा पत्र मोदी की गारंटी और भाजपा के षड्यंत्र के खिलाफ जनता कांग्रेस के साथ खड़ी रही है। ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की सरकार विपक्ष का पूरा सम्मान करती है और उम्मीद करती है कि विपक्ष अपने जिम्मेदारियां का ठीक से निर्वहन करें। भाजपा नेताओं को अभी से नेता प्रतिपक्ष चुनने की प्रक्रिया में जुट जाना चाहिए।

छत्तीसगढ़ में मनसुख मंडाविया आ जाये या अमित शाह, सरकार तो कांग्रेस की ही बनेगी

■ **भाजपा की काउंटिंग रणनीति पर सुशील आंनद का तंज**

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए दो चरणों में 90 सीटों में मतदान हो चुका है। पहले चरण में 20 सीटों में 7 नवंबर और दूसरे चरण में 17 नवंबर को 70 सीटों में मतदान हुआ। चुनावी मैदान में उतरे उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला 3 दिसंबर को होगा। जिसमें पता चलेगा की प्रदेश में किसकी सरकार आएगी। इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं मतगणना को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। पीसीसी संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आंनद शुक्ला ने भाजपा की मतगणना को लेकर रणनीति पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मनसुख मंडाविया या चाणक्य अमित शाह आ जाये, छत्तीसगढ़ में सरकार तो कांग्रेस की ही बनेगी। इसके साथ ही उन्होंने कर्मचारियों के नियमतिकरण पर कहा कि जो कर्मचारी बचे हैं उनके हित में आगे निर्णय लिया जाएगा।

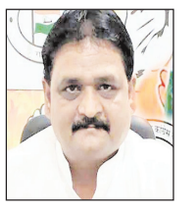

मतगणना को लेकर भाजपा की रणनीति पर कांग्रेस ने तंज कसा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आंनद शुक्ला ने कहा कि भाजपा मुगालते पालकर बैठी हैं कि वो सरकार बनाने जा रही। ढाई के अंक तक मुश्किल से पहुंचेगी, कोई भी रणनीति बना ले सब धरी के धरी रह जाएगी। छत्तीसगढ़ में चाहे मनसुख मंडाविया आ जाये या चाणक्य अमित शाह आ जाये, सरकार तो कांग्रेस की ही बनेगी।

नियमतिकरण की आस में बैठे कर्मचारी पर सुशील आंनद ने कहा, भाजपा के 15 साल की सरकार में कर्मचारियों का अन्याय, शोषण हुआ। हमारी सरकार के समय में कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की गई, बहुत से कर्मचारियों को नियमित भी किया। जो कर्मचारी बचे हैं उनके हित में संसाधनों और बजट को देखते हुए आगे निर्णय लिया जाएगा।

मतगणना को लेकर भाजपा की तैयारी पर सुशील आंनद शुक्ला ने कहा, मतगणना में गड़बड़ी करना भाजपा का चरित्र रहा है। मध्यप्रदेश में कलेक्टर ने बैलेट पेपर खुलवा दिया। भाजपा चुनाव हार रही है। इसलिए उनके नेता पटकथा लिख रहे हैं। हारने के बाद पट कथा बताएंगे कि मतगणना में गड़बड़ी हुई है।

भाजपा पर धान के मूल्य को लेकर कांग्रेस हमलावर रही हैं। इस पर सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, केंद्र में भाजपा की सरकार है छत्तीसगढ़ राज्य में चुनाव के समय जनता को ठगने के लिए धान का मूल्य 3100 किया।

24 के लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ भाजपा का घोषणा पत्र बनेगा देश भर में चुनावी मुद्दा: बैज

रायपुर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनावों के लिये भाजपा का घोषणा पत्र को कांग्रेस 24 के लोकसभा चुनाव में देश भर में चुनावी मुद्दा बनायेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि भाजपा के द्वारा विधानसभा चुनाव के लिये बनाये गये मोदी की गारंटी से भाजपा की नीयत पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी केन्द्र में सरकार चला रही है। धान की कीमत 3100 रू. देने का वायदा कर रही तथा 500 रू. में रसोई गैस सिलेंडर देने की वायदा कर रही तथा प्रत्येक महिला को हर महीने 1000 रू. देने की वायदा कर रही तथा अपने वायदों को वह प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी बता रही है। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि मोदी की यह गारंटी पूरे देश के लिये क्यों नहीं है? भारतीय जनता पार्टी देश में सरकार चला रही है। नरेन्द्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है प्रधानमंत्री के रूप में वह जो निर्णय लेंगे वह पूरे देश में लागू होना चाहिये। एक राज्य में धान की कीमत 3100 रू. कैसे हो सकती है। जब पूरे देश के लिये धान का समर्थन मूल्य केन्द्र सरकार ने कम घोषित किया है। जब पूरे देश में रसोई गैस के दाम

1100 रू. के लगभग है तो प्रधानमंत्री एक राज्य में 500 रू. के सिलेंडर की गारंटी कैसे ले सकते है। महंगाई तो पूरे देश में है देश मोदी सरकार के आने के बाद महंगाई बेतहाशा बढ़ी है राहत की इंतजार तो पूरा देश कर रहा है। भाजपा बताये देश के अन्य राज्यों में यह क्यों नहीं लागू होना चाहिये?

बैज ने कहा कि भाजपा चुनाव के पहले जनता को ठगने के लिये चुनावी वायदे करती है तथा चुनाव जीतने के बाद उसको जुमला बता देती है। यह भाजपा का असली चरित्र है। 2014 में भी मोदी ने देश की जनता से 100 दिन में महंगाई कम करने का वायदा किया था। हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की वादा किया था। हर नागरिक के खाते में 15 लाख आने का वादा किया था। किसानों की आय दुगुनी करने का भी वादा था लेकिन 10 साल सरकार बनाने के बाद भी कोई वादा पूरा नहीं हुआ। अब छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने के लिये नये जुमले फेंक कर मोदी की गारंटी बता दिया। लेकिन जनता भाजपा और मोदी दोनो के चरित्र को समझ चुकी है।

सुरंग हादसा : सेना को सलाम
आपदा प्रबंधन में कौशल

अरुणेंद्र नाथ वर्मा

चारधाम यात्रा के लिए बनाए जा रहे राजमार्ग पर सिलक्यारा के निकट भीषण सुरंग दुर्घटना में फंसे 41 मजदूरों के निकलने का इंतजार पूरा देश पिछले 16 दिनों से कर रहा था। उन्हें बचाने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने हर संभव प्रयत्न किया। उसने देश-विदेश के आपदा विशेषज्ञों से सलाह और मदद भी मांगी, ताकि सुरंग में फंसे मजदूरों को निकाला जा सके। इस कठिन काम में बीआरओ, स्वास्थ्य सेवाओं, ओएनजीसी जैसे कई संस्थाओं ने अथक परिश्रम किया, जिससे उन मजदूरों का मनोबल बढ़ा। ध्वस्त सुरंग के अंदर सुराख बनाना सबसे जरूरी काम था, ताकि मजदूरों को राहत पहुंचाने के साथ उन्हें बाहर निकाला जा सके। इसके लिए शक्तिशाली 'ऑगर' मशीन का प्रयोग किया गया, मगर दुर्भाग्यवश इस मशीन के ब्लेड ध्वस्त सुरंग के मलबे में दबी सरिया और चट्टानों से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गए। अंतत: हाथ के औजारों से थोड़ा-थोड़ा मलबा खोदकर निकालते हुए फंसे मजदूरों तक पहुंचने का निर्णय लिया गया। इस धीमी और मुश्किल प्रक्रिया को रैट माइनिंग नाम दिया गया था। इसके अलावा सुरंग के ऊपर से कुएं की खुदाई की तरह सीधे नीचे खोदने के लिए ड्रिलिंग मशीनों का उपयोग किया गया। इस तरीके में भी करीब 40 मीटर तक खुदाई करने के बाद सुरंग को मजबूती देने के लिए बनाए गए सरिया के जाल का अवरोध मिलने की पूरी आशंका थी। इन दोनों तरीकों को समझ लेने के बाद पता चलता है कि अंतिम और बेहद नाजुक दौर में सेना की मदद क्यों ली गई। दुर्गम जगह में खुदाई करने के बाद वेल्डिंग से धातु काटने के कठिन काम को अंजाम देने के लिए स्थल सेना की इंजीनियरिंग कोर की मद्रास सैपर्स इकाई के सैनिकों को लगाने का यही कारण था कि वे दुश्मन द्वारा बिछाई गई विध्वंसक सुरंगों को बेहद सावधानी से साफ करने में माहिर होते हैं। सिलक्यारा की ध्वस्त सुरंग में रैट माइनिंग की प्रक्रिया बेहद खतरनाक थी, क्योंकि वह संकरी सुरंग मलबा गिरने से और अवरुद्ध हो सकती थी। इस काम में हमारे जांबाज सैनिकों से सफलता की पूरी उम्मीद थी। अंतिम चरण के पहले ही इस आपदा में भारतीय वायुसेना बहुत महत्वपूर्ण किरदार अदा कर चुकी थी। जिस दुर्गम क्षेत्र में बॉर्डर रोड जैसी इकाइयों के जेसीबी और सड़क बनाने, चट्टानें काटने के भारी उपकरण हफ्तों या महीनों के परिश्रम से पहुंच पाते हैं, वहां विशालकाय 25-30 टन भारी आगर ड्रिलिंग मशीनों को पहुंचाने का जटिल काम वायुसेना की सहायता के बिना असंभव होता। दुर्घटना स्थल से सबसे निकट की हवाई पट्टी धरासू में थी, जो भारी ट्रांसपोर्ट विमानों के उपयोग योग्य नहीं थी। ऑगर मशीन का भारी बोझ लेकर वायुसेना के सी-17 और सी-130 जे हर्क्यूलिस जैसे विमान वहां उतर सकेंगे या नहीं, इसका आकलन वायुसेना ने आनन-फानन में पूरा किया। इसी वर्ष सूडान में फंसे हुए 121 भारतीयों को बेहद कठिन स्थितियों में निकाल कर वायुसेना सिद्ध कर चुकी है कि उड्डयन कौशल में वे सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के हैं। सूडान में सैय्यदाना की ऊबड़-खाबड़ हवाई पट्टी पर रात में नाइट विजन गोगल्स लगाकर उतरने और टेक ऑफ करने वाले कुशल वैमानिकों के लिए धरासू की हवाई पट्टी भी वैसी ही एक चुनौती थी। और वायुसेना ने सी-17 जैसे भारी विमान के साथ दो सी-130 जे हर्क्यूलिस विमानों को वहां उतार कर अद्भुत प्रदर्शन किया, जहां भारी सामान निकालने के लिए ऑफलोडिंग प्लेटफार्म और उपकरण तक नहीं थे। वायुसेना के हेलिकॉप्टर भी उस क्षेत्र का सर्वेक्षण करने में सहायक सिद्ध हुए। यों तो सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकलने के बाद अस्पताल पहुंचाने के लिए 41 एम्बुलेंस गाड़ियां प्रतीक्षारत थीं, लेकिन जरूरत पड़ने पर वायुसेना के हेलिकॉप्टर भी तुरंत उपलब्ध कराने की तैयारी की गई थी। अब जहां सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों के सकुशल बाहर निकल आने पर एक सौ चालीस करोड़ देशवासियों में खुशी की लहर है, वहीं आपदा प्रबंधन के सबसे महत्वपूर्ण चरण में थलसेना और वायुसेना के साहस, समर्पण और कौशल के प्रति भी उनका विश्वास और मजबूत हुआ है।

चुनावों में मुफ्त रेवड़ियों की बरसात

ललित गर्ग

चुनाव लोकतंत्र की जीवनी शक्ति है, यह राष्ट्रीय चरित्र का प्रतिबिम्ब होता है, लोकतंत्र में स्वस्थ मूल्यों की स्थापना के लिये चुनाव की स्वस्थता एवं उसकी शुद्धि अनिवार्य है। चुनाव की प्रक्रिया गलत एवं मूल्यहीन होने से लोकतंत्र की जड़े तो खोखली होती ही है, राष्ट्र भी मूल्यहीनता की ओर अग्रसर होता है। चरित्र-शुद्धि के अभाव में चुनाव शुद्धि की कल्पना नहीं की जा सकती है। इस बार पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में ऐसा ही देखने को मिल रहा है, रेवड़ी-संस्कृति, लोकलुभावने वायदों और गारंटियों का जो कोलाहल सुना जा रहा है, येन-केन-प्रकारेण चुनाव जीतने की होड़ देखने को मिल रही है, जो कालांतर में देश के सशक्त होने, आर्थिक अनुशासन व योग्य जनप्रतिनिधियों के चयन के लिये एक चुनौती बन सकता है। लगातार चुनावों में मुक्त की रेवड़िया बांटने की परम्परा ने चुनाव प्रक्रिया एवं उसके आदर्श को धुंधलाया है। यह विडंबना है कि लोग जनप्रतिनिधि की योग्यता, कर्मठता, चारित्रिक उज्ज्वता की प्राथमिकता को दरकिनार करके संकीर्ण सोच के लाभों को प्राथमिकता देने लगे हैं। इस दूषित परंपरा से राजनेताओं और जनता का प्रलोभन विस्तार ले रहा है। इस बढ़ती बुराई एवं विकृति को देखकर आंख मूंदना या कानों में अंगुलिया डालना अपनी जिम्मेदारी से पलायन है, इसके विरोध में व्यापक जन-चेतना जगाने की अपेक्षा है। आज चुनाव में बढ़ता भ्रष्टाचार का रावण मानवता एवं चुनाव शुद्धि की सीता का अपहरण करके ले जा रहा है, सब यह अनर्थ होते हुए देख रहे हैं, पर कोई भी जटायु आगे आकर उसका विरोध करने की स्थिति में नहीं हैं। चुनाव-भ्रष्टाचार के प्रति जनता, राजनीतिक दलों एवं नेताओं का यह मौन, यह उपेक्षाभाव उसे बढ़ायेगा नहीं तो और क्या करेगा?

मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में विधानसभा चुनावों के लिए मतदान हो चुका है। अब केवल तेलंगाना में मतदान होना शेष है। इन राज्यों के चुनाव प्रचार के दौरान यह बात और उभरकर सामने आई कि मतदाता राजनीतिक दलों के प्रलोभन का शिकार बनने के लिए तैयार है और राजनीतिक दल एवं उनके उम्मीदवार मतदाताओं को ठगने, लुभाने एवं गुमराह करने की होड़ में लगे हैं। 'गरीब की थाली में पुलाव आ गया है...लगता है शहर में चुनाव आ गया है' भारत की राजनीति एवं चुनावों पर ये दो पंक्तियां सटीक टिप्पणी हैं, जो दु:खद एवं विडम्बनापूर्ण है। आम तौर पर मतदाता राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में यह नहीं देखता कि उसमें अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, रोजगार, नागरिक सुविधाएं, बिजली-पानी आदि के ठोस वादे किए गए हैं या नहीं? वह अब यह देखता है कि किस दल ने उन्हें क्या-क्या मुफ्त वस्तुएं और सुविधाएं देने के वादे किए हैं। वक्त की जरूरत है कि मतदाताओं को लालीपॉप देने, मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के बजाय उन्हें ऐसे अवसर दिये जाने चाहिए ताकि वे कालांतर आत्मनिर्भर बन सकें, सशक्त लोकतंत्र के निर्माण में अपनी सार्थक भूमिका निभा सके, देश के सशक्त आर्थिक विकास में योगभूत बन सके।

भ्रष्ट चुनाव से तो भ्रष्ट नेतृत्व ही मिलेगा, ऐसी भ्रष्ट स्थितियों से देश के आर्थिक विकास में भी भ्रष्टता ही व्यापक होगी, शासन के सामने आर्थिक चुनौतियां खड़ी होंगी। इस तरह मुफ्त की योजनाओं और गारंटियों से सिर्फ हमारा राजकोषीय घाटा ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि भ्रष्टाचार को पनपने का खुला मौका मिलेगा। मतदाता यदि किसी राजनीतिक दल की दूरगामी नीतियों व विकास योजनाओं को नजरअंदाज करके तात्कालिक लाभ को प्राथमिकता देगा तो भविष्य में उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उम्मीदवारों के षड्यंत्र एवं मतदाताओं के लोभ हमारी चुनाव प्रक्रिया को भी संकट में डालते हैं। जाहिर-सी बात है कि मुफ्तखोरी की संस्कृति के बूते सत्ता में आने वाला नेता कालांतर में सरकारी संसाधनों के दोहन को अपनी प्राथमिकता बनायेगा। जो धन उसने चुनाव के दौरान बांटा है उसका कई गुना येन-केन-प्रकारेण वसूलेगा। जिससे लोकतंत्र में लूटतंत्र की मानसिकता को प्रोत्साहन मिल सकता है। चुनाव में मुफ्त रेवड़ी संस्कृति के साथ चुनाव का अधिकाधिक खर्चीला होना भी गंभीर चिन्ता का विषय है। एक-एक प्रत्याशी चुनाव प्रचार करने में करोड़ों रुपए व्यय करता है। यह धन उसे पूंजीपतियों एवं उद्योगपतियों से मिलता है। चुनाव जीतने के बाद वे उद्योगपति उनसे अनेक सुविधाएं जायज-नाजायज तरीकों से प्राप्त करते हैं। इसी कारण सरकार उनके शोषण के विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठा पाती और अनैतिकता एवं भ्रष्टता की परम्परा का सिंचन मिलता है। यथार्थ में देखा जाये तो जनमंत्र अर्थतं. बन कर रह जाता हैं, जिसके पास जितना अधिक पैसा होगा, वह उतने ही अधिक वोट खरीद सकेगा। ऐसे में ईमानदार, योग्य एवं कर्मठ लोगों का राजनीति में आने का रास्ता ही बन्द हो जायेगा। चुनावों में लगातार बढ़ रही भ्रष्टता की नाजुक स्थिति में व्यक्ति-व्यक्ति की जटायुवृत्ति को जगाया जा सके, चुनावी भ्रष्टाचार के विरोध में एक शक्तिशाली समवेत स्वर उठ सके और उस स्वर को स्थायित्व मिल सके तो लोकतंत्र की जड़ों को सिंचन मिल सकता है और ऐसे हालातों में भी हमारा अमृत-काल भी चुनाव-प्रक्रिया के लिये भी अमृतमय बन सकता है।

इस बार पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त पेशकश के मामले में होड़ करके राजनीतिक दल एक दूसरे को मात देने में लगे रहे। चुनाव में रेवड़ियों की इस बारिश के राजनीतिक एवं आर्थिक, दोनों निहितार्थ हैं। साथ ही यह उन राजनीतिक दलों के दोहरे रवैये को भी जाहिर करता है जो मुफ्त पेशकश के मामले में दूसरे दलों को तो आईना दिखाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के लिए खुद उनका सहारा लेने से कोई संकोच नहीं करते। यह दोहरा रवैया भाजपा के चरित्र में भी समाया है। सही मायनों में मुफ्त के उपहारों की हमेशा बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। यह हमारे लोकतंत्र की भी विफलता है कि आजादी के साढ़े सात दशक बाद भी हम अपने लोकतंत्र को इतना सजग व समृद्ध नहीं बना पाये कि मतदाता अपने विवेक से अपना दूरगामी भला-बुरा सोचकर मतदान कर सके। अतीत के अनुभव बताते हैं कि जिस भी राज्य ने मुफ्त खाद्यान्न, पानी, बिजली व सब्सिडी बांटी है उसकी अर्थव्यवस्था भविष्य में चरमराई ही है। सही मायनों में मुफ्त कुछ नहीं होता, वह करदाताओं की पसीने की कमाई से पैदा होता है। देश को कल्याणकारी नीतियों की जरूरत है, लेकिन वह आर्थिक अनुशासन और राजकोषीय विवेक पर आधारित होना चाहिए।

कोई भी दल यह बताने को तैयार नहीं कि वे मुफ्त वस्तुएं जैसे कि स्कूटी, लैपटाप, मोबाइल, सोना, मुफ्त बिजली-पानी-बस यात्रा समेत अन्य वस्तुएं और सुविधाएं देने के जो वादे कर रहे हैं उन्हें पूरा कैसे करेंगे? वास्तव में यह वह सवाल है जो मतदाताओं को करना चाहिए। वह यदि यह सवाल नहीं करता तो इसका कारण लालच और फौरी लाभ ही है। लेकिन मतदाताओं का यह लाभ का दृष्टिकोण समूचे लोकतंत्र के लिये कितना नुकसानदायी है, इस पर चिन्तन करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि रेवड़ियां बांटने का खेल देश में पहले नहीं होता था, लेकिन आज जिस पैमाने पर हो रहा है, वह हर देशभक्त की चिंता का विषय होना चाहिए। कहीं न कहीं, मुफ्त की गारंटियों का यह खेल जवाबदेह प्रशासन व आर्थिक स्थिरता पर कालांतर गहरी चोट करेगा। वहीं ये गतिविधियां एक जिम्मेदार लोकतंत्र पर सवालिया निशान लगाती हैं। यह बड़ा सत्य है कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटने से हमारी अर्थव्यवस्था व विवेकशील सुशासन पर घातक असर पड़ता है। अंतत: रेवड़ी संस्कृति का आर्थिक दबाव सरकारी संसाधनों पर पड़ता है। राज्यों के आर्थिक संसाधन सीमित हैं। ऐसे में बांटा गया धन कालांतर में हमारे बुनियादी ढांचे व विकास परियोजनाओं के लिये निर्धारित धन में कटौती करता है। जिससे समग्र एवं संतुलित विकास का लक्ष्य हासिल नहीं हो पाता। निश्चित रूप से समाज के कमजोर वर्ग को आर्थिक संबल दिया जाना चाहिए। लेकिन मुफ्त रेवड़ियां बांटने से वह अकर्मण्य एवं कामजोर होंगे, जरूरत ठोस आर्थिक विकास व रोजगार के अवसर सृजन की होनी चाहिए।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

यागकुण्डल्युपनिषद् (भाग-12)

गतांक से आगे...

जब जन्म-जन्मान्तरों के पुण्यकर्म उदित होते हैं, तब मानव अपने दोषों को जानने की इच्छा करता है, तब वह सोचता है कि वास्तव में मैं कौन हूँ एवं दोषरूप यह संसार कैसे प्राप्त हुआ है? जाग्रत् एवं स्वप्न अवस्था में तो मैं ही कर्त्ता के रूप में व्यवहार करता हूँ, परन्तु सुषुप्ति अवस्था में मेरी क्या गति होती है? इस तरह चिन्तन करते हुए अपने रूप पर विचार करता रहता है।

जिस प्रकार रुई का ढेर आग पाते ही जल जाता है, उसी प्रकार चिदाभास के प्रभाव से सांसारिक ताप से तापित अज्ञान समाप्त हो जाता है।

इस तरह सांसारिक बोध के समाप्त होने पर प्रत्यगात्मा (शुद्ध आत्मा) प्रकाशित हो जाता है तथा उससे विज्ञान (संसार का विशेष ज्ञान) भी नष्ट हो जाता है। इस तरह क्रमश: मनोमय तथा विज्ञानमय के पूर्णत: नष्ट हो जाने पर घट के भीतर रखे हुए दीपक की तरह अंत:स्थ प्रकाश रूप आत्मा ही अंत:करण में प्रकाशित होता रहता है।

इस प्रकार से नित्य प्रति जो आत्मज्ञानी आत्मा का ध्यान करता है तथा मृत्यु के आने पर भी स्थिर चित्त होकर उस पर ध्यान लगाये रहता है, उसे जीवन (सांसारिकता) से मुक्ति मिल जाती है, वही विज्ञानी है, है और वह कृतकृत्य हो जाता है। जीवन्मुक्त साधक का अन्तिम समय (मृत्यु) आने पर वह (शरीर रहते हुए जीवन्मुक्त एवं शरीर समाप्त होने पर) उसी प्रकार विदेह मुक्त हो जाता है, जिस प्रकार वायु (उन्मुक्त) आकाश में स्पन्दनरहित होकर प्रवेश कर जाती है। जो आदि अंत रहित, नित्य, अव्यय और महान् है तथा जो अटल है एवं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि पंचमहाभूतों से रहित है, वही विकाररहित परमपवित्र ब्रह्म ही अन्त में शेष बचता है, यही उपनिषद् है।

क्रमश: ...

आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक थे जगदीश चंद्र बोस

अनन्या मिश्रा

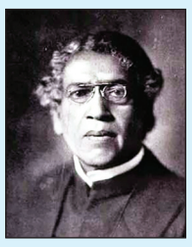

पूर्वी बंगाल के ररौली गांव में 30 नवंबर 1858 को जगदीश चंद्र बोस का जन्म हुआ। उस दौरान देश में अंग्रेजों का शासन था। वहीं उनके पिता भगवान चन्द्र बसु ब्रह्म समाज के नेता और ब्रिटिश शासन में डिप्टी मैजिस्ट्रेट के पद पर थे। बोस ने शुरूआती पढ़ाई गांव से पूरी की। फिर आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने कोलकाता यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और भौतिकी विज्ञान में पढ़ाई की। इसके बाद वह हायर स्टडी के लिए कैब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए, जहां से साल 1884 में ग्रेजुएशन् पूरा किया और भारत वापस लौटे।

देश के महान वैज्ञानिकों में जगदीश चंद्र बोस का नाम शामिल हैं। बोस ना सिर्फ भौतिकी बल्कि जीवविज्ञान में भी पारंगत थे। उन्होंने बताया कि पौधों में जान होती है, उन्हें भी दर्द होता है और पौधों पर भी रोशनी व तापमान का असर होता है। बोस को फादर और रेडियो साइंस के नाम से भी जाना जाता है। बोस ने कॉलेज के एक छोटे से कमरे में रेडियों की तरंगों को खोजा था। जहां पर ना तो कोई उपकरण थे और ना ही प्रयोगशाला था।

भारत आने के बाद जगदीश चंद्र बोस प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिकी के अध्यापक बने। यह उस दौरान की बात है कि ब्रिटिश हुकूमत भारतीयों को इस पद के लिए काबिल नहीं मानती थी। जिसके चलते यूरोपीय प्रोफेसर्स की तुलना में भारतीय प्रोफेसर्स को दो तिहाई वेतन दिया जाता था। लेकिन जगदीश चंद्र बोश अंग्रेजों के इस भेदभाव से परेशान थे, वहीं शिक्षण कार्य के दौरान उन पर भी नस्लीय टिप्पणियां की गईं। जिसके चलते बोस ने साल भर तक सैलरी लेने से इंकार कर दिया। जिसके चलते बोस को आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ा।

वेतन न लेने और आर्थिक तंगी के चलते बोस ने कलकत्ता का मकान छोड़ शहर से दूर जाने का फैसला किया। लेकिन वह वेतन न लेने की बात पर अड़े रहे। जगदीश चंद्र बोस की इस जिद के आगे अंग्रेजों और कॉलेज प्रशासन को उनके सामने झुकना पड़ा। जिसके बाद यूरोपीय प्रोफेसर्स और भारतीय प्रोफेसर्स को समान वेतन दिए जाने की बात की गई। बता दें कि बोस ने फिजिक्स और फिजियोलॉजी दोनों में कई उपलब्धियां अपने नाम की। बोस ने प्रयोगशाला और उपकरणों के बिना एक छोटे से कमरे में तरंगों की विशेषताओं पर शोध करना शुरू किया। हांलाकि पहले उनकी इस खोज को गंभीरता से नहीं लिया गया और उन्होंने भी इस खोज का पेटेंट नहीं कराया। वहीं बोस के खोज करने के करीब 2 साल बाद इटली के वैज्ञानिक मारकोनी ने इसी विषय पर खोज किया। मारकोनी ने इस खोज का पेटेंट भी कराया। जिसके कारण साल 1909 में मारकोनी को उनकी खोज के लिए भोतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला।

पाकिस्तान बना रहा फौजियों को आतंकी

सुशांत सरीन

भारतीय सेना का यह कहना एक वास्तविकता है कि जम्मू-कश्मीर को अशांत करने के लिए पाकिस्तान अपने सैनिकों को आतंकी बनाकर भेज रहा है तथा विदेशी आतंकियों की घुसपैठ कराने का षड्यंत्र भी रच रहा है। साल 2019 से देखा जाये, तो कश्मीर में आतंकी गतिविधियों के लिए स्थानीय युवाओं की भर्ती का सिलसिला बहुत तेजी से कम हुआ है। उससे पहले भी कई सालों से सौ-डेढ़ सौ से अधिक स्थानीय भर्तियों की खबरें नहीं आ रही हैं। इस कारण आतंकी गतिविधियों में भी बड़ी कमी आयी है। इसकी एक वजह यह भी है कि घाटी में प्रशिक्षण करा पाना मुश्किल होता गया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी उनके लिए परेशानी बन गयी है। ऐसी स्थिति में आतंकी कार्रवाइयों के क्षेत्र भी बदले हैं।

घाटी से अधिक घटनाएं राजौरी क्षेत्र में होने लगी हैं। डोडा में भी यह हालत बन सकती है। यह कोई नयी बात नहीं है कि पाकिस्तान अपने सैनिकों को आतंकी हमलों के लिए कश्मीर भेज रहा है। नब्बे के दशक में भी ऐसी घटनाएं हुई थीं। होता यह है कि भारतीय सुरक्षा व्यवस्था एक इलाके में आतंकियों का सफाया करती है, जिससे वहां शांति स्थापित हो जाती है। फिर वहां एक खालीपन बन जाता है, इसे आप चूक कहें या और कुछ, उसका फायदा उठाकर पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान समर्थित आतंकी गिरोह सक्रिय हो जाते हैं।

भले ही घाटी में आतंकी गतिविधियों के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं, पर पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को छोड़ने के लिए राजी नहीं है। ऐसे में उसे अपने सैनिकों को या विदेशी आतंकियों को इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ रही है। जहां तक विदेशी आतंकियों की बात है, तो यह भी नब्बे के दशक में हो चुका है, जब अरबी, अफगानी, सूडानी आदि कश्मीर आते थे। उनकी तादाद कम हुआ करती थी, पर वे आतंकी वारदातों में शामिल होते थे। ये सभी पाकिस्तानी सेना की कुख्यात खुफिया एजेंसी आईएसआई द्वारा संचालित होते थे। पाकिस्तान की नीति और व्यवहार में दोहरा मानदंड हमेशा से रहा है। भारत में कुछ लोग ऐसे हैं, जिनकी सोच है कि अगर पाकिस्तान में नवाज शरीफ के नेतृत्व में अगली सरकार बनती है, तो दोनों देशों के संबंधों में सुधार होने की उम्मीद की जा सकती है।

ऐसी सोच में कोई समझदारी नहीं है। लेकिन असलियत यह है कि पाकिस्तानी सेना की कमान जिन लोगों के हाथों में है, वे खुलेआम कहते रहे हैं कि वे कश्मीर के मुद्दे से पीछे नहीं हटेंगे। नवाज शरीफ और उनकी पार्टी भी कहती रही है कि कश्मीर को उनका समर्थन जारी रहेगा। भले कश्मीरियों को उनके समर्थन की आवश्यकता न हो, पर वे इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं। इसका सीधा मतलब है कि वे घाटी में अलगाववाद और आतंकवाद की आग को भड़काये रखना चाहते हैं। पर भारत में एक खेमा है, जो पाकिस्तान के प्यार में इस तरह पड़ा हुआ है कि उसे यह समझ ही नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान के रवैये में कोई अंतर नहीं आया है।

सो, भारतीय सेना ने जो कहा है, वह मेरी राय में वास्तविकता पर आधारित है। हमें इस ओर भी ध्यान देना होगा कि जिस तरह से हाल में कुछ मुठभेड़ की घटनाएं हुई हैं, जिनमें हमारे कई सैनिक भी शहीद हुए हैं और घायल हुए हैं, उनको देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि घुसपैठ करने वाले मिलिटेंट या आतंकी नहीं हैं, बल्कि पाकिस्तानी सेना के ही लोग हैं। यह कहना मुश्किल है कि ऐसे लोग पाकिस्तानी सेना से सेवानिवृत हो गये हैं या अभी भी सेना में हैं। मुठभेड़ों से संकेत मिलता है कि घुसपैठियों को सैनिक प्रशिक्षण मिला है। आम तौर पर आतंकियों के पास इस तरह का प्रशिक्षण नहीं होता और न ही उनमें ऐसा अनुशासन होता है। इस संबंध में हमें नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले को भी देखना चाहिए, जिसका संचालन भी पाकिस्तानी सेना और आइएसआइ द्वारा होता है।

पंजाब में नशे की गंभीर समस्या पहले से है और अब यह कश्मीर में भी बड़े पैमाने पर फैल रही है। अभी उतनी चर्चा नहीं हो रही है, पर राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी यह समस्या जड़ें जमा रही हैं। सुनने में आ रहा है कि इस बीमारी के गुजरात में भी फैलने के आसार हैं। जहां भी नशीले पदार्थों का मामला होता है, वहां बहुत पैसा भी होता है। आतंकवाद की आड़ में यह धंधा खूब चलाया जाता है। पंजाब में हाल में जो खालिस्तान का हौवा खड़ा करने की कोशिशें हो रही हैं, उसके लिए पैसा नशीले पदार्थों की तस्करी से ही आ रहा है। पंजाब में इस कारोबार का जो नेटवर्क है, उसमें नेता, अफसर, पुलिस के लोग शामिल हैं। ऐसे आरोप भी लगते रहे हैं और कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। यह बहुत गंभीर मसला है, पर दुर्भाग्य से इस पर कोई भी हाथ डालने के लिए तैयार नहीं है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में चुनाव से पहले बड़े-बड़े दावे किये थे, पर सरकार बनने के बाद किसी तरह की ठोस कार्रवाई का कोई संकेत नहीं है। यही बात कश्मीर में हो रही है। आतंकवाद पर नियंत्रण के प्रयासों में तथा पाकिस्तान के इरादों को असफल करने की कोशिशों में नशीले पदार्थों की तस्करी के पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आबादी के एक अहम हिस्से, खासकर युवाओं, को नशे का आदी बनाकर परिवार और समाज को तबाह करना आतंक की रणनीति का ही एक हिस्सा है। और, यह कारोबार आतंकवादी और अलगाववादी गतिविधियों के लिए धन जुटाने में भी सहायक होता है।

दुनियाभर में कई शोध हो चुके हैं, जिनमें रेखांकित किया गया है कि नशीले पदार्थों और आतंकवाद के बीच एक नापाक गठजोड़ बनता है। पंजाब और कश्मीर में ऐसा करने से पाकिस्तान का राजनीतिक उद्देश्य भी पूरा हो जाता है और भारत को कमजोर करने के अपने इरादे में भी कामयाब होते रहते हैं। ऐसी स्थिति में हमें एक पुख्ता रणनीति के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। यह संतोषजनक है कि कुछ घटनाओं को छोड़ दें, तो बीते वर्षों में कश्मीर घाटी में शांति की स्थिति बहुत बेहतर हुई है। खालिस्तान समर्थक तत्वों को भी काबू में करने में कामयाबी मिली है। लेकिन आतंकवाद और अलगाववाद को जड़ से मिटाने में अभी समय लगेगा। इसके लिए सीमा पर चौकसी के साथ देश के भीतर भी निगरानी बढ़ाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और, हमें ऐसे किसी भी भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि पाकिस्तान में सरकार बनने और बदलने से उसके इरादे और पैंतरे में कोई सकारात्मक बदलाव आयेगा।

आज का इतिहास

1939 शीतकालीन युद्ध शुरू हो गया, क्योंकि सोवियत रेड आर्मी ने फिनलैंड (फिनिश सैनिकों का चित्र) पर आक्रमण किया और जल्दी से मैननेरहाइम लाइन के लिए उन्नत किया, एक कार्रवाई जिसे राष्ट्र संघ द्वारा अवैध माना गया।

1942 द्वितीय विश्व-इंपीरियल जापानी नौसेना के युद्धपोतों ने गुआडलकैनाल पर तस्सराफोंगरिया के पास एक रात के नौसैनिक युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य की नौसेना बलों को हराया।

1961 तत्कालीन सोवियत संघ ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिये कुवैत के आवेदन का विरोध किया।

1962 सितंबर 1961 में डाग हम्मार्स्कोल्ड की मृत्यु के बाद बर्मी राजनयिक यू थान्ट संयुक्त राष्ट्र महासचिव बने।

1979 गुलाबी फ्लोयड द्वारा द रॉक, एक रॉक ओपेरा और अवधारणा एल्बम जारी किया गया।

1982 रिचर्ड एटनबरो द्वारा निर्देशित और बेन किंग्सले व जॉन गिल्गुड द्वारा अभिनीत फिल्म गांधी का नई दिल्ली में प्रीमियर हुआ।

1982 माइकल जैक्सन की थ्रिलर, अब तक की सबसे अधिक बिकने वाली एल्बम थी।

1988 मिस्र के विख्यात क़ारी उस्ताद अब्दुल बासित अब्दुस्समद का क़ाहेरा नगर में निधन हुआ।

1993 अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने ब्रैडी हैंडगन हिंसा हिंसा निवारण कानून पर हस्ताक्षर किए, जिसमें हैंडगन के खरीददारों को अबैकग्राउंड चेक पास करने की आवश्यकता थी।

1995 तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति ने उत्तरी आयरलैंड का दौरा किया। वहां का दौरा करने वाले वो पहले अमरीकी राष्ट्रपति थे।

1999 सिएटल में वर्ल्डट्रेड ऑर्गनाइजेशन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ वैश्वीकरण विरोधी कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शनों ने इसके उद्घाटन समारोहों को रद्द कर दिया।

2004 लायन एयर फ्लाइट सुरकरता मध्य जावा, इंडोनेशिया में दुर्घटना से 26 की मौत हुई और 538 घायल हुए।

2005 इराकी विद्रोहियों के खिलाफ एक नया अभियान पश्चिमी इराक में ऑपरेशन आयरन हैमर का संचालन करने वाले संयुक्त अमेरिकी-इराकी सैनिकों के साथ शुरू होता है।

2006 विज्ञान पत्रिका नेचर उच्च संकल्प एक्स-रे टोमोग्राफी के आधार पर एंटीकाइथेरा तंत्र के एक नए पुनर्निर्माण को प्रकाशित करता है। एंटीकाइथेरा तंत्र एक प्राचीन यूनानी यांत्रिक एनालॉग कंप्यूटर है जिसे खगोलीय स्थितियों की गणना करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

किंग नहीं तो किंगमेकर की आस में तेलंगाना भाजपा

समीर चौगांवकर

अपने ही अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। शुरुआत तेलंगाना की सीमा के बाहर आंध्र प्रदेश का हिस्सा हो चुके तिरुपति मंदिर में दर्शन पूजन से की। इससे तेलंगाना के वोटरों पर कितना असर पड़ेगा यह तो समय बतायेगा लेकिन 24 महीने पहले तक खुद को केसीआर की पार्टी बीआरएस का विकल्प मान कर चल रही भाजपा अब कांग्रेस के बाद तीसरे नंबर पर पहुंच गई है और खुद को त्रिकोणीय मुकाबले में तीसरे स्थान पर देख रही है। तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान है और 3 दिसंबर को पांचों राज्यों के चुनाव परिणाम घोषित होगे। भारतीय जनता पार्टी मध्यप्रदेश, राजस्थान में सरकार बनाने को लेकर निश्चिंत है तो छत्तीसगढ़ में किसी चमत्कार की उम्मीद कर रही है। अन्य राज्यों की तरह ही भाजपा तेलंगाना में भी मोदी के नाम और केन्द्र के काम के भरोसे वोट मांग रही है।

बीआरएस और कांग्रेस को पछाड़कर पिछड़ी जातियों के वोट हासिल करने के लिए भाजपा ने तेलंगाना में सत्ता में आने पर पिछड़ी जाति से मुख्यमंत्री देने का वादा किया है। भाजपा को यह रणनीति कारगर लग रही है क्योंकि राज्य में पिछड़ा वर्ग की आबादी 52 फीसदी है और अभी तक इस वर्ग का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठा है। यही कारण है कि भाजपा ने इस वर्ग को 36 टिकट दिए हैं वही बीआरएस ने 23 और कांग्रेस ने भी 23 पिछड़े वर्ग के नेताओं को टिकट दिए हैं।

इसके अलावा भाजपा ने रेड्डी समुदाय के 24, अनुसूचित जाति के 13, अनुसूचित जनजाति के 9 और कम्मा, ब्राह्मण और वेलमा समुदाय के एक-एक व्यक्ति को पार्टी का टिकट दिया है। भाजपा की कोशिश सभी 140 उप जातियों को एक छत के नीचे लाने की है। हालांकि पिछड़े नेता को मुख्यमंत्री बनाने का वादा और सबसे ज्यादा पिछड़े लोगों को टिकट देने का फार्मूला जमीनी स्तर पर बहुत असर करेगा, इसकी संभावना कम लग रही है, क्योंकि भाजपा ने पिछड़ा वर्ग की जाति आधारित गणना कराने का निर्णय नहीं लिया है। भाजपा को इस बात की उम्मीद है कि वह तेलंगाना में किंग नहीं तो किंगमेकर बन सकती है। भाजपा के इस भरोसे के पीछे 15 फीसद वोट शेयर और 12 सीटें जीतने की उम्मीद है।

एक समय ऐसा भी था जब लग रहा था कि भाजपा बीआरएस को बेदखल करके सरकार बना लेगी। वह समय था दिसंबर 2020 का जब ग्रेटर हैदराबाद नगर परिषद चुनाव में भाजपा ने 150 सीटों में से 48 सीटें जीत ली थी और उसके बाद दुब्बाका और हुजूराबाद विधानसभा उप

चुनाव में जीत दर्ज की थी। कार्यकर्ता भी उत्साहित थे लेकिन चुनाव से चार महीने पहले जुलाई 2023 में भाजपा ने तेलंगाना में अपने तेजतर्रार अध्यक्ष बंडी संजय कुमार को हटाकर केन्द्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को राज्य की कमान सौंप दी। किशन रेड्डी मंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष बने रहे और उनकी छवि पार्ट टाइम अध्यक्ष की बन गई।

इसलिए अब तेलंगाना में भाजपा की छवि केसीआर को सत्ता से बेदखल करने वाली पार्टी के बजाय कांग्रेस को सत्ता में आने से रोकने की कोशिश कर रही पार्टी की बनी है। भगवा पार्टी और उसके नेता जानते हैं कि सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के प्रति हमलावर दिखने के बावजूद तेलंगाना के लोग दोनों पार्टियों के बीच किसी मौन समझौते को मान कर चल रहे हैं।

भाजपा का असली गेमप्लान यह है कि विधानसभा चुनाव का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाया जाए जिससे कुछ ही महीनों बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में सांसदों की संख्या 4 से बढ़ाकर 8 तक की जा सके। लोकसभा में अपनी संभावनाओं को मजबूत करने के लिए ही भाजपा ने उम्मीदवारों की घोषणा में जानबूझकर देरी की ताकि बीआरएस और कांग्रेस दोनो के ही असंतुष्ट दिग्गजों को भरपूर मौका दिया जा सके। भाजपा ने अन्य दलों से आए कम से कम 11 पूर्व विधायकों और तीन पूर्व सांसदों को टिकट दिए हैं।

लेकिन कांग्रेस और भाजपा की तमाम कोशिशों के बाद भी 2014 से सत्ता पर काबिज चंद्रशेखर राव को तीसरी बार सत्ता से रोकना आसान नहीं होगा। केसीआर के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की पूरी संभावना लग रही है। इसके कारण भी हैं। केसीआर ने पहले कार्यकाल में सिंचाई और बिजली आपूर्ति पर जोर देने के साथ ही किसानों को सालाना दस हजार रूपये प्रति एकड़ देने की नीति अपनाई। केसीआर की इस योजना ने दक्षिण के इस राज्य को चावल का कटोरा बना दिया। कृषि उपज 1.54 करोड टन से बढ़कर 3.78 करोड टन हो गई। प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 2126 यूनिट है जो राष्ट्रीय औसत 1255 यूनिट से 70 फीसद अधिक है।

केसीआर मतदाताओं को गर्व से यह भी बताते हैं कि तेलंगाना का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2014-15 में पांच लाख करोड़ से 2022-23 में 12.9 लाख करोड़ रूपये हो गया है। राव के पक्ष में यह आंकड़ा भी जाता है कि राज्य की विकास दर औसतन 12.7 फीसद सालाना रही है, जो राष्ट्रीय औसत 10.5 फीसद के इस साल के बजटीय अनुमान से 2.2 फीसद अधिक है। केसीआर इस बात पर भी वोट मांग रहे हैं कि तेलंगाना में प्रति व्यक्ति आय जो 2014 में 1.12 लाख रूपये थी वह बढ़कर 2023 में 3.12 लाख रूपये हो गई।

इन शानदार आंकड़ों के बाद भी केसीआर के लिए यह तीसरा चुनाव जीतना आसान नहीं होगा। 2014 में नए राज्य की सहानुभूति केसीआर के लिए स्वाभाविक मददगार बनी। 2018 में रायतु बंधु योजना ने उन्हे सत्ता में वापसी करा दी। लेकिन इस बार राव के लिए चुनाव आसान नहीं रहने वाला है क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों उन पर भ्रष्टाचार और पेपरलीक के आरोप लगा रहे हैं। केसीआर के खिलाफ एक आम शिकायत यह भी है कि वह किसी की नहीं सुनते और प्रशासन पूरा अपने हाथों में रखते हैं। पार्टी के वरिष्ठ सहयोगियों और मंत्रियों को भी कोई अधिकार नहीं है। केसीआर के बिना बीआरएस संगठन और सरकार में पत्ता भी नहीं हिलता।

परिवारवाद का आरोप भी केसीआर के लिए परेशानी का सबब है। केसीआर खुद मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष हैं। उनके बेटे केटीआर कार्यकारी अध्यक्ष और उद्योग मंत्री है। एक भतीजा टी हरीश राव स्वास्थ्य और वित्त मंत्री है। दूसरा भजीता संतोष कुमार राज्यसभा सांसद है। केसीआर पर परिवारवाद को बढ़ावा देने और सत्ता की मलाई परिवार में ही बांटने का आरोप है।

तमाम आरोपों के बाद भी केसीआर तीसरी बार सरकार बनाने को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। तेलंगाना का यह चुनाव केसीआर बनाम केसीआर है। अगर केसीआर तीसरी बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो ऐसा कारनामा करने वाले वह दक्षिण के पहले नेता होगें क्योंकि अभी तक दक्षिण में कोई नेता लगातार तीन कार्यकाल नहीं ले सका है। केसीआर लगातार तीसरी बार वापसी करेंगे या कांग्रेस केसीआर को बेदखल करेगी या फिर किसी को भी बहुमत न मिलकर त्रिशंकु सरकार बनेगी, यह तो 3 दिसंबर को साफ हो सकेगा। लेकिन इतना साफ है कि जहां केसीआर के लिए यह चुनाव करो या मरो जैसा है, वहीं भाजपा त्रिशंकु विधानसभा की उम्मीद लगाये बैठी है ताकि उसकी प्रासंगिकता प्रदेश में बढ़ जाए।

स्टालिन-अखिलेश की जुगलबंदी के मायने

अंकित सिंह

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री की 15वीं पुण्य तिथि पर चेन्नई के प्रेसीडेंसी कॉलेज परिसर में वीपी सिंह की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया, जिसमें समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव को सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इस कार्यक्रम में वीपी सिंह की पत्नी सीता कुमारी और बेटे अभय सिंह और अजेय प्रताप सिंह भी मौजूद थे। डीएमके द्वारा वीपी सिंह का जश्न मनाना, जिनकी सरकार ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था, को राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले विपक्षी खेमे के बीच पार्टी की स्थिति को मजबूत करने के प्रयास के रूप में देखा जाता है। प्रतिमा का अनावरण करने के बाद,

स्टालिन ने कहा कि वीपी सिंह के जीवन का जश्न मनाना द्रमुक सरकार की जिम्मेदारी थी क्योंकि नेता सामाजिक न्याय के संरक्षक थे जिन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया। उन्होंने जल बंटवारे पर अंतर-राज्य विवादों का निपटारा करने के लिए कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए भी दिवंगत नेता की सराहना की। अखिलेश ने इस पहल के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया और कहा कि यह 2024 से पहले पूरे देश में एक स्पष्ट संदेश देगा। उन्होंने सरकारी संस्थानों के निजीकरण के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने और जाति जनगणना के लिए भी आह्वान किया। इस बीच, स्टालिन ने सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों के बीच एकता का आग्रह किया और ओबीसी और एससी/एसटी के लिए कोटा नीति के उचित कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया। स्टालिन ने कहा कि यदि उत्तर प्रदेश वीपी सिंह का मातृ राज्य था, तो स्टालिन ने कहा, तमिलनाडु उनका पिता राज्य था। इस कार्यक्रम में स्टालिन ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव को बुलाया। लेकिन कांग्रेस से दूरी रखी। हालांकि, कांग्रेस के साथ गठबंधन में रहकर वह तमिलनाडु में सरकार चला रहे हैं। इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके के बीच भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जिस तरह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आमने-सामने है ठीक वैसा ही कांग्रेस और डीएमके के बीच भी है। ऐसे में डीएमके ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की है। इंडिया एलाइंस जोर-जोर से बना था, तीन बड़ी बैठक की भी हुई लेकिन उसके बाद यह ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके भीतर का विरोध तब खुलकर सामने आया जब मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं हो सका और दोनों दल आमने-सामने हो गए। माना जा रहा है कि जल्द ही अखिलेश यादव ममता बनर्जी से भी मिलने वाले हैं। साथ ही साथ वह 3 दिसंबर के बाद बीआरएस प्रमुख चंद्रशेखर राव से भी मुलाकात कर सकते हैं। इन दोनों ही नेताओं से अखिलेश यादव के बेहद ही मजबूत संबंध हैं बीआरएस लगातार एंटी बीजेपी और एंटी कांग्रेस गठबंधन की बात करती रहती है। वहीं ममता भी कांग्रेस के साथ गठबंधन में बहुत सहज दिखाई नहीं दे रही हैं। नीतीश कुमार भी कांग्रेस के रवैया से खुश नहीं हैं और उन्होंने पिछले दिनों सार्वजनिक कार्यक्रम में अपनी नाराजगी व्यक्त कर दी थी। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषण को कामना है की वीपी सिंह की आदमकद प्रतिमा का अनावरण तो महज एक बहाना था, असली निशाना कांग्रेस पर लगाना था। वीपी सिंह क्षेत्रिल दलों के दम पर बनी थी और कांग्रेस इससे दूर रही थी। कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को उतना महत्व देना नहीं चाहती। वहीं, क्षेत्रीय दल जिन राज्यों में उनकी पकड़ मजबूत है वहां कांग्रेस के हिसाब से चलना नहीं चाहते। यही कारण है कि इंडिया गठबंधन में लगातार खटपट की स्थिति दिखाई दे रही है।

योगी फॉर्मूले से जातिगत जनगणना दांव को ध्वस्त करेगी भाजपा

अमित शर्मा

जातिगत जनगणना और जातिगत आरक्षण का दांव चलकर विपक्ष भाजपा को लोकसभा चुनाव 2024 में घेरने की रणनीति बना चुका है। राहुल गांधी, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव और स्टालिन रोज इस मुद्दे को नए-नए तरीके से धार दे रहे हैं। भाजपा योगी फॉर्मूले के सहारे विपक्ष के इस हमले को ध्वस्त करने की तैयारी कर रही है। इसके अंतर्गत जिन ओबीसी-दलित जातियों को अब तक आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है, उन्हें प्राथमिकता के साथ उन्हीं वर्गों की उपश्रेणी में आरक्षण दिलवाना और नई जातियों को भी ओबीसी-दलित जातियों में शामिल करना शामिल है। इसके साथ ही संगठन से लेकर सरकार तक में ओबीसी--दलित जातियों की भागीदारी को और अधिक मजबूत बनाकर उनका सामाजिक सशक्तीकरण करके उन्हें अपने साथ जोड़ने का फॉर्मूला अपनाया जा सकता है। भाजपा ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभार्थी वर्ग बनाकर भी इन वर्गों को अपने से जोड़ने की कोशिश की है। लोकसभा चुनाव के पहले इस रणनीति को और अधिक धार दी जा सकती है। इसके पूर्व योगी आदित्यनाथ सरकार ने इन्हीं वर्गों की उपश्रेणियों का निर्माण कर इन्हें आरक्षण का अधिक लाभ देने की रणनीति अपनाई थी, जिसका विपक्षी दलों की ओर से विरोध हुआ था। योगी आदित्यनाथ सरकार ने आर्थिक-सामाजिक तौर पर पिछड़ी कुछ अन्य नई जातियों को भी इन वर्गों में शामिल करने की रणनीति अपनाई थी। यह मामला अदालत की चौखट तक जा पहुंचा था। लेकिन नए संदर्भों में इस कोशिश को एक बार फिर मजबूती से आजमाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2014 से ही कल्याणकारी योजनाओं की राजनीति की। नरेंद्र मोदी सरकार ने विभिन्न योजनाओं के सहारे हर वर्ग के गरीब वर्गों का कल्याण किया। इससे हर जाति-वर्ग के गरीब भाजपा के साथ जुड़े। विपक्षी दलों ने देख लिया कि यदि इस तरह की गरीब हितैषी राजनीति होती रही, तो उनकी जाति आधारित राजनीति हमेशा-हमेशा के लिए समाप्त हो जायेगी। यही कारण है कि अब नए तरीकों से ओबीसी-दलित वर्गों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। राकेश त्रिपाठी ने कहा कि लेकिन जातिवाद के नाम पर केवल राजनीति कर इन दलों ने अपने चंद परिवारों का भला करने का काम किया है और यह बात जनता ने देख ली है। जनता यह समझ रही है और यही कारण है कि अब अखिलेश यादव जैसे लोगों की जाति के नाम पर समाज को तोड़ने की कोई कोशिश सफल नहीं होगी।

तेलंगाना की सबसे बड़ी लड़ाई, पूरे प्रदेश में जाएगा संदेश

जलज मिश्रा

तेलंगाना में शहरों के मुकाबले चुनावी रंग गांवों में ज्यादा है, लेकिन हैदराबाद कुछ अलग है। पूरे प्रदेश का राजनीतिक संदेश यहीं से जाता है। शहर में दबदबा रखने वाली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 24 सीटों में से नौ पर लड़ रही है। पिछले चुनाव में यहां सात सीटों पर ओवैसी की पार्टी तो 16 पर बीआरएस ने बाजी मारी थी। भाजपा ने प्रदेश में यहीं की सीट गोशामहल से खाता खोला था। कांग्रेस को यहां कोई सीट नहीं मिली थी। ओवैसी का दखल कहीं दिखाई देता है तो यहीं पर। वह बाकी सीटों पर बीआरएस का साथ देने का एलान कर चुके हैं।

पिछले लोकसभा चुनाव में इस क्षेत्र की चार सीटों में से हैदराबाद से एआईएमआईएम के ओवैसी, सिकंदराबाद से भाजपा के जी किशन रेड्डी ने बाजी मारी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी यहां के मल्काजगिरी से सांसद हैं और चिवडला में बीआरएस के रंजीत रेड्डी जीते थे। इन्हीं परिणामों ने अब सभी दलों के मन में उम्मीद बढ़ा दी है। कांग्रेस को लगता है कि वह इस बार यहां खाता जरूर खोलेगी तो भाजपा अपनी संख्या को गोशामहल से आगे बढ़ाना चाहती है। कहा तो यह भी जा रहा है कि ओवैसी अपनी परंपरागत सात सीटों पर ही प्रमुखता से लड़ते हैं। ओवैसी के समर्थकों की मानें तो उनकी सातों सीटों पर कोई टक्कर में नहीं है जबकि स्थानीय जानकारों का कहना है कि इस बार कोई एक या दो सीटें हाथ से जा भी सकती हैं। असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ हैदराबाद को लेकर सभी की उत्सुकता यह है कि बीआरएस को ओवैसी के समर्थन के बावजूद कांग्रेस शहर में खाता खोलने में सफल होगी या नहीं। साथ ही यह कि भाजपा पिछली बार के मुकाबले इस विधानसभा चुनाव में अपनी सीट संख्या बढ़ा पाने में कितनी सफल हो पाती है।

जुबली हिल्स सीट को लेकर कांग्रेस प्रचार कर रही है कि

गोशामहल में प्रत्याशी न उतारने वाले ओवैसी जुबली हिल्स में बीआरएस के प्रत्याशी के सामने भी चुनाव लड़ा रहे हैं। जबकि अन्य सीटों पर उनका बीआरएस को समर्थन है। यहां से कांग्रेस की ओर से पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान और मुरादाबाद के सांसद रहे अजहरुद्दीन मैदान में हैं। बीआरएस के विधायक पी गोपीनाथ फिर से ताल ठोक रहे हैं। एआईएमआईएम ने अपने पार्षद फराज को यहां से उतारा है। इस सीट पर 40 प्रतिशत मुस्लिम हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बीआरएस को जितवाने के लिए ओवैसी ने दूसरा मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है। पिछले चुनाव में ओवैसी की पार्टी का यहां से कोई प्रत्याशी नहीं था। जुबली हिल्स की जनता जागरूक है। वह सारा खेल समझ रही है। कुछ लोग पिछले काफी चुनावों से सिर्फ बांटने की राजनीति कर रहे हैं। इस बार उनका मंसूबा कामयाब नहीं होगा। मुझे खुशी है कि अपनी जनता के बीच इतना प्यार मिल रहा है।

भाजपा के राजा सिंह ने पिछले चुनाव में पूरे प्रदेश में अपनी पार्टी के लिए एकमात्र हैदराबाद की सबसे चर्चित सीट गोशामहल जीती थी। खास बात यह है कि यहां पर एआईएमआईएम का मुख्यालय दारुस्लाम भी है। एआईएमआईएम ने प्रत्याशी नहीं उतारा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी का कहना है कि धर्म पर अनुचित टिप्पणी करने वाले राजा सिंह के सामने ओवैसी प्रत्याशी खड़ा करने की हिम्मत नहीं दिखा पाए। हालांकि करीब 27 फीसदी मुस्लिम वोट यहां जिताने की स्थिति में रहते हैं। दो बार चुनाव जीतने के बाद राजा सिंह यहां से हैट्रिक बनाने की तैयारी में हैं। उनकी विवादित टिप्पणी के बाद हैदराबाद के आसपास काफी बवाल हुआ था और उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। इतना ही नहीं भाजपा ने भी उन्हें निष्कासित कर दिया था। राजा सिंह पर कुछ सालों पहले दो पादरियों की हत्या का भी आरोप लगा था, हालांकि इसमें वह बरी हो गए। कुछ सांप्रदायिक बवालों में राजा सिंह मुखर होने से पहचाने जाने लगे। वह हिंदू वाहिनी के भी सदस्य रहे हैं। उनके सामने बीआरएस के नंद किशोर व्यास उर्फ नंदू बिलाल और कांग्रेस से एडवोकेट सुनीता राव हैं। मुख्य मुकाबला भाजपा और बीआरएस में ही है। एक युवा सोहैल का मानना है कि यहां पर मुस्लिम वोटर बीआरएस के साथ हैं। यहां सहारनपुर के लकड़ी कारोबारियों और राजस्थान से आए व्यापारियों की संख्या अच्छी खासी है। हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले दीपक का कहना है कि यहां का चुनाव तो राजा सिंह के इर्द गिर्द ही घूमता है। एआईएमआईएम के अकबरुद्दीन ओवैसी यहां से मैदान में हैं। यहां ओवैसी परिवार के दबदबे का अंदाजा लगाया जा सकता है। चाय की दुकान पर बैठे शारिक कहते हैं कि यहां आकर चुनाव के नतीजे जानने की जरूरत ही नहीं है। यहां पर कोई टक्कर में दिखता ही नहीं है। 70 प्रतिशत मुस्लिम आबादी वाली इस सीट पर अकबरुद्दीन चार बार विधायक रह चुके हैं। भाजपा के एक प्रत्याशी तो पहले ही पीछे हट चुके हैं। अब महेंद्र भाजपा, नागेश कांग्रेस और एमएस रेड्डी बीआरएस से मैदान में हैं। शाम के समय मंदिर में आरती चल रही है और लोग पास ही विश्व प्रसिद्ध चारमीनार को निहार रहे हैं। एक कारोबारी मो. जाहिद अली का कहना है कि यह ओवैसी की ही सीट है। एआईएमआईएम प्रत्याशी लोगों के बीच सक्रिय भी रहते हैं। उन्हीं के प्रत्याशी जीतते रहे हैं। विधायक मुमताज अली का टिकट काटकर पूर्व मेयर मीर जुल्फिकार अली को ओवैसी लड़ा रहे हैं।

विधानसभा चुनावों में खराब विचारों की वापसी

शेखर गुप्ता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका दल मौजूदा विधानसभा चुनावों में उन बड़े विचारों का इस्तेमाल नहीं कर रहे जिन्हें वे आमतौर पर प्रयोग में लाते है। तकरीबन एक चौथाई सदी से हमारे राजनीतिक चक्र में एक खास रुझान देखने को मिल रहा है जहां तीन प्रमुख राज्यों में आम चुनाव से करीब छह महीने पहले चुनाव होते हैं। इन चुनावों को बड़े फाइनल के पहले सेमीफाइनल कहना लुभावना हो सकता है लेकिन यह गलत भी है। हम 2003 से ही जानते हैं कि ये चुनाव आम चुनाव के बारे में बहुत भ्रामक तस्वीर पेश करते हैं। हालांकि इन चुनावों में आपका सामना उन बड़े विचारों से हो सकता है जो आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं। हालांकि वर्तमान चुनावी मौसम में छोटे विचारों की वापसी हुई है। खासकर पहले देखे जा चुके विचारों जैसे बुरे विचारों की। कुछ विचार तो ज्यादा ही बुरे हैं।

अगर आम चुनावों में यही हमारी राजनीति को परिभाषित करेंगे तो भविष्य निराशाजनक है। मोटे तौर पर एक तरफ बुरे विचार हैं सब्सिडी और मुफ्त उपहार देना तथा दूसरी ओर जाति जनगणना तथा आरक्षण में इजाफा। मैं मानता हूं कि एक मतदाता के लिए जो निःशुल्क उपहार है वह दूसरे के लिए सशक्तीकरण का उपाय हो सकता है। परंतु हमारी नजर में सशक्तीकरण का सबसे बड़ा माध्यम आर्थिक वृद्धि और साहसी सुधार हैं। उसके लिए एक किस्म के धैर्य की जरूरत है जो वर्तमान की हड़बड़ी भरी राजनीति में नहीं नजर आता। महज 15 वर्ष पहले हम दो दशकों की धर्म और जाति की मुश्किलों वाली राजनीति के बाद आकांक्षी मतदाताओं की सराहना कर रहे थे। धर्म की राजनीति ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की मत हिस्सेदारी बढ़ाई जबकि जाति की राजनीति ने हिंदी क्षेत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को मदद पहुंचाई। हमने इस तथ्य को सराहा कि 2009 से भारतीय मतदाताओं खासकर युवाओं ने बेहतर भविष्य के लिए मतदान किया। उम्मीद की राजनीति, बदले की राजनीति पर भारी पड़ रही थी और इसका जश्न मनाना उचित ही था।

भारतीय राजनीति में यह स्थापित तथ्य है कि दबदबे वाले नेता ही अपने दौर के मुद्दे तय करते हैं और बाकी नेता उनका प्रतिकार करते हैं। भारत इस मायने में एक विशिष्ट लोकतांत्रिक देश है कि यह हमेशा एकध्रुवीय रहता है। एक दबदबे वाला दल होता है और बाकी सब उससे जूझ रहे होते हैं। पहले चुनाव के करीब 60 वर्ष बाद तक हम कांग्रेस के नेतृत्व वाली एकध्रुवीय व्यवस्था में जीते रहे। बाकी सारी राजनीति कांग्रेस या गांधी परिवार के विरोध में रहती। उस समय कई बार समाजवादियों, हिंदी प्रदेश के दलों और भाजपा के मातृ संगठन भारतीय जन संघ का विपक्ष पर दबदबा था। परंतु वे कभी कांग्रेस या गांधी परिवार के खिलाफ बड़ा विचार तैयार नहीं कर पाए। यानी वे वैचारिक स्तर पर दूसरा ध्रुव नहीं तैयार कर सके। तब भी नहीं जब 1977 में जनता पार्टी के रूप में एक दल के रूप में एकत्रित हुए। यह अवधि 2013 में नरेंद्र मोदी के उभार के साथ समाप्त हुई। तब से अब तक हम अपने दूसरे एकध्रुवीय दौर में प्रवेश कर गए हैं और वह है मोदी की भाजपा का। वह जिस तरह अपनी राजनीति और अपनी नीतियों को परिभाषित करते हैं, उससे उन्हें चुनौती देने वालों को

अपना प्रतिवाद तैयार करना होता है। हां चूंकि वे एक स्पष्ट परिभाषित विचारधारा से आते हैं इसलिए प्रतिद्वंद्वियों को प्रतिकिया देने में मदद मिलती है। संभव है उनके बीच बहुत अधिक वैचारिक या राजनीतिक समन्वय न हो लेकिन वे एक मुद्दे पर साझा स्वर में बोलते हैं- धर्मनिरपेक्षता की उनकी परिभाषा बनाम भाजपा का हिंदुत्व। हालांकि बाद में उनमें से कई ऐसा करने से हिचकने लगे। हिंदू मतदाताओं के अलग-थलग हो जाने का डर साफ है और उसे समझा भी जा सकता है। आप मोदी को वोट देते हों या नहीं लेकिन यह तो मानेंगे कि वह अपना मंच खुद तैयार करते हैं। वह एक बड़ा मुद्दा तय करते हैं जो आगे की लड़ाई को निर्धारित करता है। क्या उन्होंने हालिया चुनावों में ऐसा कुछ किया है? तथ्य यह है कि वह और उनकी पार्टी जिन तीन चीजों के बारे में बात कर रही है वह हैं निःशुल्क उपहार (जिसमें सब्सिडी और बाजार को नुकसान पहुंचाने वाले हस्तक्षेप शामिल हैं), जाति और धर्म आधारित मुद्दे हैं। जिन पांच राज्यों में चुनाव हो रहा है वहां मुख्यतया कांग्रेस से ही लड़ाई है। वह तीन राज्यों में से पहले दो में इन्हीं बड़े मुद्दों पर बातचीत कर रही है। धर्म काफी हद तक भाजपा का चुनावी एजेंडा है और उसके सभी प्रचार अभियानों में नजर आता है। जाति के मोर्चे पर उसकी प्रारंभिक प्रतिक्रिया थी जाति सर्वेक्षण प्रकाशित करने के लिए बिहार सरकार की निंदा करना। राहुल गांधी इस मुद्दे पर आबादी के मुताबिक पिछड़ा वर्ग के आनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात कह रहे हैं। चुनाव के पहले 2 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में 19,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की घोषणा करते हुए मोदी ने कहा, 'विपक्ष ने अपने समय में गरीबों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया तथा वे अभी भी वही कर रहे हैं। उस समय उन्होंने लोगों को जाति के नाम पर बांटा और आज भी वे यही कर रहे हैं।' परंतु तेलंगाना में उन्होंने जाति को लेकर अच्छा माहौल बनाया, खासतौर पर मडिगाज को लेकर जो दलितों में सबसे बड़ा समूह है और तेलंगाना के मतदाताओं में 16 फीसदी का हिस्सेदार है। व्यापक तौर पर यह माना जाता है कि तेलंगाना के दलितों में दूसरा बड़ा समूह-माला कहीं अधिक बड़ा लाभार्थी है।

प्रभावी रूप से देखें तो वह ऐसा वादा कर रहे हैं जो जाति केंद्रित दलों से अलग नहीं है- आबादी के अनुपात में लाभ की हिस्सेदारी। राजस्थान में अपने प्रचार अभियान में उन्होंने गुर्जर मतदाताओं को याद दिलाया कि कैसे उनके नेताओं मसलन पायलट परिवार के साथ कांग्रेस ने 'बुरा व्यवहार' किया। उपहारों आदि को लेकर उनके रुख में आया बदलाव सबसे उल्लेखनीय है। उन्होंने16 जुलाई, 2022 को ऐसी घोषणाओं को रेवड़ी कहा था। इस वर्ष अप्रैल के बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से रेवड़ी शब्द नहीं दोहराया है। खुद उनकी पार्टी की राजनीति पूरी तरह बदली हुई है और उनकी सरकार सब्सिडी पर 'भारत ब्रांड' आटा बेच रही है। शायद कर्नाटक की चुनावी हार के बाद लगे झटके ने उन्हें और उनकी पार्टी को हिला दिया। हमारी राजनीति में यह एक चिरपरिचित तरीका है जहां हारने वाला अपने भीतर झांकने के बजाय बाहरी कारणों पर दोषारोपण करना चाहता है। यदि ऐसा न होता तो भाजपा को पता होता कि वह अपने मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई के खराब शासन की कीमत चुका रही है। उलटे उसने हार के लिए कांग्रेस की मुफ्त घोषणाओं, उसकी पांच गारंटियों को वजह ठहराया। प्रधानमंत्री की ओर से रेवड़ी संस्कृति के भाषणों के कुछ महीने के भीतर भाजपा ने चुनावी राज्यों में इसी आधार पर रणनीति तैयार कर ली। भाजपा ने राजस्थान के प्रचार अभियान में एक पोस्टर का इस्तेमाल किया जिस पर लिखा था- 'मोदी की गारंटी'। इसमें 20 वादे किए गए हैं जिनमें युवतियों के लिए दो लाख रुपये की बॉन्ड जमा राशि और मुफ्त स्कूटी देने के अलावा गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बोनस तथा गरीब विद्यार्थियों को परिधान खरीदने के लिए 1,200 रुपये हर वर्ष देने की बात कही गई है। मध्य प्रदेश में उनकी पार्टी ने पहले ही कांग्रेस की ओर से महिलाओं को आर्थिक मदद देने की योजना को पूरी तरह अपना लिया है। कांग्रेस ने तो मध्य प्रदेश की आईपीएल टीम बनाने को भी चुनाव घोषणा पत्र का हिस्सा बना दिया है। संभव है कि भाजपा आगामी विधानसभा चुनावों और फिर लोकसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन करे लेकिन यह पहला अवसर है जब उसने चुनाव प्रचार का अपना जांचा-परखा और सफल तरीका विपक्ष के कारण बदला है।

अगले साल इन राशियों पर रहेगी शनि की साढ़े साती और ढैय्या, बढ़ सकती हैं समस्याएं

वर्ष 2024 में शनिदेव कुंभ राशि में ही विराजमान रहेंगे. इसके कारण मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों पर शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव रहेगा. शनिदेव की साढ़ेसाती के तीन चरण होते हैं. अगले वर्ष मकर राशि पर साढ़ेसाती का तीसरा चरण शुरू होगा जबकि मीन राशि पर पहला चरण शुरू होगा और कुंभ राशि पर दूसरा चरण. साढ़ेसाती का दूसरा चरण सबसे कष्ट देने वाला होता है इसलिए कुंभ राशि के जातकों को विशेष सावधानी रखनी होगी.

इन राशियों पर रहेगी शनि की ढैय्या

वर्ष 2024 में शनिदेव के कुंभ राशि में विराजमान होने के कारण वृश्चिक और कर्क राशि वालों पर ढैय्या का प्रभाव रहेगा. शनिदेव की ढैय्या का प्रभाव ढाई साल तक रहता है. वर्ष 2024 में वृश्चिक और कर्क राशि के जातकों को बहुत संभल कर रहने की जरूरत है. खासकर वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है.

शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या से बचाव

वर्ष 2024 में जिन राशियों पर शनिदेव के प्रभाव के कारण साढ़ेसाती और ढैय्या का असर होगा उन्हें इससे बचने के लिए खास उपाय करने चाहिए. साढ़ेसाती और ढैय्या का प्रभाव कम करने के लिए हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा और शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं. इसके साथ ही जरूरतमंदों को दान देने और बुजुर्गों और महिलाओं के सम्मान का ख्याल रखने से साढ़ेसाती और ढैय्या के कष्टों से राहत मिल सकती है.

राहु की महादशा का 18 साल तक रहता है प्रभाव, इन उपायों से दूर होगा कष्ट

ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ग्रहों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव होता है। हमारे जीवन में किसी न किसी ग्रह की अंतर्दशा और महादशा चलती रहती है। वहीं उसका असर भी हमारे जीवन पर कभी सकारात्मक तो कभी नकारात्मक रूप से पड़ता है। बता दें कि राहु-केतु ग्रह की महादशा होने पर व्यक्ति के जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आती है। किसी भी जातक पर 18 साल तक राहु की महादशा चलती है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु शुभ होता है, तो राहु महादशा के दौरान व्यक्ति को मान-सम्मान, पैसा खूब मिलता है। वहीं राहु के अशुभ होने पर व्यक्ति को धन हानि और बीमारियां घेरे रहती हैं। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि राहु की महादशा का जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है और इसका क्या फल होता है।

राहु देता है प्रखर बुद्धि

अगर किसी जातक की कुंडली में राहु शुभ स्थिति में होता है, तो वह व्यक्ति तेज बुद्धि का मालिक होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि के बल पर खूब पैसा और नाम कमाता है। ऐसे व्यक्ति की राहु किस्मत चमका देता है। वहीं जब किसी जातक की कुंडली में राहु अशुभ स्थिति में होता है, तो ऐसा व्यक्ति धोखेबाज और झूठा होता है। इस तरह के व्यक्ति से सब दूर रहना पसंद करता है।

राहु की महादशा का शुभ प्रभाव

बता दें कि जिन जातकों की कुंडली में राहु शुभ स्थिति में होता है, वह व्यक्ति आकर्षक और सुंदर होता है। ऐसा व्यक्ति समाज में लोकप्रिय होता है और उसकी तरफ लोग जल्द आकर्षित होते हैं। राहु की स्थिति शुभ होने पर व्यक्ति समाज में प्रभावशाली स्थान पाने के साथ ही मान-सम्?मान, ऊंचा पद और पैसा पाता है। वहीं राहु की महादशी राजनीति में सक्रिय लोगों को बहुत लाभ देती है। राजनीति में सक्रिय लोगों को राहु की महादशा पद-प्रतिष्ठा और यश दिलाता है।

राहु की महादशा का अशुभ प्रभाव

वहीं जिन लोगों की कुंडली में राहु अशुभ स्थिति में होता है। तो ऐसे व्यक्ति को अशुभ फल मिलता है। ऐसा व्यक्ति गलत रास्तों पर चलता है, वह छल-कपट से पैसे कमाता है और नशे व नॉनवेज का लती होता है। ऐसा व्यक्ति भगवान में भरोसा नहीं करता है। उसको कई तरह की बीमारियां घेरे रहती हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में राहु की स्थिति अशुभ होती है, वह व्यक्ति पागल भी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को हिचकी, आंतों की समस्या, मानसिक अस्थिरता, अल्सर और गैस्ट्रिक की समस्या हो सकती है।

अशुभ राहु की महादशा के उपाय

- यदि कुंडली में राहु अशुभ स्थिति में होता है तो महादशा के दौरान भगवान भोलेनाथ और भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इससे व्यक्ति के कष्ट कम होते हैं।
- इसके अलावा बुधवार के दिन काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाना चाहिए। इससे राहु दोष शांत होता है।
- अगर आप राहु की अशुभ स्थिति से परेशान हैं, तो आपको रोजाना नहाने के पानी में काले तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे आपको राहत मिलेगी।
- वहीं रोजाना राहु ग्रह के मंत्र *ऊँ रां राहवे नमः* मंत्र का जाप करना चाहिए।

इन आसान तरीकों से आप भी साफ कर सकते हैं अपना 'औरा', जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

अक्सर हम सभी बार-बार बीमार पड़ते हैं। जल्दी-जल्दी बातों पर चिढ़ने लगते हैं और शरीर व मन अंदर से थका-थका महसूस होता है। ऐसे में आप कुछ भी करें, लेकिन आप हमेशा परेशानियों से घिरे रहते हैं। अगर आपके साथ भी यह सारे लक्षण होते हैं, तो इसका साफ मतलब है कि आपका 'औरा' साफ नहीं है। ऐसे में आपको जल्द से जल्द अपने 'औरा' को साफ करने की जरूरत है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि 'औरा' क्या होता है।

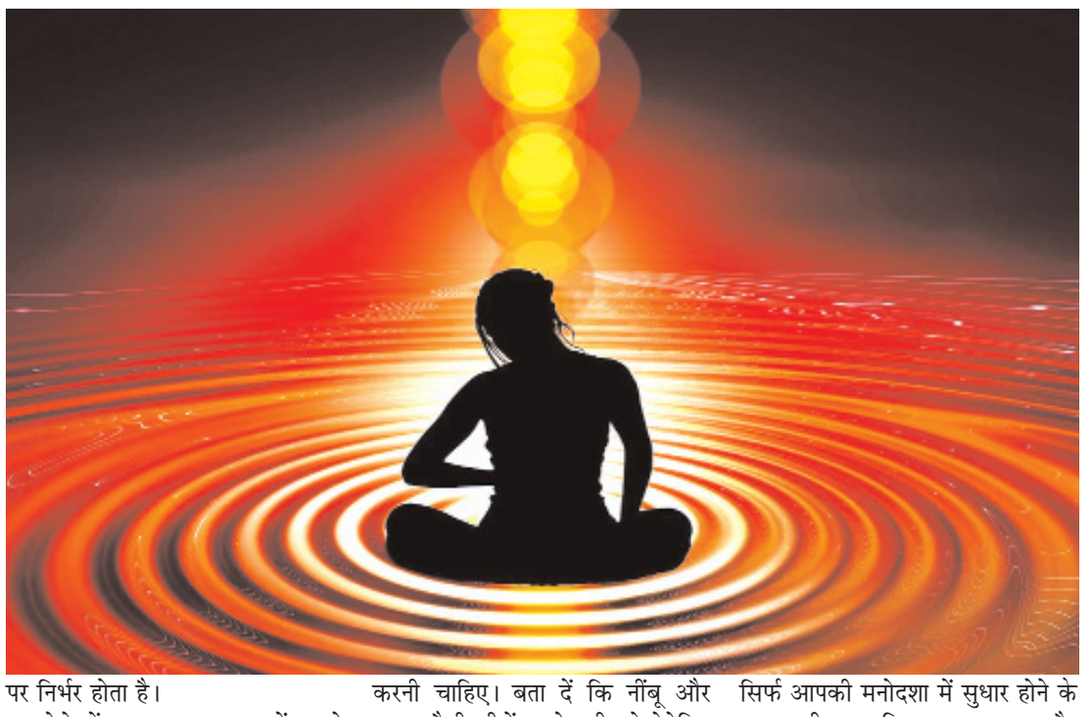

आपको बता दें कि वास्तु एक्सपर्ट के मुताबिक औरा यानी कि आभा, आपकी ऊर्जा का वह क्षेत्र है, जो आपके शरीर को घेरे रहती है। आपकी आभा आसपास घटने वाली स्थिति-परिस्थिति को ग्रहण करती है। जब आप अपने आसपास के लोगों के साथ ऊर्जा का आदान-प्रदान करते हैं, तो आपका औरा यानी की आभा स्ट्रेस का अनुभव करती है। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप किसी से मिलते हैं, तो आपको अन्य लोगों के मुकाबले की उसका व्यक्तित्व आकर्षक लगता है। तो वहीं कुछ लोगों से मिलने पर हमें निगेटिविटी का एहसास होता है। यह हमारे 'औरा' पर निर्भर होता है।

ऐसे में समय-समय पर हमें अपने ऑरिक क्षेत्र को साफ करने की जरूरत होती है। अगर आपको भी ऊपर बताए गए लक्षणों का अनुभव होता है, तो आपको अपने मन और शरीर को पूरी तरह से साफ करने की जरूरत होती है। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अपने 'औरा' को कैसे साफ कर सकते हैं।

ऐसे करें दिन की शुरूआत

सुबह उठने के साथ ही आपको अपने दिन की शुरूआत नींबू पानी से करनी चाहिए। बता दें कि नींबू और नमक जैसी चीजें हमारे शरीर से नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालने का काम करती है। नींबू पानी के सेवन से आपके शरीर से गंदगी, निगेटिविटी और टॉक्सिन बाहर निकल जाती है। साथ ही यह हमारे शरीर को कई तरह से लाभ पहुंचाता है।

प्रकृति के साथ बिताएं कुछ समय

हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर प्रकृति काफी गहरा असर डालती है। प्रकृति आपके मूड को बेहतर बनाता है। प्रकृति के साथ समय बिताने पर आपको पूरा दिन के लिए ऊर्जा मिलती है। इससे न सिर्फ आपकी मनोदशा में सुधार होने के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण भी बेहतर होता है। ऐसे में प्रयास करें कि रोजाना सुबह कम से कम एक घंटा प्रकृति के साथ समय बिताएं और धूप में बैठें।

सुने सूदिंग साउंड

हमारे इमोशनल हेल्थ, परफॉर्मेंस और नींद के लिए म्यूजिक एक अविश्वसनीय इलाज है। पुराने समय में यह हीलिंग थेरेपी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। म्यूजिक हमारे शरीर और दिमाग दोनों पर शक्तिशाली और विविध प्रभाव डालने का काम करता है। इसके अलावा यह हार्ट रेट और ब्रीदिंग को प्रभावित करता है। संगीत हमारे हार्मोन को रिलीज करने के साथ ही इम्यून सिस्टम को उत्तेजित करता है।

मेडिटेशन करें

मेडिटेशन हमारी हेल्थ के लिए काफी अच्छा माना जाता है। मेडिटेशन करने से नेगेटिव इमोशन्स कम होता है। रोजाना मेडिटेशन करने से आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है। इससे आपको तनाव और चिंता से राहत मिलती है और आप रिलैक्स फील करते हैं। इसलिए रोजाना सप्ताह में कम से कम 5 बार रोज सुबह-शाम 15-15 मिनट के लिए मेडिटेशन करें।

सूदिंग बाथ

नहाने के बाद हम सभी तरोताजगी महसूस करते हैं। ऐसे में आप सूदिंग बाथ लेकर भी अपने %औरा% को साफ कर सकते हैं। सूदिंग बाथ ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें आप एसेंशियल ऑयल, सॉल्ट्स और कुछ हर्ब्स के साथ एक बाथ लिया जाता है। जो आपको अंदर से रिलैक्सिंग फील करवाता है। सूदिंग बाथ लेने के लिए आप सबसे पहले एक बाथटब को भर लें और फिर उसमें यूकेलिप्टस और लैवेंडर ऑयल डाल लें। फिर उस बाथटब में रोज पेटल हिमालयन सॉल्ट डाल दें। फिर इसमें करीब 10 मिनट तक बैठें। इससे न सिर्फ आपका मन हल्का होगा, बल्कि आपकी आभा भी साफ होगी।

सुबह-शाम जरूर करना चाहिए इन मंत्रों का जाप, जीवन में बनी रहेगी सुख-शांति

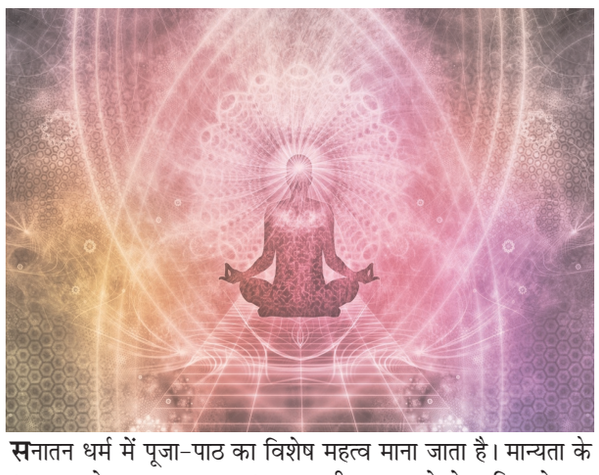

सनातन धर्म में पूजा-पाठ का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता के अनुसार, रोजाना सुबह-शाम भगवान की पूजा करने से व्यक्ति को शुभ फल की प्राप्ति होती है और घर में सुख-शांति का वास होता है। वहीं ईश्वर की पूजा से पूरा दिन अच्छा बीतता है और सभी काम बनते हैं।

सुबह के अलावा शाम को भी पूजा किए जाने का विधान है। इससे व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इसलिए माना जाता है कि सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और रात को जल्दी सोना चाहिए।

इसके साथ ही सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक के बीच में हमारे द्वारा किए गए कार्यों का भी हमारे जीवन पर अधिक प्रभाव पड़ता है। ऐसे में अगर आप अपने दिन को सकारात्मक और शुभ बनाना चाहते हैं, तो आपको सुबह-शाम पूजा के अलावा कुछ मंत्रों का जाप करना चाहिए।

इन मंत्रों के जाप से जीवन में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होता है और सुख-समृद्धि का वास होता है। ऐसे में इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि किन मंत्रों का जाप करना हमारे लिए शुभ होता है।

1. कराग्रे वसते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती।

करमूले तु गोविन्दः प्रभाते करदर्शनम॥

बता दें कि व्यक्ति के हथेलियों में भगवान श्रीहरि विष्णु, माता लक्ष्मी और मां सरस्वती का वास माना जाता है। इसलिए सुबह सोकर उठने के साथ ही अपनी हथेलियों को देखते हुए ऊपर बताए गए मंत्र का जाप करना चाहिए।

2.गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वति।

नर्मदे सिन्धु कावेरी जलऽस्मिन्सन्निधिं कुरु॥

नहाने से हमारे शरीर की सफाई होने के साथ ही नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। ऐसे में अगर स्नान के दौरान आप इस मंत्र का जाप करते हैं, तो इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है।

3.ऊं सूर्याय नमः।

हिंदू धर्म में सूर्य देव को प्रत्यक्ष ईश्वर का दर्जा दिया गया है। ऐसे में स्नान आदि कर सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना चाहिए। इस दौरान ऊपर दिए गए सूर्य देव के मंत्र का 11 बार जाप करना होगा। ऐसा करने से न सिर्फ आपके कार्य बनेंगे, बल्कि आप खुद को ऊर्जावान भी महसूस करेंगे।

4. सह नाववतु। सह नौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै।

तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।। ऊं शान्तिः शान्तिः शान्तिः।।

हम सभी को भोजन करने से पहले ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। इसके लिए आप ऊपर दिए गए मंत्र का जाप कर अन्न प्रदान करने के लिए ईश्वर के प्रति धन्यवाद जता सकते हैं।

5.जले रक्षतु वाराहः स्थले रक्षतु वामनः।

अटव्यां नारसिंहश्च सर्वतः पातु केशवः।।

रात में सोने से पहले जो व्यक्ति इस मंत्र का जाप करता है, उसे शुभ फल की प्राप्ति होती है और जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है।

वास्तु के अनुसार, इस दिशा में सिर रखने से आती है अच्छी नींद

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर को सजाने से देवता प्रसन्न होते हैं और घर पर किसी तरह का कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। वास्तु घर की सजावट में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।

अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से सुकून और आराम की तलाश में हम सभी अपने अपने घरों का रुख करते हैं। ऐसे में घर यदि वास्तु शास्त्र के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। इससे हमारा मन शांत रहता है और नए नए कार्य को करने के लिए प्रेरित होता है।

वास्तु घर की सजावट में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इससे घर की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर को सजाने से देवता प्रसन्न होते हैं और घर पर किसी तरह का कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। आज हम कुछ आसान से वास्तु उपाय बताने जा रहे हैं

1. बेडरूम में मेन गेट की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। सोते वक्त कभी -भी पूर्व दिशा में सिर और पश्चिम दिशा में पैर करके सोने से मन आध्यात्मिक भावनाओं की वृद्धि होती है।
2. किसी भी व्यक्ति को दक्षिण दिशा की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए। इससे बेचैनी, घबराहट जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है।
3. घर के कमरों में कांटे वाली गुलदस्ते नहीं रखनी चाहिए।
4. घर के उत्तर दिशा में जिसे ईशान कोण भी कहते हैं हल्के वस्तुएं रखनी चाहिए।
5. घर में अग्नि से जुड़ा हुआ कोई भी उपकरण दक्षिण- पूर्व दिशा में रखना चाहिए।
6. घर में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक आइटम को का उचित रखरखाव करना चाहिए।
7. घर में यदि पौधे लगे हुए हैं तो उनमें रोजाना पानी देना चाहिए। ताकि पौधा सूखने न पाए।
8. दक्षिण पश्चिम दिशा में ओवरहेड वॉटर टैंक की व्यवस्था करने से काफी शुभ माना जाता है।

रंगों की खुशबू से महक उठेगा घर परिवार

वास्तु शास्त्र के अनुसार किसी घर को बनाने से उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। इसी तरह, घर की बाहरी दीवारों के लिए कुछ वास्तु रंग बताए गए है। जो उस घर में रहने वाले लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। आज हम ऐसे ही कुछ रंगों के बारे में बताने जा रहे हैं। जिन्हें घर की बाहरी दीवारों पर लगाने से उस घर की रौनक और बढ़ जाती है।

1. नीला रंग

यदि घर की बाहरी दीवार को नीले रंग से रंग दिया जाए तो इससे घर की सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। हमेशा घर की बाहरी दीवार के लिए हल्का नीला रंग चुनें। हालांकि यह रंग घर के अंदर नहीं करना चाहिए। लेकिन इसे बाहर के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। यह ब्रह्मांड से एनर्जी को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है और अपने दोस्तों को हमेशा के लिए अपनी तरफ रख सकता है।

2. हरा

घर की बाहरी दीवार पर वास्तु के अनुसार हरा रंग करना शुभ होता है। हरा आराम, प्रकृति और विकास का दर्शाता है। यह एक ऐसा रंग है जो कपल्स के बीच रोमांस को भी बढ़ा सकता है। घर के लिए वास्तु के अनुसार हरा रंग आपके घर में पॉजिटिविटी लाएगा और दूसरे रंगों की तुलना में बहुत साफ दिखेगा।

3. पीला

वास्तु के अनुसार घर की बाहरी दीवार का रंग करने से पॉजिटिविटी बनी रहती है। घर के अंदर रहने वाले लोगों के जीवन में पीला रंग बहुत उम्मीद और खुशी ला सकता है। यह शक्ति का रंग है, इसलिए ऑफिस में तरक्की पाने की इच्छा रखने वाले लोगों को अपने घर को पीले रंग से रंगना चाहिए।

4. सफेद रंग

सफेद रंग शांति का प्रतीक माना जाता है। अगर आप अपने घर या ऑफिस में किसी भी तरह के वाद-विवाद से बचना चाहते हैं, तो बाहरी हिस्से को सफेद रंग से रंगना सबसे अच्छा विकल्प है। ऐसा करने से न केवल आपके घर से निगेटिव एनर्जी दूर रहेगी। इसके अलावा, सफेद रंग हमेशा से फैशन में है और अधिक से अधिक लोगों उसे देखना पसंद करते हैं।

5. ऑरेंज

यदि आप घर की बाहरी दीवारों के लिए सबसे अच्छे वास्तु रंगों में से एक चुनना चाहते हैं, तो ऑरेंज कलर आपको निराश नहीं करेगा। न केवल चमकीले रंग बहुत अच्छे लगते हैं बल्कि यह आपके घर में गर्मी और खुशी भी लाता है।

6. बैंगनी

वास्तु के अनुसार घर के लिए, बैंगनी रंग समृद्धि और गरिमा का प्रतीक है। इस रंग का रॉयल्टी, विलासिता को दर्शाता है। अपने घर को बैंगनी रंग से रंगना आपको सबसे अलग बना सकता है और निश्चित कर सकता है कि आपके मेहमानों को वह शाही ठाठ -बाट मिलेगा जिसके वह हकदार हैं।

7. भूरा

वास्तु के अनुसार घर की बाहरी दीवार का रंग ब्राउन रहे, तो ब्राउन बेज कलर के साथ जाना आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। यह एक भारी रंग है जो रिश्तों के लिए स्थिरता और स्थायित्व का प्रतीक है। ज्यादातर लाइब्रेरी और घर की बाहरी दीवारों के लिए लोग इसे चुनते हैं।

8. गुलाबी

नफरत से भरी दुनिया में, आपके पास एक ऐसा घर हो सकता है जो आपके जीवन में प्यार के एक खंम्भे की तरह हर वक्त मौजूद रहे।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

अगले 5 वर्षों तक 81 करोड़ लोगों को मिलेगा मुफ्त खाद्यान्न

नईदिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार को 81 करोड़ गरीबों को प्रति माह 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया। इसे 1 जनवरी 2024 से लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत, केंद्र 1 जनवरी 2023 से शुरू होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए पीएमजीकेएवाई के तहत अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों और प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध करा रहा है। पिछले साल दिसंबर में, केंद्र ने पीएमजीकेएवाई को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के साथ विलय करने का निर्णय लिया। अतिरिक्त खाद्यान्न नि:शुल्क उपलब्ध कराने के लिए 2020 में क्क्लृद्ध की शुरुआत की गई थी। एनएफएसए के तहत, 75 प्रतिशत ग्रामीण आबादी और 50 प्रतिशत शहरी आबादी को दो श्रेणियों-अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले घरों के तहत कवर किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में करीब 13.50 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए।

उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत

बेंगलूरू। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को आय से अधिक संपत्ति मामले में हाईकोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने शिवकुमार को हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाली अपील वापस लेने की अनुमति दे दी। शिवकुमार ने सीबीआई को दी गई सरकारी मंजूरी को रद्द करने से इनकार करने वाले आदेश को चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने बुधवार को शिवकुमार को राहत देने वाला आदेश पारित किया। बता दें कि भाजपा की सरकार के दौरान सीएम येदियुरप्पा ने कांग्रेस अध्यक्ष शिवकुमार के खिलाफ सीबीआई केस दर्ज करने को मंजूरी दे दी थी। इसके बाद डीके शिवकुमार के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की थी। आय से अधिक संपत्ति के कथित आरोप में सीबीआई जांच से राहत पाने के लिए शिवकुमार ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कर्नाटक हाईकोर्ट की पीठ के समक्ष शिवकुमार की पैरवी की।

7-20 तक महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र

मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र सात से 20 दिसंबर के बीच आयोजित किया जाएगा। एक अधिकारी ने बताया कि परंपरा के अनुसार यह सत्र राज्य की दूसरी राजधानी नागपुर में आयोजित किया जाएगा। विधान भवन के एक अधिकारी ने कहा, महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र की शुरुआत सात दिसंबर को होगा और यह 20 दिसंबर तक चलेगा। शेड्यूल के अनुसार इस सत्र में कामकाज के 10 दिन होंगे। इस सत्र में विपक्षी पार्टियों द्वारा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार को मराठा आरक्षण, बेमौसम बारिश, राज्य में निवेश जैसे कई अन्य मुद्दों पर घेरने की संभावना है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने बताया कि इस सत्र का आयोजन नागपुर में कराने को लेकर चर्चा की गई थी। उन्होंने कहा, विपक्षी पार्टी के नेता होने के तौर पर हम मांग करते हैं कि इस सत्र को तीन सप्ताह के लिए आयोजित किया जाए।

केरल के राज्यपाल व मुख्यमंत्री साथ बैठकर निकालें हल : सुको

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट केरल सरकार की उस याचिका पर विचार कर रहा है, जिसमें राजभवन पर विधेयकों को मंजूरी देने में अत्यधिक देरी का आरोप लगाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को फटकार लगाई और कहा कि पंजाब के मामले में पहले ही बताया जा चुका है कि राज्यपाल की शक्ति का इस्तेमाल विधायिका के कानून बनाने की प्रक्रिया को रोकने के लिए नहीं किया जा सकता। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने इस बात पर गौर किया कि कार्यवाहियों के बाद राज्यपाल खान ने आठ विधेयकों पर निर्णय लिया है। साथ ही अदालत ने उन्हें विधेयकों पर चर्चा करने के लिए संबंधित मंत्री के साथ मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से मिलने के लिए कहा है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्यपाल के कार्यालय की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी की इस दलील पर गौर किया कि आठ विधेयकों में से सात को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखा गया है जबकि एक को खान ने मंजूरी दे दी है।

हिमंत बिस्वा सरमा ने राहुल और प्रियंका पर कसा तंज

गुवाहाटी। एक वीडियो में राहुल और प्रियंका गांधी को एक राजनीतिक गाने पर नाचते हुए दिखाए जाने के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर सरमा ने कहा, मंगलवार को, एक चिंतित राष्ट्र प्रार्थनाओं में डूबा हुआ था और उत्तराखंड के हमारे श्रमिकों की सुरक्षा का इंतजार कर रहा था, एक परिवार हमेशा की तरह मौज-मस्ती-गायन और नृत्य में व्यस्त था। असम के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि चाहे वह 26/11 हो या कोई अन्य महत्वपूर्ण अवसर - यह हमेशा परिवार के लिए सबसे पहले मनोरंजन होता है। राहुल और प्रियंका समेत कांग्रेस पार्टी के नेताओं को दिखाने वाला यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। यह तब सामने आया जब उत्तरकाशी में 41 श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए बचाव अभियान चल रहा था।

कम्युनिस्ट और ममता ने मिलकर बंगाल को किया बर्बाद: अमित शाह

केंद्रीय गृहमंत्री बोले- जहां रवीन्द्र संगीत सुनाई पड़ता था, वहां बम के धमाके गूंज रहे

कोलकाता। केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह बुधवार को पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। उन्होंने कोलकाता में प्रतिवाद सभा को संबोधित किया। इस दौरान शाह ने ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा कि सोनार बांगला और मां माटी मानुष के नारे के साथ कम्युनिस्टों को हटाकर ममता दीदी सत्ता में आईं। लेकिन बंगाल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आज भी बंगाल में घुसपैठ, तुष्टिकरण, राजनीतिक हिंसा, भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं आज आह्वान करने आया हूं, अगर 2026 में यहां भाजपा सरकार बनानी है, तो इसकी नींव 2024 के लोकसभा चुनाव में डाल कर मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाइए।

अमित शाह ने कहा कि 27 साल बंगाल में कम्युनिस्टों का शासन रहा, तीसरे टर्म में ममता बनर्जी की सरकार बनी। दोनों ने मिलकर बंगाल को बर्बाद कर दिया। पूरे देश में चुनावी हिंसा सबसे ज्यादा बंगाल में होती है। ममता बनर्जी बंगाल में घुसपैठ को रोक नहीं पाई हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खुलेआम घुसपैठियों को वोटर कार्ड और आधार कार्ड बंट रहे हैं और ममता बनर्जी चुप बैठी हैं। भारतीय जनता पार्टी नेता ने बंगाल विधानसभा से सुवेंदु अधिकारी के निलंबन का जिक्र किया और कहा, आप सुवेंदु को विधानसभा से निकाल सकते हैं लेकिन बंगाल के लोगों को चुप नहीं करा सकते, वे कहते हैं कि आपका समय समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने बीजेपी को करीब 2.30 करोड़ वोट और 77 सीटों का आशीर्वाद दिया है...उनका उत्साह साफ बता रहा है कि उन्होंने 2026 में बीजेपी सरकार लाने का फैसला कर लिया है!

शाह ने कहा कि जिस बंगाल में कभी सुबह-सुबह रवीन्द्र संगीत सुनाई पड़ता था, आज वही बंगाल बम धमाकों से गूंज रहा है। पूरे देश से गरीबी खत्म हो रही है, लेकिन बंगाल में गरीबी कम होने का नाम नहीं ले रही है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने पूरे देश से आतंकवाद को समाप्त किया है। कश्मीर से जिस

धारा-370 को हटाने के लिए बंगाल के सपूत श्यामाप्रसाद मुखर्जी जी ने बलिदान दिया था, उस धारा- 370 को मोदी जी ने समाप्त किया। उन्होंने दावा किया कि वामपंथी उग्रवाद को समाप्त किया। भारत के तिरंगे को चंद्रयान 3 के माध्यम से चांद पर पहुंचाया। नई संसद बनाई और देश के अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंचाया।

गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि मोदी जी बंगाल में कल्याण सुनिश्चित करने के लिए लाखों करोड़ रुपये भेजते हैं, लेकिन बंगाल में सिंडिकेट राज गरीबों तक पैसा नहीं पहुंचने देता। उन्होंने कहा कि 2026 के चुनाव में दो तिहाई बहुमत के साथ बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी। लेकिन इससे पहले 2024 का चुनाव आ रहा है। 2019 में आपने 18 सीटें दी थी। मैं आपसे करबद्ध विनती करने आया हूं कि 2024 में इतनी सीटें दीजिए कि मोदी जी को शपथ विधि के बाद कहना पड़े कि मैं बंगाल के कारण प्रधानमंत्री बना हूं।

सीएए को कोई नहीं रोक सकता, हम लागू करेंगे

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को घोषणा की कि नरेंद्र मोदी सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) लागू करेगी और इसे कोई नहीं रोक सकता। पार्टी के लोकसभा अभियान की शुरुआत करने के लिए कोलकाता में एक रैली को संबोधित करते हुए शाह ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य में घुसपैठ रोकने में असमर्थ हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में घुसपैठियों को वोटर और आधार कार्ड खुलेआम और अवैध तरीके से बांटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस राज्य में इतनी घुसपैठ होती है, क्या वहां विकास होगा?.. इसलिए ममता बनर्जी सीएए का विरोध कर रही हैं... लेकिन मैं कहूंगा कि सीएए देश का कानून है, और इसे कोई नहीं रोक सकता... हम इसे लागू करेंगे।

2020 में संसद द्वारा पारित, सीएए 2015 से पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत में प्रवेश करने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करता है। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) जोर देकर कहती है कि सीएए असंवैधानिक है और यह मुसलमानों को बाहर करता है और एक धर्मनिरपेक्ष देश में नागरिकता को आस्था से जोड़ता है। केंद्र ने पहले कहा था कि वह सीएए के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया में है। रविवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने कहा था कि सीएए के नियम 30 मार्च 2024 तक तैयार कर लिए जाएंगे। बुधवार को, शाह ने एस्प्लेनेड में अपने संबोधन के दौरान आरोप लगाया कि बनर्जी की सरकार ने कम्युनिस्टों के साथ मिलकर बंगाल राज्य को बर्बाद कर दिया।

हम आपको यह भी बता दें कि राज्य प्रशासन ने शुरू में उस स्थान पर भाजपा की रैली का विरोध किया था, जहां सत्तारुढ़ तृणमूल कांग्रेस हर साल 21 जुलाई को अपनी शहीद रैली आयोजित करती है। हालांकि, बाद में कोलकाता उच्च न्यायालय की एकल पीठ और खंडपीठ दोनों ने भाजपा के आयोजन के लिए अनुमति दे दी थी। बहरहाल, भीड़ की दृष्टि से देखें तो अमित शाह की कोलकाता रैली बेहद सफल रही। देखा जाये तो इस भीड़ के जरिये भाजपा ने अपना शक्ति प्रदर्शन भी कर दिया है। साथ ही इस रैली को सफल बनाने के लिए पार्टी जिस एकजुटता के साथ लगी हुई थी उससे उन अटकलों पर भी विराम लगा है जिसके तहत बंगाल भाजपा में कई धड़ों के सक्रिय होने और अलग-अलग राह पर चलने की खबरें आती थीं।

तेलंगाना विधानसभा के लिए मतदान आज

बीआरएस के दीक्षा दिवस पर भड़की कांग्रेस

नई दिल्ली। तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। रचाकोंडा के कमिश्नर डीएस चौहान ने कहा, भी तैयारियां हो चुकी हैं...सभी जगहों पर सुरक्षाबल तैनात कर दिए गए हैं... केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की 25 कंपनियां भी तैनात की गई हैं...28 नवंबर से धारा 144 लागू कर दी गई है। मतदान वाले इलाकों में निषेधाज्ञा 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगी। धारा 144 के प्रभाव के दौरान बैठकें और रैलियों पर पाबंदी रहेगी। लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने की अनुमति भी नहीं है।

मतदान के एक दिन पहले तेलंगाना भवन में बीआरएस ने दीक्षा दिवस समारोह का आयोजन किया। तेलंगाना कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बोम्मा महेशकुमार गौड़ ने इसे चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास करार दिया। उन्होंने कहा यह आदर्श आचार संहिता का घोर उल्लंघन है। मतदान 30 नवंबर को है ऐसे में 28 और 29 नवंबर पूरी तरह से शांतिपूर्ण दिन होने चाहिए। कोई राजनीतिक दल कार्यक्रम नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग के नियम के अनुसार किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति नहीं। ऐसे में दीक्षा दिवस कैसे मनाया गया? यह सिर्फ तेलंगाना की जनता को प्रभावित करने के लिए है। कांग्रेस चुनाव आयोग से उनके खिलाफ कार्रवाई और सख्त कदम उठाने का अनुरोध करती है।

तेलंगाना के नामपल्ली क्षेत्र के कांग्रेस विधायक के खिलाफ एक वोटर को एक लाख रुपये रिश्वत के तौर पर देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। कांग्रेस सांसद फिरोज खान के खिलाफ आरपी एक्ट की धारा 71सी, 188 और 123 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी हैदराबाद के चार मीनार के श्री भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा करने पहुंचे। उन्होंने उत्तरकाशी के सुरंग में फंसे 41 मजदूरों के सुरक्षित बाहर निकालने का श्रेय देवी भाग्य लक्ष्मी के आशीर्वाद को दिया है।

उन्होंने कहा, देवी भाग्य लक्ष्मी के आशीर्वाद से उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। इस बचावकार्य में शामिल सभी अधिकारियों का मैं धन्यवाद करता हूं। पीएम मोदी के लीडरशिप और सीएम पुष्कर धामी के नेतृत्व में यह मिशन कामयाब हो पाया है।

तेलंगाना के हनुमाकोंडा जिले में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। डीएम सिकता पटनायक ने कहा कि गुरुवार को सुबह सात बजे से जिले में मतदान शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा, दो विधानसभा क्षेत्रों के लिए व्यवस्था की गई है, इसलिए यहां लगभग 2500 मतदान कर्मी रिपोर्ट कर रहे हैं और उनके लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं।

तेलंगाना में मतदान से पहले बीआरएस नेता केटी रामा राव ने हैदराबाद में आयोजित रक्तदान शिविर के दौरान रक्तदान दिया। तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 से पहले निजामाबाद में चुनाव अधिकारियों को मतदान सामग्री वितरित की जा रही है।

खेल
प्रमुख समाचार

राहुल द्रविड़ ही रहेंगे भारतीय टीम के कोच

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए इस बात की घोषणा कर दी है कि राहुल द्रविड़ ही टीम इंडिया के कोच रहेंगे। बीसीसीआई ने उनका कार्यकाल बढ़ा दिया है। वहीं, कोचिंग स्टाफ में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि द्रविड़ मुख्य कोच रहेंगे। विक्रम राठौर बल्लेबाजी कोच, पारस म्हाम्ब्रे गेंदबाजी और टी दिलीप फील्डिंग कोच के पद पर बने रहेंगे।

बीसीसीआई ने विज्ञप्ति जारी कहा कि हाल ही में संपन्न विश्व कप के बाद अनुबंध की अवधि समाप्त होने के बाद बीसीसीआई ने राहुल द्रविड़ के साथ सार्थक चर्चा की और सर्वसम्मति से कार्यकाल को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। बोर्ड भारतीय टीम को तैयार करने में द्रविड़ की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करता है और उनकी असाधारण व्यावसायिकता की सराहना करता है। बोर्ड एनसीए के प्रमुख और स्टैंड-इन हेड कोच के रूप में उनकी अनुकरणीय भूमिकाओं के लिए वीवीएस लक्ष्मण की भी सराहना करता है। अपनी प्रसिद्ध ऑन-फील्ड साझेदारियों की तरह द्रविड़ और लक्ष्मण ने भारतीय क्रिकेट को आगे बढ़ाने में मिलकर काम किया है।

कार्यकाल बढ़ाए जाने पर द्रविड़ ने कहा, टीम इंडिया के साथ पिछले दो साल पूरी तरह से यादगार रहे हैं। हमने साथ में उतार-चढ़ाव देखे हैं और इस पूरी यात्रा के दौरान टीम के भीतर समर्थन और सौहार्द रहा है। हमने ड्रेसिंग रूम में जो संस्कृति स्थापित की है, उस पर मुझे वास्तव में गर्व है। हमारी टीम के पास जो कौशल और प्रतिभा है, वह अभूतपूर्व है। मैं बीसीसीआई और पदाधिकारियों को मुझ पर भरोसा करने, मेरे दृष्टिकोण का समर्थन करने और इस दौरान समर्थन प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स में 700 से ज्यादा का उछाल, निफ्टी 20 हजार के पार

नईदिल्ली। भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को तूफानी तेजी दर्ज की और बाजार लगातार दूसरे दिन पॉजिटिव नोट में बंद हुए। बाजार के दोनों प्रमुख इंडेक्स एक प्रतिशत से ज्यादा की बढ़त लेकर बंद हुए। तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 727.71 अंक या 1.10 प्रतिशत का उछाल लेकर 66,901.91 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 66,946.28 अंक स्तर तक भी पहुंच गया था। सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से 27 के शेयर ग्रीन निशान में बंद हुए जबकि तीन कंपनियों के स्टॉक लाल निशान में रहे। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 भी 206.90 अंक या 1.04 प्रतिशत की बढ़त के साथ 20,096.60 अंक पर बंद हुआ। यह इस साल 18 सितंबर के बाद पहली बार 20 हजार के अंक पार बंद हुआ है। निफ्टी की 40 कंपनियों के शेयर हरे जबकि 10 लाल निशान में बंद हुए।

2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा को तीगुना करने पर भारत

नईदिल्ली। वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक 'एम्बर' द्वारा बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की 14वीं राष्ट्रीय विद्युत योजना (एनईपी) वर्ष 2030 तक अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना से अधिक करने की राह पर है, लेकिन इसे हासिल करने के लिए देश को कुल 293 अरब डॉलर की जरूरत होगी। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) ने कहा है कि विश्व को जीवाश्म ईंधन की जरूरत कम करने और इस सदी के अंत तक वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए 2030 तक अपनी नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना और ऊर्जा दक्षता को दोगुना करना होगा। अमेरिका, यूरोपीय संघ (ईयू) और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के नेतृत्व में 60 से अधिक देश अब अक्षय ऊर्जा को तीन गुना करने और ऊर्जा दक्षता को दोगुना करने की प्रतिबद्धता का समर्थन कर रहे हैं।

जोमैटो में चीनी कंपनी ने बेची 3.4 प्रतिशत हिस्सेदारी

नईदिल्ली। फूड डिलीवरी एग्रीगेटर जोमैटो के 3.4 प्रतिशत शेयरों यानी करीब 29.7 करोड़ शेयरों की बिक्री एक ब्लॉक डील के जरिये बुधवार को हुई है। यह खबर आते ही जोमैटो के शेयरों में दमदार तेजी आई और कंपनी के शेयर 4.3 फीसदी उछलकर 119 रुपये पर ट्रेड करने लगे। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अलीपे सिंगापुर होल्डिंग ने जोमैटो में अपनी पूरी 3.44 फीसदी हिस्सेदारी 400 मिलियन डॉलर (3,326 करोड़ रुपये) में बेच दी है। बता दें कि अलीपे ग्रुप का मालिकाना हक एंटफिन के पास है और यह चीन के अरबपति जैक मा की कंपनी अलीबाबा ग्रुप का हिस्सा है। 12.48 बजे तक भी जोमैटो के शेयरों में बीएसई और एनएसई में उछाल देखने को मिला। बीएसई पर कंपनी के शेयर 4.35 फीसदी उछलकर 118.15 रुपये पर ट्रेड करते दिखे। वहीं, एनएसई पर इसके शेयर 3.78 फीसदी चढ़कर 118.10 रुपये पर ट्रेड करते दिखे।

आईआरईडीए के शेयर निर्गम मूल्य से 56 प्रतिशत उछाल के साथ सूचीबद्ध

नईदिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड (आईआरईडीए) के शेयर निर्गम मूल्य 32 रुपये से 56 प्रतिशत से अधिक उछाल के साथ बुधवार को सूचीबद्ध हुए। बीएसई और एनएसई दोनों पर शेयर निर्गम मूल्य से 56.25 प्रतिशत चढ़कर 50 रुपये पर सूचीबद्ध हुए। दोनों सूचकांकों पर बाद में यह 74 प्रतिशत बढ़कर 55.70 रुपये पर पहुंच गए। कंपनी को शुरुआती कारोबार में बाजार मूल्यांकन 14,460.17 करोड़ रुपये रहा। आईआरईडीए के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) को गत बृहस्पतिवार 38.80 गुना अभिदान मिला था। आईपीओ के लिए मूल्य दायरा 30-32 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था।

जब विवाह में व्यापार है, तब दहेज भी कारोबार है

संजय तिवारी

23 नवंबर को देवउठनी एकादशी के दिन नारायण निद्रा से जागे तो हिन्दुओं ने अपने पवित्र मांगलिक कार्यों को करना प्रारंभ कर दिया। उनके लिए विवाह से अधिक मांगलिक कार्य भला और क्या होगा? इसलिए नारायण के निद्रा त्यागते ही एक बार फिर देशभर में विवाह की बहार आ गयी। कॉन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स ने अनुमान लगाया है कि इस सीजन में 23 नवंबर से 15 दिसंबर तक मात्र 23 दिन के अंदर लगभग 35 लाख विवाह होंगे जिसमें 4.25 लाख करोड़ का व्यापार होने का अनुमान है। यह लग्न सीजन विवाहित होने वाले जोड़ों से अधिक व्यावसायिक जगत के लिए फायदेमंद होनेवाला है।

भारत परिवार आधारित सामाजिक संरचना है। यहां पारिवारिक और सामाजिक संबंधों पर ही सबसे अधिक धनराशि खर्च की जाती है। कुछ दशक पहले तक विवाह में बाजार का दखल सिर्फ गहनों और कपड़ों की खरीदारी तक सीमित था। इसके अलावा विवाह की पूरी व्यवस्था सामाजिक सहयोग से पूरी की जाती थी। लेकिन बदलते समय के साथ साथ विवाह की पूरी व्यवस्था समाज आधारित होने की जगह बाजार आधारित होती चली गयी। बाजार द्वारा प्रायोजित नित नये प्रयोग ने नयी नयी परंपराओं को जन्म दिया है जिसमें डीजे बैण्ड का शोर ही नहीं बल्कि प्री वेडिंग शूटिंग और डेस्टिनेशन वेडिंग जैसे मंहगे शौक भी विवाह की परंपरा बनते जा रहे हैं।

नब्बे के दशक में देश में पूंजीवाद बढ़ा और बाजार ने पैर पसारे तो विवाह संस्कार में भी अपनी जगह बनाते चले गये। समाज ने इसे रोका भी नहीं। कन्याधन के नाम पर वधू पक्ष द्वारा जो कुछ दिया जाता था, वो

आमतौर पर कन्या के घरेलू इस्तेमाल का सामान और गहना कपड़ा ही होता था। लेकिन बाजार का दखल बढ़ा तो टीवी, फ्रिज, कूलर या एसी, मोटरसाइकिल या फिर फोर व्हीलर सहित घर का हर साजो सामान दहेज का हिस्सा बन गया।

भारत में उत्सव पर्व तथा विवाह ये बाजार के लिए व्यापार के दो प्रमुख अवसर बन गये हैं। व्यापारिक घरानों का अपना आंकलन और अध्ययन है कि विवाह पर जो खर्च होता है उसमें एक सीजन में ही 60 हजार करोड़ के गहने खरीदे जाते हैं। इसके बाद कपड़ों का बाजार, कंज्यूमर आइटम का बाजार भी बम बम रहता है। व्यावसायिक घरानों के अध्ययन के अनुसार ही देखें तो सालाना 8 से 10 लाख करोड़ का व्यापार विवाह से उत्पन्न होता है। इसमें न सिर्फ दहेज का सामान, गहने, कपड़े, कन्ज्यूमर आइटम बल्कि परिवहन, टूरिज्म, होटल इंडस्ट्री को भी तगड़ा कारोबार मिलता है और करोड़ों लोगों को रोजगार भी। भारत में विवाह हर कारोबारी के लिए कुछ न कुछ व्यावसायिक अवसर पैदा करता है। कन्फडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स के ताजा अध्ययन को ही देखें तो भारत में विवाह के अलग अलग बजट हैं। शुरुआत 3 लाख से होती है। जिन विवाहों का इस सीजन में आंकलन किया गया है इसमें से लगभग 6 लाख विवाह ऐसे होंगे जिनका बजट 3 लाख तक होगा। इसके बाद 10 लाख विवाह ऐसे होंगे जिनमें प्रति विवाह 6 लाख रूपये तक खर्च होगा। इसके बाद लगभग 12 लाख विवाह ऐसे होंगे जिनमें औसत 10 लाख रूपये तक खर्च होगा। 6 लाख विवाह ऐसे होंगे जिनका बजट 25 लाख तक होगा। 50 हजार शादियां ऐसी होंगी जिनमें 50 लाख से एक करोड़ तक का खर्च होगा। जबकि 50 हजार विवाह ऐसे होंगे जिनका बजट एक करोड़ से ऊपर होगा।

इस तरह विवाह बाजार के हर हिस्से के लिए कुछ न कुछ कारोबार पैदा करते हैं। अगर डिजाइनर ड्रेस का कारोबार करनेवाले बिजनेस पाते हैं तो कपड़े के छोटे कारोबारी भी अपने लिए व्यापार का अवसर पाते हैं। ऐसे ही हर सेक्टर में ऊपर से लेकर नीचे तक विवाह सबके लिए कुछ न कुछ कारोबार और रोजगार पैदा करता है। अब तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी अपने मन की बात में डेस्टिनेशन वेडिंग पर सवाल उठाया है। अगर देश के बाहर जाकर विवाह करनेवालों की संख्या में कमी आती है तो यह कारोबार भी भारत में ही बढ़ेगा।

डाकमत पत्रों की गिनती पृथक रूप से आरओ के टेबल में होगी

● डाकमत पत्रों की गिनती के लिए दिया गया प्रशिक्षण ● प्रशिक्षकों ने दी तकनीकी जानकारी

रायपुर. समय का विशेष ध्यान रखें, मतगणना तिथि 3 दिसम्बर को सुबह 7 बजे तक अपनी सीट तक मतगणना में संलग्ल अधिकारी-कर्मचारियों को पहुंच जाना चाहिए। उन्हें अपनी निर्धारित टेबल पर ही बैठना है। डाक मतपत्रों की गिनती सबसे पहले होगी। डाक मतपत्रों की गणना रिटर्निंग ऑफिसर करेंगे , जिनके सहयोग के लिऐ विशेष सहायक रिटर्निंग आफिसर होंगे,इसके लिए अलग टेबल होगा। डाक मतपत्रों की वैधता के बारे में उनका निर्णय ही मान्य होगा। इस कार्य के लिए नियुक्त गणना पर्यवेक्षक और सहायक उनकी सहायता करेंगे। डाक मतपत्रों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षकों ने यह कहते हुए डाक मतपत्रों की गिनती की संबंध में तकनीकी जानकारी साझा की।

यह प्रशिक्षण कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रास सभाकक्ष में दिया गया।

प्रशिक्षकों ने बताया कि डाक मतपत्र के दो वर्गों में हैं ईटीपीबीएस अर्थात इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट और साधारण डाक मतपत्र। इन दोनों में एक ही प्रत्यक्ष अंतर होगा, ईटीपीबीएस पर अभ्यर्थी के चुनाव चिह्न अंकित नहीं होंगे पर दलीय सम्बद्धता (या निर्दलीय) का उल्लेख होगा। अन्य डाक मतपत्र पर चुनाव चिह्न होगा पर दलीय सम्बद्धता नहीं लिखी होगी। उन्होंने बताया कि पूर्व-गणना परीक्षण के बाद ईटीपीबीएस को भी सामान्य डाक मतपत्र की ही तरह हैण्डल करना है। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती ही प्रारंभ होगी। सामान्यत: एक निर्वाचन क्षेत्र में डाक मतों की गणना के लिए प्रत्येक 500 प्राप्त मतों के लिए एक टेबल आबंटित होगा।

प्रशिक्षण में जानकारी दी गई कि दोनों ही प्रकारों के डाकमतों के लिए तीन अनिवार्य अभिलेख होंगे, जिसमें पहला बाहरी लिफाफा बी (13सी) मतदाता की घोषणा (13ए); और 3) तथा मतपत्र का लिफाफ़ा ए (13बी) शामिल है। ईटीपीबीएस के लिए

रिटर्निंग अधिकारी द्वारा गणना-पूर्व व्यवस्था की जायेगी। इसमें (एक एआरओ की देख-रेख में अधिकतम 10) मेजों पर लिफाफ़ों की स्केनिंग की व्यवस्था की जायेगी। ऐसे प्रत्येक मेज पर एक दल में क्यूआर कोड स्केनर के साथ एक सुपरवाईज़र और एक सहायक होंगे। सॉफ्टवेयर की मदद से प्रत्येक ईटीपीबीएस के बाहरी लिफाफे 13-सी के क्यूआर कोड को स्केन कर पोर्टल में अपलोड किया जायेगा।

प्रशिक्षण में बताया गया कि ईटीपीबीएस के लिए लिफाफों एवं मतपत्र के लिए कलर कोड लागू नहीं होता। मत के ख़ारिज होने के अन्य कारण ईटीपीबीएस पर भी यथावत लागू होंगे। डाक मतपत्र पर मतांकन के लिए कोई विशेष चिन्ह नहीं है। मतदाता द्वारा किसी भी चिन्ह का उपयोग अपनी मतांकन के लिए किया जा सकता है। इस संबंध में निर्देश केवल यह हैं कि निर्वाचक का चयन स्पष्ट परिलक्षित होता हो। किसी तकनीकी कारण से (घोषणा पत्र में त्रुटि, 13-सी में घोषणा पत्र न मिलने, निर्धारित रंग का लिफाफ़ा न होने आदि)गणना में शामिल न किए गये सभी डाक मतवाले लिफाफे गणना स्थल से हटा लिये जायेंगे और उन्हें एक अलग पैकेट में सुसंगत टीप के साथ सीलबंद किया जायेगा। शेष लिफाफों के अन्यथा वैध पाये जाने पर सभी 13-सी वाले लिफाफे अपने 13-ए के साथ संलग्न करते हुए (गोपनीयता को दृष्टिगत रखते हुए) गणना स्थल से हटा दिए जायेंगे। इन्हें भी एक अलग पैकेट में सुसंगत टीप के साथ सीलबंद किया जायेगा। इसके बाद ही सभी 13-बी (भीतरी, छोटा लिफाफ़ा) खोला जायेगा और मतपत्र बाहर निकाला जायेगा। डाक मतपत्र (चाहे ईटीपीबी हो या सामान्य) उस स्थिति में अविधिमान्य होंगे जब मतपत्र (ईटीपीबी को छोड़कर) पर आरओ के हस्ताक्षर की मुहर न लगी हो।

एक से अधिक अभ्यर्थियों के नाम के समक्ष कोई निशान लगा हो। यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों के नाम के समक्ष अलग-अलग निशान हो तब भी उसे अविधिमान्य किया जाएगा। किसी एक अभ्यर्थी के नाम के समक्ष लगा निशान दूसरे अभ्यर्थी के खाने तक इस प्रकार चला गया हो कि उसके चयन का निर्धारण कर सकना संभव न हो, या किसी भी अभ्यर्थी के नाम के समक्ष कोई निशान न लगा हो।

कई राशन दुकानों का स्टाक दो दिन में खत्म

रायपुर। केन्द्र सरकार ने राशन वितरण में पोर्टेबिलिटी लागू की है। वन नेशन वन कार्ड के तहत हितग्राही किसी भी जिले या राज्य में जाकर राशन ले सकता है। राजधानी में बड़ी संख्या में लोगों ने योजना का लाभ उठाते हुए पास की राशन दुकान को खाद्यान्न लेने चुना है। दूसरी ओर योजना को लेकर कई तरह की विसंगति भी देखने में आ रही है। शासन के निर्देश पर दुकान संचालक एसे सभी हितग्राहियों को राशन का वितरण कर रहे हैं। लेकिन इसकी वजह से कुछ दुकान संचालकों को दिया गया एक माह का राशन मात्र दो दिन में ही खत्म होता जा रहा है। इतना ही नहीं दूसरे कार्ड धारकों को राशन देने के बाद अतिरिक्त आवंटन की मांग करने पर भी दुकान संचालकों को राशन नहीं दिया जा रहा है। साथ ही 75 प्रतिशत वितरण के बाद ही राशन का आवंटन देने की बात कही जा रही है लेकिन सारा सिस्टम ऑनलाइन होने के बावजूद और राशन खत्म होने के बाद भी मॉड्यूलर में राशन शेष दिख रहा है जिसे महीने की 10 तारीख के बाद अपडेट करने की बात कही

जा रही है। इसकी वजह से हितग्राही राशन दुकान तो जा रहे हैं लेकिन वहां राशन नहीं होने की वजह से खाली हाथ लौट रहे है। खाद्य विभाग के आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश भर में सर्वाधिक पोर्टेबिलिटी रायपुर जिले में ही हुई है। आंकड़ों के हिसाब से रायपुर में 58000 कार्ड धारकों द्वारा करीब 1 लाख ट्रांजैक्शन किए गए हैं वहीं सबसे कम पोर्टेबिलिटी के आंकड़े सरगुजा जिले के हैं यहां 180 कार्ड धारकों द्वारा 303 ट्रांजैक्शन किए गए हैं। शहर में कई राशन दुकान खुलने के बाद कार्डों को भी नई दुकान में ट्रांसफर किया गया है लेकिन हितग्राही जिस दुकान में कार्ड अटैच है वहां से राशन लेने की बजाय पुरानी दुकान से ही राशन ले रहे हैं इसकी वजह से एक दुकान का स्टाफ घट रहा है जबकि दूसरी दुकान का स्टाफ खत्म नहीं हो रहा है।

राशन दुकानों के लिए नान द्वारा बनाए गए नियमानुसार दुकान संचालक द्वारा 75 प्रतिशत राशन का वितरण करने के बाद ही अतिरिक्त नया आवंटन जारी किया जाएगा लेकिन दुकानों में स्टॉक खत्म होने के बाद तुरंत अपडेट नहीं होने की वजह से नए स्टॉक के लिए इंतजार करना पड़ रहा है।

टाटा ईतवारी एक्सप्रेस एक को रद्द रहेगी

रायपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत राऊरकेला-झारसुगुड़ा सेक्शन के बीच पानपोष में ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक लिया जा रहा है । यह ब्लॉक का कार्य 29 नवम्बर को लिया जाएगा । परिणामस्वरूप दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलने वाली कुछ गाड़ियो का परिचालन प्रभावित रहेगा।

टाटानगर-इतवारी एक्सप्रेस इस दिन रद्द रहेगी। दूसरे दिन 1 दिसम्बर, को 18110 इतवारी-टाटानगर एक्सप्रेस रद्द रहेगी । इसी तरह उत्तर पूर्व रेलवे के वाराणसी रेल मण्डल के छपरा यार्ड का आधुनिकीकरण का कार्य के लिए कुछ गाड़ियो का परिचालन रहेगा ।

दुर्गछपरा-दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस बलिया रेलवे स्टेशन में ही समाप्त होगी और यह गाड़ी बलिया से ही दुर्ग के लिए रवाना होगी । यह गाड़ी दिनांक 29 दिसम्बर से 12 जनवरी, 2024 तक दुर्ग एवं बलिया के बीच ही चलेगी । नवम्बर माह में 29 एवं 30 नवम्बर, 2023 को तथा दिनांक 01, 03, 05, 07, 08, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28 एवं 29 दिसम्बर, 2023 को, जनवरी माह में 02, 04, 05, 07, 09, एवं 11 जनवरी, 2024 को बलिया से दुर्ग के लिए रवाना होगी ।

15160 दुर्ग-छपरा सारनाथ एक्सप्रेस को नवम्बर माह में 29 एवं 30 नवम्बर, 2023 को, दिसम्बर माह में दिनांक 1, 02, 04, 06, 08, 09, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29 एवं 30 दिसम्बर, 2023 को, जनवरी माह में 01, 03, 05, 06, 08, 10 एवं 12 जनवरी, 2024 को बलिया तक ही चलेगी।

आज, कल फिर हो सकती है बेमौसम बरसात

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदल गया है। प्रदेश में मंगलवार को बादल छाए रहने के साथ ही मौसम ने करवट ली और कई इलाकों में हल्की मध्यम

बारिश हुई। कहीं-कहीं बूंदाबांदी हुई, तो कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ी। आगे भी कुछ दिन मौसम ऐसे ही बने रहने की संभावना है। अब न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की की जाएगी और प्रदेश में ठिठुरन बढ़ने लगेगी। मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश में बारिश की स्थिति बनी हुई है। इससे तापमान गिरेगा और ठंड बढ़ने लगेगी।

बीते दिनों मंगलवार को प्रदेश के जांजगीर सबसे ठंडा रहा। यहां न्यूनतम तापमान 11.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम का मिजाज बदलने से प्रदेश के कई जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इससे प्रदेश में सुबह के साथ दोपहर में भी ठंड रहा। इन दिनों छत्तीसगढ़ में धान की कटाई के साथ ही मिजांई का भी काम चल रहा है। मौसम में बदलाव के कारण किसान भी चिंता में हैं। प्रदेश में धान खरीदी भी शुरू हो गया है। बीते दिनों की बारिश से सभी किसान अस्त व्यस्त हो गए। वहीं धान खरीदी केन्द्रों में धान की सुरक्षा के लिए तुरंत इंतजाम किया गया। बारिश की संभावना से केन्द्रों में इसके लिए पहले से ही तैयारी कर लिया गया था। बीते दिनों मंगलवार को मौसम को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी जिला अधिकारीयों को धान की सुरक्षा को लेकर सचेत किया था। वहीं खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने मंदिर हसौद के एक केंद्र में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने केंद्रों में धान को बारिश से बचने के लिए पर्याप्त प्रबंध करने के निर्देश दिए। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पड़ रही कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। सुबह और देर शाम को लोग अलाव के आसपास बैठे नजर आ रहे हैं।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

सेवामुक्त हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर को आयोग में दी गयी भावभीनी विदाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री ठाकुर राम सिंह सेवामुक्त हो गये हैं। आज इसी के

मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग में विदाई समारोह का आयोजन कर उन्हें भावभीनी विदाई दी गयी। आयोग के सभाकक्ष में दोपहर 12 बजे से आहूत इस समारोह को संबोधित करते हुए सचिव श्री कैसर अब्दुल हक़ ने कहा कि बतौर आयोग के सचिव के अल्प कार्यकाल में भी उन्हें श्री सिंह से बहुत कुछ सीखने मिला। कार्य के प्रति समर्पण, ज़िम्मेदारी लेकर काम पूरा करना और समय की पाबंदी श्री सिंह के व्यक्तित्व की ऐसी ख़ासियत है जो उनके शांत, सौम्य व्यक्तित्व में चार चाँद लगा देती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगर आयोग के सभी अधिकारी कर्मचारी इन गुरों को अपना लेंगे तो उन्हें सफलता पाने में कोई दिक़्क़त नहीं आएगी। श्री सिंह अपने प्रशासनिक कार्यकाल में हमेशा सही और कड़े फ़ैसले लेते रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग में भी हमेशा चुनाव जैसे महत्वपूर्ण कार्य को अपने अनुभव से आसानी से संपादित करते रहे हैं। उन्होंने अंत में कहा कि सेवामुक्त होकर श्री सिंह स्वस्थ, खुशहाल और दीर्घायु रहें यही प्रार्थना है। उप सचिव श्री दीपक अग्रवाल ने कहा कि ना केवल राज्य निर्वाचन आयोग बल्कि दो ज़िला बिलासपुर और रायपुर में जब श्री सिंह कलेक्टर के तौर पर पदस्थ रहे. तब उनके साथ काम करने का मौका मिला.

तेंदुए की खाल के साथ तीन गिरफ्तार

गरियाबंद। तेंदुए की खाल बेचने के फिराक में घूम रहे ओडिशा के 3 आरोपियों को उदंती सीतानदी अभ्यारण्य की एंटी पोचिंग टीम ने धर दबोचा. बता दें कि 27 नवंबर को उदंती सीतानदी अभ्यारण्य की एंटी पोचिंग टीम को सूचना मिली थी कि बीरीघाट क्षेत्र में कुछ संदिग्ध तेंदुए की खाल को बेचने ग्राहक तलाश रहे. इस सूचना पर टीम ने तेंदुए की खाल के साथ तीन आरोपियों को हिरासत में लिया.

अभ्यारण्य प्रशासन ने आज प्रेस नोट जारी कर बताया कि आरोपी कार्तिक गोड 45 वर्ष उसका बेटा गोरांगो गोड 23 वर्ष के अलावा उपेंद्र रावत 25 वर्ष को खाल के साथ हिरासत में लिया गया. तीनों आरोपी ओडिशा चंदाहांडी थाना क्षेत्र के चकामाल ग्राम के निवासी हैं. उपनिदेशक वरुण जैन के मार्गदर्शन में टीम का नेतृत्व कर रहे उदंती अभ्यारण्य के सहायक संचालक गोपाल कश्यप ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि तेंदुए को जहर देकर मारा गया. शिकार के मामले में अन्य और आरोपी है, जिसकी पतासाजी की जा रही है. कश्यप ने कहा कि पेशेवर इन तस्करों के निशानदेही पर आगे की पड़ताल जारी है. आगे बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद है. आरोपियों के विरूद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्यवाही कर 28 को देवभोग न्यायालय में पेश किया गया, जहां से तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया. इस अभियान में सुशील सागर रेंजर इंदागांव, चंद्रबली ध्रुव उपनोडल अधिकारी, राकेश मार्कडेय, चूरामन धृत लहरे, ओमप्रकाश राव, फलेश्वर दीवान, ऋषि ध्रुव समेत अन्य वन कर्मचारियों का विशेष योगदान रहा.

जनता ने भाजपा को मुख्यमंत्री का चेहरा ढूंढने का अवसर नहीं दिया

रायपुर। प्रदेश में फिर कांग्रेस की सरकार बन रही है।जनता ने भाजपा को मुख्यमंत्री का

चेहरा ढूंढने का अवसर नहीं दिया है। भाजपा को नेता प्रतिपक्ष कौन होगा? इस दिशा में मजबूती से प्रयास करना चाहिए।भाजपा को यह बताना चाहिए क्या मोदी की गारंटी पर चुनाव लडने वाली भाजपा का अगला नेता प्रतिपक्ष गारंटी देने वाला होगा? या फिर राज्य निर्माण के वक्त नेता प्रतिपक्ष चुनने आए प्रभारी के साथ एकात्म परिसर में हुई घटना की फिर पुनर्विवृत्ति होने वाली है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि जनता ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का चेहरा सरकार के काम और कांग्रेस की घोषणा पत्र पर भरोसा किया है। भाजपा जिस प्रकार से नकारात्मकता ,अफवाह फैलाकर चुनाव लड़ी है। जनता ने उसे खारिज कर दिया है।दूसरे राज्यों से भाजपा के कई दिग्गज नेता आकर छत्तीसगढ़ में चुनाव की कमान संभाले थे।सभी को मुंह की खानी पड़ी है। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेताओं को चुनाव प्रचार के दौरान धूल चटा दिया है। भाजपा के घोषणा पत्र मोदी की गारंटी और भाजपा के षड्यंत्र के खिलाफ जनता कांग्रेस के साथ खड़ी रही है। ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की सरकार विपक्ष का पूरा सम्मान करती है और उम्मीद करती है.

रायपुर में टिकटों की कालाबाजारी, पुलिस ने 4 लोगों पर की कार्रवाई

रायपुर. भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टी-20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के टिकटों की कालाबाजारी करने वालों पर रायपुर पुलिस ने कार्रवाई की है. चार लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर उनसे 13 नग टिकट जब्त किया है. बता दें कि एक दिसंबर को शहीद वीरनारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम परसदा रायपुर में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच टी-20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच होगा. इसके टिकटों की कालाबाजारी की सूचना पर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने सभी पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट को मैच के टिकटों की कालाबाजारी करने वालों के संबंध में जानकारी एकत्र कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे. वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और थाना कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने आज थाना कोतवाली क्षेत्र के अलग-अलग स्थानो में टिकटों की कालाबाजारी करते तुलसी बाराडेरा मंदिर हसौद निवासी अनिल जांगड़े, आकाश कुमार धीवर तथा सिविल लाईन निवासी बबलू नायक एवं आशीष मिश्रा को पकड़ा.

केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 81 करोड़ लोगों को मिलेगा फ्री राशन

रायपुर। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और 30 नवंबर 2023 को तेलंगाना में पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के आखिरी दौर से पहले मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है. यह

देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को पांच साल तक मुफ्त अनाज देने वाली योजना है. पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत कोविड महामारी के दौरान से की गई थी. सरकार ने इस योजना को 1 जनवरी 2024 के बाद अगले पांच साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है. योजना के लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त अनाज मिलेगा और 81 करोड़ भारतीयों को योजना का लाभ मिलेगा. अंत्योदय योजना का लाभ पाने वाले परिवारों को 35 किलो अनाज मिलता रहेगा. वहीं सरकार अगले पांच साल में इस योजना पर 11.80 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी. इस योजना के तहत 31 दिसंबर 2023 तक मुफ्त अनाज दिया जाना है. लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार ने इस योजना को पांच साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है.

कैथलैब में एक्स रे के कारण निकलने वाले हानिकारक विकिरणों से डॉक्टर, सहयोगी स्टाफ एवं मरीज को भी देगी सुरक्षा

अम्बेडकर अस्पताल में लगा रेडिएशन प्रोटेक्शन सिस्टम

रायपुर। डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय स्थित एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट के कैथ लैब में कार्यरत डॉक्टर एवं पूरी टीम को रेडिएशन(विकिरणों) से सुरक्षा प्रदान करने के लिए रेडिएशन प्रोटेक्शन सिस्टम लगाया है। एगनेस्ट नामक यह सुरक्षा कवच कैथ लैब में कार्यरत मेडिकल टीम को एक्स रे मशीन से निकलने वाली हानिकारक विकिरणों से सुरक्षा प्रदान करता है। एसीआई के कार्डियोलॉजी विभाग एवं कार्डियोलॉजिक्स कंपनी के सहयोग से इसे कैथ लैब में लगाया गया है।

विभागाध्यक्ष कार्डियोलॉजी विभाग डॉ. स्मित श्रीवास्तव ने रेडिएशन प्रोटेक्शन सिस्टम (विकिरण सुरक्षा प्रणाली) के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि एगनेस्ट, कैथलैब में कार्यरत पूरी मेडिकल टीम को यहां तक कि प्रोसीजर टेबल में लेटे मरीज को हानिकारक एक्स रे विकिरणों से सुरक्षा प्रदान करेगी। यह सुरक्षा कवच कार्डियोलॉजी प्रोसीजर किये जाने वाले टेबल के साथ चारों तरफ से अटैच है। यह कार्बन माइक्रो फाइबर बेस तथा रेडिएशन एब्जॉर्बिंग मेटलिक एलॉय (बिस्मथ और

एंटीमनी धातु) से बना है जो एक्स रे मशीन से निकलने वाले हानिकारक विकिरणों को सोख लेते हैं। इन विकिरणों से यदि बचाव न किया जाये तो भविष्य में कैंसर, मोतियाबिंद एवं अन्य बीमारियां होने की संभावना रहती है।

डॉ. स्मित श्रीवास्तव के अनुसार, कैथलैब में पूरी प्रक्रिया एक्स रे मशीन की सहायता से की जाती है (एक्स रे गाइडेड प्रोसीजर)। कैथ लैब में प्रतिदिन कार्डियक इंटरवेंशनल प्रक्रिया होती है। पूरी टीम लम्बे समय तक यहां रहती है। ऐसे में पूरी टीम विकिरण के संपर्क में आती है। एगनेस्ट एक व्यापक, स्कैटर रेडिएशन (फैलने वाले विकिरण) सुरक्षा प्रणाली है जो पूरी तरह से आधुनिक कैथ लैब में रेडिएशन के फैलाव एवं बिखराव को रोकने में मदद करती है। यह कैथ लैब में कार्य करने वाली मेडिकल टीम को सुरक्षा प्रदान करते हुए एक्स रे विकिरणों से होने वाले दुष्प्रभाव को कम करती है। इसे सीआर्म एक्स रे मशीन की गति एवं दिशा के अनुसार इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह रोगी की दिशा के अनुसार सरलता से इधर उधर घूम सकता है। यह 91 प्रतिशत रेडिएशन से सुरक्षा देता है।

राज्यपाल से छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के अध्यक्ष ने की सौजन्य भेंट

रायपुर, 29 नवंबर 2023/ राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन से आज राजभवन में छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के अध्यक्ष श्री जुबिन शाह और श्री प्रभतेज भाटिया ने सौजन्य भेंट की साथ ही उन्होंने 1 दिसंबर 2023 को शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम नया रायपुर में भारत और ऑस्टेलिया के बीच होने वाले टी-20 क्रिकेट मैच के लिए राज्यपाल को आमंत्रित किया।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.